राष्ट्रीय संस्करण

कमाई और लोकप्रियता में विराट ने सलमान को पछाड़ा

>>16

वर्ष 3 अंक 192

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 दिसंबर 2019

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 16

नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा, तीन की मौत

अराजकता ▶ उप्र में उपद्रवियों ने दो पुलिस चौकियां व वाहन फूंकें, लखनऊ में एक की मौत, दो अन्य को लगी गोली

एडीजी, आइजी सहित करीब 70 पुलिसकर्मी घायल

जेएनएन, नई दिल्ली

देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में गुरुवार को कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। हिंसक प्रदर्शन के दौरान तीन की मौत हो गई। एक की उत्तर प्रदेश और दो की कर्नाटक के मंगलुरु में मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में माहौल काफी गर्मा गया। यहां विरोध के नाम पर तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाएं हुईं जिसमें कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। दिल्ली, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग सड़कों पर तो दिखे लेकिन बड़ी हिंसक घटनाएं नहीं हुईं।

उप्र में उपद्रवियों ने सरकारी संपत्तियों को बनाया निशाना : उप्र में समाजवादी पार्टी के आह्वान पर बुलाया गया विरोध प्रदर्शन दोपहर होते ही आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग में तब्दील हो गया। उपद्रवियों ने दर्जनों सरकारी और निजी वाहनों में आग लगाने के साथ ही दो पुलिस चौकी फूंक दी। हिंसा में हुसैनाबाद इलाके में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि दो युवक गोली लगने से घायल हो गए। मीडिया की ओबी वैन भी निशाना बनीं। पथराव में एडीजी, आइजी, एसपी ट्रैफिक सहित 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बेकाबू होता देख मेट्रो और परिवहन निगम की बसों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बाजार सहित तमाम सरकारी और निजी कार्यालय समय से पहले बंद करा दिए गए। विवि की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।

वहीं संभल में उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई जगह जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को तितर-बितर किया। रामपुर में सांसद आजम खां व अन्य सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्वांचल के वाराणसी, मऊ, भदोही और प्रयागराज में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

(विशेष सामग्री पेज-5 और 6 पर)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सीएए के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो गया। परिवर्तन चौक पर उपद्रवियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस पर पथराव किया। पंकज ओझा

दिल्ली–जयपुर हाईवे पर जाम में फंसे क्रू मेंबर, 25 उड़ानें रद

दिल्ली–जयपुर नेशनल हाईवे आठ पर जाम लग जाने के कारण विभिन्न विमानन कंपनियों के चालक दल (क्रू मेंबर) आइजीआइ एयरपोर्ट समय पर नहीं पहुंच पाए। जिसके चलते इंडिगो सहित अन्य एयरलाइंस को करीब 25 उड़ानें रद करनी पड़ीं। वहीं, 25 से ज्यादा का संचालन 20 मिनट से दो घंटे की देरी से हुआ। प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे आठ पर पुलिस दिल्ली जाने वाले वाहनों को जांच के बाद ही जाने दे रही थी। जिस कारण लंबा जाम लग गया। इंडिगो और एयर इंडिया सहित अन्य एयरलाइन ने प्रदर्शन की वजह से जाम में फंसे विमान यात्रियों के टिकट के पैसे लौटाने या उसे अन्य उड़ानों में समायोजित करने की घोषणा की है। हाल के दिनों में यह पहली बार हुआ है, जब दिल्ली में जाम की वजह से उड़ानों को रद करना पड़ा। एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने बताया कि एयरलाइंस की किसी भी उड़ान को रद नहीं किया गया है। सिर्फ आठ विमानों के उड़ान में देरी हुई।

दिल्ली में भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन

- 20 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया
- कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क रहे बंद

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी जमकर विरोध–प्रदर्शन हुआ। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग व छात्र–छात्राएं शामिल हुए। पुलिस की अनुमति के बिना लाल किला, मंडी हाउस और जंतर–मंतर पर सैकड़ों लोगों ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान एहतियातन 20 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए और विभिन्न इलाकों में मोबाइल इंटरनेट व एसएमएस सेवा भी बंद कर दी गई। धारा–144 के उल्लंघन में स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव, कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित व जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद सहित बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया। दूसरी ओर राजघाट पर बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों ने नए कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। मजनूं का टीला, आदर्श नगर, रोहिणी के कैंपों के ये शरणार्थी बच्चों के साथ राजघाट पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के समर्थन में नारेबाजी की। पिछले पांच दिनों से बंगाल के छह जिलों में बंद इंटरनेट सेवाओं को गुरुवार को कुछ क्षेत्रों में बहाल कर दिया गया।

गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी प्रदर्शन

गुजरात के अहमदाबाद शहर में हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 19 लोग घायल हो गए। वहीं 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां करीब 2,000 लोगों की भीड़ जमा हुई थी। कर्नाटक के मंगलुरु में भीड़ को तितर–बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। एजेंसी के मुताबिक, मंगलुरु में प्रदर्शन में घायल हुए दो लोगों की मौत हो गई है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। केरल में प्रदर्शनकारियों ने राजभवन का घेराव किया। हैदराबाद में भी पुलिस ने एहतियातन कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच, असम और मेघालय में स्थिति लगभग शांत है और जनजीवन सामान्य हो रहा है।

विरोध में कुछ फिल्मी कलाकार भी उतरे

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित रैली में शामिल अभिनेता फरहान अख्तर (बाएं) और अन्य लोग। प्रेट्र

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विभिन्न दलों के कार्यकर्ता, छात्र और बॉलीवुड की हस्तियों ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया। बॉलीवुड हस्तियों में फरहान अख्तर, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर, आनंद पटवर्धन, सुधींद्र कुलकर्णी ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

उपद्रवियों की संपत्ति नीलाम कर होगी नुकसान की भरपाई : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों की आग में गुरुवार को लखनऊ व संभल भी सुलग उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों जिलों में उपद्रवियों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा है कि सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति को नीलाम कराकर की जाएगी। योगी ने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कहा कि कांग्रेस, सपा व अन्य वामपंथी संगठन अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। योगी ने कहा कि उपद्रवियों से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। वह खुद पूरी कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं।

आइजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश में 110 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। जहां हिंसा की आशंका थी, वहां निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 3305 लोगों को हिरासत में लिया गया और कई व्यक्तियों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई थी। लखनऊ में 112 और संभल में 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अन्य उपद्रवियों को चिह्नित कराकर उनकी तलाश कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर भ्रामक व भड़काऊ पोस्ट/संदेश को लेकर विभिन्न जिलों में 13 मुकदमे दर्ज कर पांच आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। संभल में तीन रोडवेज बसों में आगजनी व तोड़फोड़ की गई। बसों में हुए पथराव से चार व्यक्ति घायल हुए। संभल में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लखनऊ में 12 वाहनों में आगजनी की गई। आइजी का दावा है कि लखनऊ व संभल के अलावा गुरुवार को अन्य सभी जिलों में शांति व्यवस्था रही। अन्य जिलों में भी संदेह के आधार पर कई अराजकतत्वों को हिरासत

योगी आदित्यनाथ फाइल फोटो

में लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने बुधवार तक प्रदेश में 126 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस के सामने आज और बड़ी चुनौती : पुलिस के सामने अब शुक्रवार को शांति-व्यवस्था बनाए रखने की और बड़ी चुनौती है। प्रदेश में धारा 144 लागू है और शुक्रवार को नमाज के बाद लोगों के एक स्थान पर जुटने की संभावना है। कई संगठनों ने 20 दिसंबर को भी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि हालात से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है। खुफिया तंत्र को और सक्रिय किया गया है। लखनऊ में शुक्रवार को 10 अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। सभी संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है और शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

सुनियोजित ढंग से किया गया उपद्रव : आइजी कानून-व्यवस्था का कहना है कि सोशल मीडिया की मानीटरिंग से सामने आ रहा है कि लखनऊ में अराजकतत्वों ने सुनियोजित ढंग से उपद्रव व हिंसा फैलाई। सोशल मीडिया के संदेशों व अन्य तथ्यों को देखा जा रहा है। अराजकतत्वों को चिह्नित कराया जा रहा है। 1786 ट्विटर, 3037 फेसबुक व 38 यूट्यूब पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

सरोकार

बिहार में रेत पर लिख रहे हरित क्रांति का नया अध्याय

संझौली (रोहतास) : बिहार में रोहतास जिले में काव नदी के तटीय इलाके में जहां कभी दिन में भी बंदूकें गरजती थीं, अब खुशहाली लौट आई है। लोग रेत पर हरित क्रांति का नया अध्याय लिख रहे हैं। किसानों के घर धन–धान्य से भरे तो बच्चे पढ़ लिख कर बड़े पदों पर पहुंच गए। (पेज–10)

जागरण विशेष

सब सुन रहे हैं कीर्ति के हौसले की 'कीर्ति'

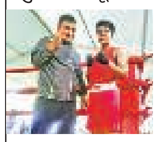

पानीपत : हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव निवासी कीर्ति बॉक्सर थीं, 2014 में पैर की एड़ी ट्रैक्टर से कुचल गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। खुद को रिंग के लिए तैयार कर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। (पेज–10)

न्यूज गैलरी

नेशनल कैपिटल ▶ पृष्ठ 2

निर्भया के दोषी पवन की अर्जी खारिज, वकील पर जुर्माना

नई दिल्ली : वर्ष 2012 में वारदात के समय नाबालिग होने का दावा करते हुए निर्भया मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने पवन के अधिवक्ता एपी सिंह के बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा, धनराशि निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था निर्मल छाया को दी जाए।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

ठंड का सितम, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री पर सिमटा

नई दिल्ली : पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए बदलाव ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ कंपकंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर जारी है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

उद्योग जगत की मांग, कारोबारी माहौल में हो सुधार

नई दिल्ली : उद्योगपतियों का कहना है कि घरेलू स्तर पर कारोबार के माहौल में सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। उद्योग जगत का मानना है कि सरकार को नीतिगत स्थिरता पर भी ध्यान देना होगा। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के कुछ नामी गिरामी उद्यमियों के साथ बजट पूर्व बैठक की थी जिसमें अलग–अलग स्तर पर इन बातों को रखा गया।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

जज ने लिखा, चौक पर तीन दिन टांगा जाए मुशर्रफ का शव

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में मौत की सजा सुनाने वाले न्यायाधीशों ने 167 पेज के अपने फैसले में दोषी के खिलाफ तल्ख बात कही है। फैसले में लिखा है कि अगर सजा दिए जाने से पहले ही पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ की मौत हो जाती है तो उनके शव को विदेश से पाकिस्तान लाया जाए और राजधानी इस्लामाबाद के डी–चौक पर तीन दिन तक फंदे से लटकाकर रखा जाए।

नड्डा बोले, सीएए लागू किया जाएगा, एनआरसी भी लाएंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इस कानून को लागू किया जाएगा और सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भी लाएगी। गुरुवार को अफगानिस्तान से आए सिख शरणार्थियों के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने यह बात कही। इन शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता कानून से भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उन्होंने कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना की।

नड्डा ने कहा कि भाजपा की विरोधी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के तहत इस कानून का विरोध कर रही हैं। भारत में रह रहे तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की दुर्दशा की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्हें उनसे मिलना चाहिए। ये लोग 28-30 सालों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन वे अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं करा सकते या मकान नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं है। हमारे विरोधी वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं देख सकते।

- भाजपा नेता ने विपक्ष पर लगाया वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप
- कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मानवीय आधार पर लिया है फैसला

नई दिल्ली में गुरुवार को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा (मध्य में) को अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने पारंपरिक अफगानी पगड़ी बांधी और सीएए बनाने के लिए आभार जताया। एएनआइ

नड्डा ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और यह सिलसिला जारी रहेगा। नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा और भविष्य में हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी लाएंगे।

सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा मुख्यालय में नड्डा से मिला और नागरिकता कानून में बदलाव के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया। नड्डा ने कहा कि इन सिखों ने लगभग तीन दशक पहले अफगानिस्तान छोड़ दिया था और अपना धर्म बचाने के लिए भारत चले आए। भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें नागरिकता देने के लिए कागजी कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी, ताकि वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें। कांग्रेस, तृणमूल और वाम दलों समेत अन्य पार्टियों द्वारा विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला दिया कि वे लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मानवीय आधार पर यह फैसला लिया है और यह देशहित में है।

संरा की निगरानी में जनमत संग्रह करवाया जाए : ममता पेज>>5

ट्रंप के खिलाफ चलेगा महाभियोग

वाशिंगटन, प्रेट्र : विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (73) के खिलाफ महाभियोग पर मुहर लगा दी है। वह अमेरिकी इतिहास में ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके खिलाफ महाभियोग को मंजूरी दी गई। ट्रंप के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग और संसद की कार्यवाही में रोड़ा अटकाने के आरोप तय किए गए हैं। अब महाभियोग की सुनवाई अगले वर्ष संसद के ऊपरी सदन सीनेट में होगी। रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले इसी सदन में यह तय होगा कि ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे या नहीं।

प्रतिनिध सभा में ट्रंप के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग का आरोप 197 के मुकाबले 230 जबकि संसद की कार्यवाही में रोड़ा अटकाने के आरोप 229-198 मतों से पारित किया गया। इस प्रस्ताव को अब सीनेट में पेश किया जाएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। सीनेट में बहुमत के नेता मिच मैककोनेल ने कहा, वह महाभियोग की सुनवाई अगले साल की शुरुआत में करेंगे। वहीं, प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, 'अगर अब हम कुछ नहीं करते तो यही लगता कि हमने कर्तव्यों को त्याग दिया है। यह दुखद है कि राष्ट्रपति के गैरजिम्मेदाराना कृत्यों ने महाभियोग को आवश्यक बना दिया।'

- अमेरिकी इतिहास के तीसरे राष्ट्रपति जिन पर चलेगा महाभियोग
- विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने पारित किया प्रस्ताव
- सत्ता के दुरुपयोग और कार्यवाही में रोड़ा अटकाने के तय किए आरोप

अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में महाभियोग पर मुहर लगने के बाद मिशिगन में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

वे पहले दिन से ही मुझ पर महाभियोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तीन साल के दौरान अफवाहें फैलाने और अंधेरे में तीर चलाने के बाद अब डेमोक्रेट्स लाखों देशभक्त अमेरिकियों के वोट का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं।

–डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति

ह्वाइट हाउस ने शर्मनाक बताया

राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस ने महाभियोग को अमेरिकी इतिहास में सबसे शर्मनाक सियासी प्रसंग करार दिया। साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ भी गलत नहीं किया है।

इस मामले में चला महाभियोग

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने गत 25 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। इसमें उन्होंने जेलेंस्की पर अगले साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने संभावित डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन को बदनाम करने के लिए दबाव बनाया था।

महाभियोग का इतिहास

- 243 साल के अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिये कुर्सी नहीं गंवानी पड़ी
- 1868 में एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ महाभियोग चला था, पर वह सीनेट से बरी हो गए थे
- 1998 में बिल क्लिंटन पर महाभियोग चला था, लेकिन वह भी सीनेट में बच गए थे
- 1974 में रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग पर मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया था

महाभियोग के पक्ष में भारतवंशी सांसदों ने दिया मत पेज>>13

इतिहास का पन्ना

कांग्रेस नेता ने 2003 में कहा था–बांग्लादेश से पीड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलनी चाहिए, असहज कांग्रेस का जवाब–नोटिफिकेशन के जरिये दी जा सकती है नागरिकता

भाजपा ने जारी किया वीडियो, मनमोहन ने की थी सीएए जैसे कानून की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता कानून का सड़क से लेकर कोर्ट और राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक विरोध कर रही कांग्रेस को इतिहास का पन्ना दिखाते हुए भाजपा ने असहज कर दिया है। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का वह वीडियो सार्वजनिक किया है जिसमें नेता विपक्ष रहते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें ज्यादा उदार होना चाहिए। खास बात यह है कि यह मांग उन्होंने संसद (राज्यसभा में) के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में की थी, लेकिन अब कांग्रेस ने न केवल सदन में इसका विरोध किया है, बल्कि वह इस मसले पर अन्य विरोधी दलों को भी सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रही है।

कभी समर्थन-कभी विरोध में उलझी कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का अब कहना है कि ऐसा कुछ किया जाना था तो अधिसूचना

राज्यसभा में बोलते हुए तत्कालीन नेता विपक्ष मनमोहन सिंह। वीडियो ग्रैब

के जरिए किया जाना चाहिए था, कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने सीधे शब्दों में कहा कि 'कांग्रेस मुंह छिपा रही है।'

नागरिकता कानून को लेकर सरकार की तरफ से बार-बार साफ किया जा रहा है कि यह किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। जो भी भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता पर कोई अंगुली नहीं उठ रही है, लेकिन कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों को इस पर भरोसा नहीं है। वैसे तो 12 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा के दौरान ही भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को 2003 में मनमोहन सिंह की मांग याद दिलाई थी, लेकिन गुरुवार को भाजपा ने उस वीडियो को ट्वीट भी किया। वीडियो में मनमोहन सिंह कह रहे हैं-'मैं शरणार्थियों की स्थिति पर सवाल कर रहा हूं तो यह भी कहना चाहता हूं कि देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के बारे में बहुत ज्यादा उदार होना चाहिए। यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है।' मौजूदा समय नागरिकता संशोधन कानून को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर आघात और संविधान के विपरीत बता रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने तब सामने बैठे तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उम्मीद है, वह (आडवाणी) इस पर विचार करेंगे। ध्यान रहे कि उस वक्त नागरिकता संशोधन पर ही चर्चा हो रही थी।

वीडियो सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस के सिंघवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा-'क्या 1971 और देश के बंटवारे के समय की आज से तुलना हो सकती है। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था, लेकिन क्या कभी इसके लिए किसी भी सरकार ने कानून बनाया? कुछ लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए नागरिकता दी जा सकती है, जैसे युगांडा के 50 लोगों को नागरिकता दी गई थी, लेकिन इस तरह तीन देशों में कुछ धर्मों का नाम लेकर कानून बनाना उचित नहीं है। हम उसका विरोध कर रहे हैं।'

भाजपा की ओर से भूपेंद्र यादव ने भी तत्काल पलटवार किया। उन्होंने कहा- 'कांग्रेस अब मुंह छिपा रही है। विरोध करने के लिए मनमोहन सिंह को झुठला रही है। शरणार्थियों और नागरिकों को लेकर नीति तय करना उचित दिशा में कदम है। यह हर देश करता है। कांग्रेस का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है।' उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के काल में गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तान से आए ऐसे हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए गजट जारी हुआ था।

करात ने भी शरणार्थियों को नागरिकता देने की वकालत की थी : बताते हैं कि संप्रग काल के दौरान ही तत्कालीन माकपा महासचिव प्रकाश करात ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उनके बयान की याद दिलाई थी और बांग्लादेश से पीड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता की बात की थी। हालांकि, माकपा पोलित ब्यूरो ने इसका खंडन किया है और कहा है कि वामदलों की ओर से संसद में भी यह संशोधन लाया गया था कि नागरिकता के लिए धर्म को आधार न बनाया जाए, लेकिन भाजपा ने उसे खारिज कर दिया था।

(अगर मनमोहन सिंह का वह वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस लिंक पर जाएं : **http://www.jagran.com/politics/national-did-you-know-manmohan-demanded-caa-in-2003-bjp-release-video-19858671.html**)

अश्लील मैसेज भेजने पर सेना के एडीजी सुभाष शरण कार्यमुक्त

लखनऊ : एनसीसी बालिका कैडेटों को अश्लील वीडियो भेजने के मामले में आखिरकार मेजर जनरल डॉ. सुभाष शरण को पद गंवाना पड़ गया। कोर्ट मार्शल से पहले ही सेना भर्ती मुख्यालय यूपी व उत्तराखंड के एडीजी शरण को कार्यमुक्त कर दिया गया है। सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के आदेश के बाद एडीजी की सेवा से जुड़ी सारी सुविधाएं रोक दी गई हैं। (पेज–6)

आइपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने पैट कमिंस

कोलकाता : ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर पैट कमिंस आइपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। गुरुवार को यहां आइपीएल के 13वें सत्र के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में कोलकाता नाइटराइडर्स ने 26 साल के कमिंस को 15.5 करोड़ रुपये की भारी–भरकम रकम चुकाकर अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के नाम था, जिसे 2017 में हुई नीलामी में तत्कालीन टीम राइजिंग पुणे सुपरजाइंट ने 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। (पेज–14)

967 छात्रों को प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं आइआइटी दिल्ली में। पहले चरण की प्लेसमेंट प्रक्रिया में इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले 10 फीसद ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 20 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

कुलपति ने दिए वैकल्पिक माध्यम से परीक्षा के निर्देश

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन की तरफ से गुरुवार को परिपत्र जारी करते हुए छात्रों को जानकारी दी है कि वैकल्पिक माध्यम से सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संस्थान में मौजूदा समय में छात्रों द्वारा छात्रावास की फीस वृद्धि को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार इन प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा स्कूलों को बंद किया गया है। इसके कारण इनमें सेमेस्टर परीक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के पीएचडी छात्र एवं वामपंथी छात्र संगठन आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साईं बालाजी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई स्कूलों के डीन की तरफ से ईमेल के जरिये सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्नपत्र भेजा जा रहा है। छात्रों से ईमेल के जरिये भेजे गए प्रश्नपत्र के जवाब को वॉट्सएप के जरिये मांगा जा रहा है। यह व्यवस्था गलत है। (जासं)

केजरीवाल व पीके लांच करेंगे आप का पहला चुनावी कैंपेन

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी कैंपेन की कमान संभालने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) ने काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत शुक्रवार को प्रशांत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई में आप का पहला चुनावी कैंपेन लांच किया जाएगा। इसे 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को काउंटर करने की योजना के रूप में भी देखा जा रहा है। मोदी की रैली से ठीक पहले आप का चुनावी कैंपेन शुरू करके प्रशांत किशोर दिल्ली विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की तैयारी में हैं। इस बार आप नए नारे और नई टैगलाइन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनाव फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। इसके लिए अधिसूचना जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है। (जासं)

90 कैप्सूल में 880 ग्राम ड्रग निगलकर पहुंचा यात्री पकड़ा

नई दिल्ली : ब्राजील से 90 कैप्सूल में 880 ग्राम ड्रग निगलकर दिल्ली पहुंचे एक यात्री को आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा है। उसके पेट में ड्रग होने की पुष्टि होने पर कोर्ट के आदेश के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाकर उसके पेट से ड्रग वाले 90 कैप्सूल निकाले गए। आरोपित वेनेजुएला का नागरिक है। कस्टम के मुताबिक जांच अधिकारियों ने एक संदिग्ध की पहचान कैप्सूल में ड्रग निकलकर तस्करी करने में माहिर तस्कर के रूप में की। शक के आधार पर उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की। (जासं)

वायु प्रदूषण से निपटने में स्मॉग टॉवर प्रभावी नहीं : अमेरिकी विशेषज्ञ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता की भी बताई कमी
- करोड़ों रुपये इस पर खर्च करने के बजाय किसानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने की बताई जरूरत
- कहा, शहरी क्षेत्रों के अलावा कोई भी सतर्क नहीं

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग टॉवर लगाने जैसे विकल्पों को अजमाने की तैयारियां भले ही जोरों पर है, लेकिन हवा की गुणवत्ता पर काम करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ प्रकाश दोराईस्वामी इसे प्रभावी नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ना तो यह वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान है और ना ही इससे यह खत्म होने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि इसके पैदा होने वाले स्रोतों को खत्म किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे लगाने पर जो करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे, उसकी जगह किसानों को तकनीकी मदद मुहैया कराने में मदद दी जानी चाहिए, ताकि वह फसलों के अवशेष को न जलाएं। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे लोग निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें।

वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर काम करने वाली अमेरिका की प्रतिष्ठित एजेंसी आरटीआइ इंटरनेशनल के प्रमुख वैज्ञानिक (वायु गुणवत्ता) दोराईस्वामी गुरुवार को दिल्ली में थे।

'जागरण' से विशेष बातचीत में दोराईस्वामी ने बताया कि वायु प्रदूषण को लेकर उन्होंने हाल ही में दिल्ली, चंडीगढ़ सहित देश के कई शहरों में कार्यशालाएं आयोजित की थीं, जिनमें सरकारी एजेंसियों के साथ स्थानीय प्रशासन, तकनीकी संस्थान और प्रदूषण को लेकर काम करने वाली अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान प्रदूषण के जो तीन बड़े कारण सामने आए, उनमें पहला- निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, दूसरा- फसलों के अवशेष को जलाया जाना और तीसरा- वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्तर में सही मायनों में कमी लाना है तो इन्हीं तीन मुख्य बिंदुओं को लेकर जमीनी स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने इसे लेकर कुछ उपाय भी बताए हैं। साथ ही कहा कि वह इससे जुड़े सभी सुझाव भारत और अमेरिका की सरकारों को भी सौंपेंगे। साथ ही उम्मीद जताई कि इससे जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट जनवरी के अंत तक दे देंगे।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सरकार इसे लेकर अपने स्तर पर सभी प्रभावी कदम उठा रही है। उनके पास इससे निपटने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम है। लेकिन इसमें सफलता तभी मिलेगी, जब जमीनी स्तर पर काम होगा। फिलहाल अभी इसमें कमी है।

स्मॉग टॉवर को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह ठीक एयर प्यूरीफायर जैसा ही है जो बंद कमरे की हवा को साफ रखने में मदद करता है। लेकिन यह तभी तक ठीक से काम करता है, जब तक घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। यदि दरवाजे और खिड़कियां खुली रहेंगी, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को खत्म किया जाए, ताकि प्रदूषण पैदा ही न हो।

गौरतलब है कि यह एजेंसी मौजूदा समय में भारत में नॉर्थ अमेरिकन सेंटर के साथ मिलकर वायु प्रदूषण से निपटने में सरकार को नीतिगत मदद दे रही है। इससे पहले वर्ष 2016-17 में भी इस एजेंसी ने भारत में वायु प्रदूषण को लेकर अपनी एक रिपोर्ट दी थी। बाद में उसके कई सुझावों को सरकार ने अपने प्लान में दी जगह दी थी।

बढ़ा प्रदूषण, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर इंडेक्स

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बादल छाए रहने और हवा की गति भी मंद होने के कारण गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर और बढ़कर खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 362 दर्ज किया, जो किबहुत खराब श्रेणी का रहा। मौसमी परिस्थितियों में सुधार न होने पर शुक्रवार को भी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम ही है। एनसीआर के कुछ जगहों पर एयर इंडेक्स 400 का आंकड़ा पार कर गंभीर श्रेणी में भी पहुंच सकता है।

दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स	
दिल्ली	362
गाजियाबाद	391
फरीदाबाद	375
ग्रेटर नोएडा	351
नोएडा	378
गुरुग्राम	298

सोमवार से दो जगह शुरू होगा पार्किंग का ट्रायल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : लंबे समय से चली रही कवायद के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोमवार से दो जगहों पर पार्किंग प्लान का ट्रायल शुरू हो जाएगा। यह ट्रायल कमला नगर और कृष्णा नगर मार्केट में दो सप्ताह तक चलाया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) की टीम खुद वहां का निरीक्षण करेगी और ट्रायल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी।

यह फैसला इंडिया हेबीटेट सेंटर स्थित ईपीसीए कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में उपस्थित रहे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इस दिशा में निर्देश दे दिए गए हैं। लाजपत नगर में भी यह ट्रायल इसी हफ्ते शुरू कर दिया जाएगा। यदि यह तीनों पायलट प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो फिर इसी मॉडल पर पूरी दिल्ली के लिए पार्किंग प्लान तैयार कर उसे लागू किया जाएगा। ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल के मुताबिक दोनों जगहों पर संबंधित नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को अपनी-अपनी सड़कों पर मिलकर यह काम शुरू करने को कहा गया है।

राजधानी में फ्री वाई-फाई सेवा शुरू

एक और तोहफा ▸ केजरीवाल ने आइटीओ बस स्टॉप से योजना का किया शुभारंभ

अगले छह माह में पूरी दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को फ्री वाई-फाई दिल्ली का सपना साकार किया। उन्होंने आइटीओ बस स्टॉप से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत दिल्ली भर में 109 हॉट स्पॉट शुरू किए गए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली दुनिया में पहला ऐसा शहर बन गया, जहां सरकार की तरफ से पूरे शहर के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जा रही है। अब प्रति सप्ताह 500 हॉट स्पॉट लगेंगे। उन्होंने हॉट स्पॉट के जरिये ही दिल्ली विश्वविद्यालय में इस योजना का शुभारंभ कर रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात की। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को भी इस योजना के शुरू होने पर बधाई दी।

केजरीवाल ने कहा कि अगले छह माह में पूरी दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। इससे प्रति 500 मीटर पर लोग फ्री वाई फाई की सुविधा ले सकेंगे। इससे 22 लाख लोग एक साथ इंटरनेट सर्फ कर सकेंगे। एक उपभोक्ता को प्रतिमाह 15 जीबी डाटा मुफ्त मिलेगा। इस योजना पर कुल 99,50,38,560 रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले हॉट स्पॉट की कार्यप्रणाली पर पूरी नजर रखेंगे। देखेंगे कि यह कैसा काम कर रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में शेष दिल्ली में भी हॉट स्पॉट लगा देंगे।

80 मीटर के दायरे में करेंगे काम : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी के चार हजार बस स्टॉप के ऊपर और सात हजार अन्य जगहों पर हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। इनमें आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन व अन्य स्थान भी शामिल है। सभी हॉट स्पॉट 80 मीटर के दायरे में काम करेंगे। 6100 हॉट स्पॉट 200 एमबीपीएस के होंगे और 5900 हॉट स्पॉट 50 एमबीपीएस स्पीड के होंगे।

रेंज बदलने पर भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा इंटरनेट : मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हॉट स्पॉट पर 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक एप बनाया गया है। इसके जरिये उपभोक्ता को अपनी केवाइसी की डिटेल भरनी होगी। केवाइसी भरने के बाद यूजर के फोन में ओटीपी आएगा। वह ओटीपी डालने के बाद इंटरनेट का कनेक्शन चालू हो जाएगा। यदि आप एक सप्ताह तक अपने हॉट स्पॉट के जोन से निकलकर दूसरे के जोन में जाते हैं, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा बल्कि वह दूसरे हॉट स्पॉट की रेंज में जाकर ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएगा।

सीसीटीवी को भी हॉट स्पॉट से जोड़ा जाएगा : दिल्ली में लगे सीसीटीवी को फ्री वाई फाई सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली को और सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2015 में सरकार में आते ही हॉट स्पॉट पर काम शुरू हो गया था। रेस्टो कंपनी को वाई फाई का अनुबंध दिया गया है। दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों एवं वाई-फाई का मेंटेनेंस दिल्ली सरकार करेगी।

आइटीओ स्थित बस स्टॉप से फ्री वाई-फाई योजना के शुभारंभ के अवसर पर बोलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (बाएं)। जागरण

केंद्र सरकार पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फ्री वाई-फाई योजना की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ही के दिन दिल्ली में अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के निर्देश के बाद टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट, वायस और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी थीं। इसके चलते कई घंटों तक लोगों को फोन और इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने में परेशानी हुई।

इन जगहों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा शुरू

- कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
- कश्मीरी गेट आइएसबीटी
- आइटीओ बस स्टैंड
- मंडी हाउस बस स्टैंड
- दिल्ली सचिवालय
- इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन
- दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड
- सराय काले खां बस स्टैंड

संपत्तियों के विकास से नहीं बढ़ पा रही मेट्रो की कमाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- यात्रियों के किराये पर ही निर्भर डीएमआरसी
- मेट्रो का घाटा बढ़ा, वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई बात

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को संपत्तियों के विकास (प्रोपर्टी डेवलपमेंट) और आय के अन्य विकल्प तलाशने की बात कह चुका है। लेकिन व्यावसायिक संपत्तियों के विकास में डीएमआरसी को खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इस वजह से संपत्तियों के विकास से मेट्रो की कमाई अधिक नहीं बढ़ पा रही है। यात्रियों के किराये पर भी डीएमआरसी की निर्भरता बनी हुई है। हालांकि परिचालन की कमाई के लिहाज से मेट्रो फायदे में है, लेकिन लोन व हर तरह की देनदारी चुकाने के बाद डीएमआरसी का घाटा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। डीएमआरसी की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में डीएमआरसी को विभिन्न स्रोतों से कुल छह हजार 461 करोड़ 52 लाख राजस्व मिला। कुल खर्च चार हजार 498 करोड़ 77 लाख रहा। इस तरह मेट्रो को एक हजार 962 करोड़ 75 लाख फायदा हुआ, लेकिन वित्तीय समायोजन के बाद डीएमआरसी ने 462.23 करोड़ का घाटा दिखाया है। इसके पिछले वित्त वर्ष में घाटा महज 93.14 करोड़ था। इसका एक कारण तो यह है कि वर्ष 2017 में दोगुना किराया वृद्धि के बाद परिचालन से मेट्रो की कमाई 38.39 फीसद तक बढ़ गई थी। वर्ष 2018-19 में मेट्रो का नेटवर्क 251.68 किलोमीटर से बढ़कर 343.63 किलोमीटर हो गया। इसके बावजूद परिचालन से मेट्रो की कमाई में 18.35 फीसद ही बढ़ोतरी हो पाई। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि फेज तीन के सभी कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होने के बाद भी मेट्रो में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीएमआरसी ने इस बार वार्षिक रिपोर्ट में भी मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। मेट्रो नेटवर्क के मुकाबले यात्रियों की संख्या कम बढ़ने के कारण परिचालन से राजस्व में 555.54 करोड़ की बढ़ोतरी हो पाई। इस तरह डीएमआरसी ने परिचालन से तीन हजार 582 करोड़ 80 लाख कमाई की। जबकि संपत्ति विकास से महज 97.28 करोड़ राजस्व मिला। किराये के बाद डीएमआरसी को सबसे ज्यादा राजस्व दूसरे शहरों की मेट्रो परियोजनाओं में कंसल्टेंसी सेवा के रूप में मिलता है।

उल्लेखनीय है कि कई नए स्टेशनों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित करने की योजना है ताकि मेट्रो का राजस्व बढ़ सके। डीएमआरसी ने जनकपुरी में आवासीय परिसर विकसित करने की योजना भी बनाई थी। इस योजना के तहत डीएमआरसी ने फ्लैट बनाकर विक्री करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा व्यावसायिक संपत्ति विकास की कई योजनाएं हैं, जो परवान नहीं चढ़ पा रही हैं।

'दिल्ली में हिंसा के लिए भाजपा व आप जिम्मेदार'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार एवं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने का घिनौना प्रयास किया है। इससे आज दिल्ली की जनता न केवल आहत है, बल्कि अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रही है।

चोपड़ा गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में ब्लॉक व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की सभा में बोल रहे थे। बैठक को चोपड़ा के अलावा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद, मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा और राजेश लिलोठिया ने भी संबोधित किया। चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, दिल्ली की आम जनता भयभीत है और लोग अपने दफ्तर से न घर पहुंच पा रहे हैं और न ही रोजमर्रा के काम कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद होने, जगह जगह ट्रैफिक जाम होने व धारा 144 लगने से अफरातफरी का माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के इन हालातों के लिए भाजपा व आप ही पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे दिल्ली में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करें, साथ ही पीड़ित लोगों की मदद भी करें।

कीर्ति आजाद ने कहा कि सरकार में बैठे लोग ही जब हिंसा कराएंगे व कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो देश और दिल्ली का शासन कैसे चलेगा, यह समझ से परे है। उन्होंने दिल्ली में घटी घटनाओं गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा करते हुए सभी गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग भी की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा द्वारा रखे गए एक प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया। इस प्रस्ताव में राजधानी में जनजीवन को अस्तव्यस्त करने और दिल्ली को हिंसा के हवाले करने के लिए जिम्मेदार भाजपा व आप की निंदा की गई।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जिला कमेटी और ब्लाक अध्यक्षों के साथ हुई बैठक को संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा। सौजन्य : कांग्रेस

125 डिपार्टमेंटल स्टोरों पर आज से नहीं मिलेगी शराब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के 125 डिपार्टमेंटल स्टोरों पर शुक्रवार से शराब की ब्रिकी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने के आरोप में आबकारी विभाग ने इन स्टोरों का एल-12 और एल-12 एफ लाइसेंस निरस्त कर दिया, जो शराब की बिक्री के लिए आवश्यक होता है। विभाग की छापेमारी के बाद दिल्ली सरकार ने यहां शराब की बिक्री बंद करने का बड़ा फैसला किया है।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दो-तीन महीने पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ दिल्लीभर में 125 डिपार्टमेंटल स्टोरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान यहां तय मात्रा से ज्यादा शराब मिली थी जबकि एल-12 और एल-12 एफ लाइसेंस के अनुसार डिपार्टमेंटल स्टोर के कुल उत्पादों में शराब की मात्रा 12 फीसद से अधिक नहीं हो चाहिए। छापेमारी के दौरान इन डिपार्टमेंटल स्टोरों पर 50 से लेकर 90 फीसद मात्रा में शराब मिली थी। इसके चलते 40 स्टोरों को उसी समय सील कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद विभाग ने इनकी सील खोल दी थी। शुक्रवार से शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर गई है।

निर्भया के दोषी पवन की याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- हाई कोर्ट ने वकील पर 25 हजार का जुर्माना लगाया
- दोषी पवन ने अपराध के समय खुद को बताया था नाबालिग

वर्ष 2012 में वारदात के समय नाबालिग होने का दावा करते हुए निर्भया मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने पवन के अधिवक्ता एपी सिंह के बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया। पीठ ने कहा कि उक्त धनराशि निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था निर्मल छाया के पक्ष में एक सप्ताह के अंदर भुगतान की जाए। पीठ ने पवन की आयु से जुड़ा फर्जी शपथपत्र दाखिल करने पर दिल्ली बार काउंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इस मामले में पवन के अलावा विनय, मुकेश और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि पवन कुमार ने नाबालिग होने का दावा इससे पहले पुनर्विचार याचिका में भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। गुरुवार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर एपी सिंह पीठ के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दूसरे पक्ष के संबंध में जानकारी दिए बगैर ही अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की बात करते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की। इस पर पीठ ने सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित भी कर दी। कुछ ही देर बाद पीड़िता की मां की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय लाऊ, अधिवक्ता जितेंद्र झा एवं अधिवक्ता सीमा सिद्धार्थ ने पीठ को जानकारी दी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जा चुका है और इस याचिका का कोई आधार नहीं है।

याचिका सिर्फ दोषियों की फांसी की सजा को टालने के उद्देश्य से लगाई गई है। पीड़िता के परिजन भी अदालत में मौजूद थे। इसके बाद पीठ ने अधिवक्ता एपी सिंह को अपने कर्मचारियों के माध्यम से फोन, एसएमएस और ईमेल के जरिये दोपहर बाद सुनवाई होने के संबंध में जानकारी भेजी। लेकिन एपी सिंह ने अदालत में आने की जहमत नहीं उठाई। ढाई बजे जब अदालत दोबारा बैठी और सुनवाई शुरू हुई तो पीठ ने इसे अपने फैसले में दर्ज किया।

पीड़िता की मां ने किया स्वागत : निर्भया की मां ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि अदालत ने अपना काम किया और मैं इस फैसले से संतुष्ट हूं। दोषी और उसके अधिवक्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया। जुर्माना लगाकर अदालत ने मामलों को लटकाने वालों को सख्त संदेश दिया है।

आयु के संबंध में दी गलत जानकारी

पवन कुमार ने याचिका में दावा किया कि स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार उसका जन्म 8 अक्टूबर 1996 को हुआ था और घटना के दौरान वह नाबालिग था। ऐसे में उसे नाबालिग होने का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि पुलिस की जांच और सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार उसके पिता ने बताया था कि पवन का जन्म 17 जुलाई, 1992 को हुआ था। इससे 16 दिसंबर, 2012 को हुई वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म की घटना के दौरान वह 18 साल का था।

यह कहा याचिका में

याचिका में दोषी पवन कुमार ने आरोप लगाया कि उम्र की जांच के लिए अधिकारियों ने उसकी हड्डी का परीक्षण नहीं किया था। घटना के समय नाबालिग होने के कारण वह जेजे एक्ट की धारा 7ए के तहत किसी भी अदालत के समक्ष जा सकता है। अंतिम फैसला होने के बावजूद किसी भी स्तर पर इसकी पहचान कराई जा सकती है।

योजना

हर फायर स्टेशन को अलग से स्टॉफ देकर जांच के लिए अलग विंग बनाने का है प्रस्ताव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में आग से सुरक्षा व्यवस्था हो सकेगी मजबूत

आग बुझाने व जांचने की टीमें होंगी अलग-अलग

रजनीकान्त मिश्र, नोएडा

दिल्ली के अनाज मंडी क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में 43 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश फायर सर्विस आग से सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरत रहा है। पुरानी औद्योगिक इकाइयों की जांच से लेकर नई बिल्डिंग की जांच के लिए फायर स्टेशन में अलग से विंग बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अग्निशमन विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया गया है। फायर स्टेशनों में बनने वाली विंग पुरानी बिल्डिंग की जांच के अलावा अन्य बिल्डिंग की एनओसी जारी करने से पहले निरीक्षण करेगी। उसके बाद ही उन बिल्डिंग की एनओसी जारी होगी। इस प्रकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की तरफ से मेरठ परिक्षेत्र के उप निदेशक अमन शर्मा की टीम ने तैयार किया है।

यह प्रस्ताव अग्निशमन मुख्यालय लखनऊ भेजा जाएगा। प्रयास है कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कराया जाए। मुख्यालय से अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो खास कर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर व लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।

आग बुझाने के साथ जांच में आ रही है मुश्किलें : खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 15 हजार औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। फायर स्टेशनों में पहले से ही फायर मैन सहित अन्य स्टॉफ की भारी कमी है और काम का दबाव भी रहता है। ऐसे में फायर फाइटिंग के साथ इन सभी औद्योगिक इकाइयों की प्रति वर्ष जांच करना अग्निशमन विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है। अग्निशमन विभाग की तरफ से तैयार हो रहे प्रस्ताव पर मंजूरी मिलती है और इस अलग विंग का गठन होता है तो सबसे अधिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ गाजियाबाद को फायदा मिलेगा। इन शहरों में औद्योगिक इकाइयों के साथ बहुमंजिला इमारत, कामर्शियल बिल्डिंग व बाजारों की आग से सुरक्षा व्यवस्था की आसानी से निगरानी हो सकेगी।

आग बुझाने के साथ सभी बिल्डिंग की जांच करना फायर स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसके लिए हर फायर स्टेशन पर एक अलग विंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे मुख्यालय को भेजा जाएगा। इसके लिए अलग से फोर्स की भी मांग की जा रही है।

-अमन शर्मा, उप निदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, मेरठ परिक्षेत्र

जामिया हमदर्द को मिले नए कुलाधिपति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जामिया हमदर्द संस्थान (डिम्ड विश्वविद्यालय) में सैयद शाहिद मेहदी को नया कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। उन्होंने निवर्तमान कुलाधिपति डॉ हाबेल खुराकीवाला का स्थान ग्रहण किया है। वह संस्थान के चौथे कुलाधिपति बने हैं।

मेहदी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के एल्युमिनी हैं। उन्होंने एएमयू से हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस में एमए की। इसके बाद वर्ष 1963 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में देश भर में इस बैच में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बतौर आइएएस, उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार में भी कई पद संभालें। इससे पहले वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति का पद भी वर्ष 2000 से 2004 के दौरान संभाल चुके हैं। इटली की राजधानी रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन में भारत सरकार की ओर से वैकल्पिक स्थायी प्रतिनिधि के पद पर भी रह चुके हैं।

'विजय गोयल ने दिल्ली की जनता का अपमान किया'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- संजय सिंह बोले, अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगें भाजपा सांसद

भाजपा सांसद विजय गोयल द्वारा दिल्ली की जनता पर की गई टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आप का कहना है कि विजय गोयल द्वारा यह कहना कि दिल्ली की जनता मुफ्त की चीजों के बदले में अपना वोट बेचती है, सीधे तौर पर दिल्लीवासियां का अपमान करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने गोयल से दिल्ली के निवासियों से माफी मांगने की भी मांग की है। उनका कहना है कि गोयल के बयान से साफ हो जाता है कि दिल्ली में भाजपा सरकार आने पर जनता को मिल रही सभी मुफ्त सुविधाओं को खत्म कर दिया जाएगा।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार का यह फर्ज होता है कि वह अपने राज्य की जनता को मूलभूत जरूरतों की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए और अगर केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा अपने हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो इसके लिए केजरीवाल को लक्ष्य करना ठीक बात नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि यह बेहद ही गंभीर स्थिति है और चिंता का विषय है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि विरोध करना हर भारतीय नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका एक सभ्य तरीका है।

14 दिन की हिरासत मांगी है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटियाला हाउस कोर्ट से कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की मनी लांड्रिंग के एक मामले में, विशेष न्यायाधीश अनुराग सैन की अदालत ने तलवार के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया और तिहाड़ जेल प्रशासन को 20 दिसंबर को उसे पेश करने का निर्देश दिया है।

अमेरिका ने भारत के सामने उठाया अनुच्छेद 370 व सीएए का मुद्दा

अमेरिकी विदेश मंत्री पोंपिओ ने विदेश मंत्री जयशंकर के समक्ष जताई चिंता, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा भी जताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिकी सरकार ने पहली बार कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का मुद्दा भारत के समक्ष उठाया है। साथ ही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा भी जताया है। खास तौर पर जिस तरह से सीएए को लेकर समाज में चर्चा हो रही है और इस पर कोर्ट में विचार किया जा रहा है, उसे लेकर संतोष जताया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में इन प्रक्रियाओं का वह आदर करता है। वैसे भारत ने साफ किया कि गुरुवार को वाशिंगटन में हुई 'टू प्लस टू' वार्ता में इन मुद्दों को नहीं उठाया गया।

भारत-अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में अमेरिकी प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'विदेश मंत्री माइक पोंपिओ ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों व धार्मिक आजादी की सुरक्षा के मुद्दे को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा है। यह हमारी कूटनीति का अहम हिस्सा है। हमारे विभाग व मंत्री की नीति में भी इसका खास स्थान है, लेकिन मंत्री इस बात को भी मानते हैं कि भारत मजबूत लोकतांत्रिक देश है। सीएए के बारे में भारत में काफी व्यापक तौर पर चर्चा हो रही है। कोर्ट भी उसकी समीक्षा करेगा। राजनीतिक दलों की तरफ से उसका विरोध किया जा रहा है। मीडिया में भी चर्चा हो रही है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हो रहा है और हम उसका आदर करते हैं।' अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, सीएए की समीक्षा भारतीय व्यवस्था के दायरे में ही होना चाहिए।

अमेरिकी विदेशी विभाग की तरफ से पहली बार इस तरह की प्रक्रिया आई है। इसके पहले अमेरिकी प्रशासन के एक अन्य विभाग जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है, ने सीएए को लेकर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। अमेरिका ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद की स्थिति और अभी तक कई राजनेताओं के हिरासत में होने का मुद्दा भी उठाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से ही भारत लगातार अमेरिका के संपर्क में है। अमेरिका का दवाब यह है कि भारत कश्मीर में जल्द से जल्द राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करे और वहां बंद राजनेताओं को रिहा करे। इस पर भारत ने उन्हें बताया है कि हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चिंताओं के बारे में जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से पूछा गया तो उनका जवाब था, 'टू प्लस टू वार्ता में यह मुद्दा नहीं उठा।'

भारत–अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता के बाद वाशिंगटन में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बाएं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोंपियो। प्रेट्र

मजबूत हुआ भारत–अमेरिका का रणनीतिक गठजोड़

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

वाशिंगटन में भारत-अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की अगुआई में हुई 'टू प्लस टू वार्ता' ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्ते को और गहरा बना दिया है। एक तरफ जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर और स्पष्टता आई है तो भारत में अमेरिका की निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों की तरफ से अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण की राह एक बड़ी अड़चन खत्म हो गई है। दोनों देशों ने इसके लिए इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी एनेक्स (आइएसए) को मंजूरी दे दी है जो एक तरह से भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा करने की गारंटी देती है।

अमेरिका दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने समकक्षों मार्क एस्पर और माइक पोंपिओ के साथ 'टू प्लस टू वार्ता' की। इस वार्ता से पहले रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की अलग-अलग बैठक हुई। 'टू प्लस टू वार्ता' भी दो दौर में हुई। यह दूसरी बैठक थी। सनद रहे कि पहली बैठक सितंबर, 2018 में हुई थी। बैठक के बाद जारी प्रेस बयान से साफ है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति इसमें काफी अहम रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने-अपने बयानों में यह छिपाने की भी कोई कोशिश नहीं की कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा भारत-अमेरिका रिश्तों को करीब लाने का एक अहम जरिया बन गया है। सनद रहे कि इस क्षेत्र में चीन काफी सिलसिलेवार तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वह इस बारे में तय अंतरराष्ट्रीय कायदे कानून को भी नहीं मान रहा। ऐसे में जयशंकर का यह कहना, 'हमने यह चर्चा की कि किस तरह से न सिर्फ एक दूसरे की क्षमता को ही बढ़ाने की राह निकाली जाए बल्कि इस समूचे क्षेत्र को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए। हमारा सहयोग एक आजाद, सभी के लिए खुला, शांतिपूर्ण और समृद्धशाली हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थापना हो', यह बयान भारत और अमेरिका के बीच बन रहे सामंजस्य को बताता है।

बैठक का दूसरा अहम पहलू रहा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी एनेक्स को मंजूरी देना। इसका खाका हाल ही में दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के अधिकारियों की तरफ से गठित एक समिति ने तैयार किया था। यह भारत में निवेश करने वाली या संयुक्त उद्यम के जरिये प्लांट लगाने वाली अमेरिकी रक्षा कंपनियों के निवेश और तकनीक को सुरक्षा मुहैया कराएगा। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात के संकेत दिए कि आने वाले दिनों में अमेरिका की कई रक्षा कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और भारत भी अमेरिका से कई तरह के रक्षा उपकरणों की खरीद करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि किस तरह पिछले एक दशक में भारत उसके हथियारों का एक बड़ा खरीददार देश हो गया है। आने वाले दिनों में दोनों देशों की तरफ से रक्षा क्षेत्र में कई रक्षा उपकरणों और हथियारों को संयुक्त तौर पर विकसित करने का एलान किया जाएगा। साथ ही यह भी फैसला किया गया कि दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच हर वर्ष 'टाइगर ट्रंप' के नाम से युद्धाभ्यास किया जाएगा।

आतंकवाद का मुद्दा भी काफी अहम रहा क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ कई स्तरों पर सहयोग हो रहा है। दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में हर तरह के आतंकवाद की निंदा तो की ही गई है साथ ही अमेरिका ने अपनी तरफ से मुंबई और पठानकोट आतंकी वारदातों के हमलावरों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग रखी। बैठक में द्विपक्षीय कारोबार का मुद्दा भी उठा। संयुक्त बयान के मुताबिक, कारोबारी रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर अभी दोनों पक्षों में जो बात हो रही है उसमें साझा हितों का ख्याल रखने का वादा किया गया है। 5जी का मुद्दा भी उठा और अमेरिका ने बगैर किसी लाग लपेट के कहा कि भारत को इस बारे में उसकी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। सनद रहे कि 5जी में चीन की कंपनी हुआवई की तकनीक भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे।

'टू प्लस टू वार्ता' के अहम पहलू

- हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग में आई स्पष्टता
- भारत में अमेरिकी रक्षा कंपनियों के आने की राह आसान
- हर वर्ष दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच होगा युद्धाभ्यास
- दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हॉट लाइन स्थापित
- चाबहार में भारतीय गतिविधियों को ईरान पर लगे प्रतिबंधों से छूट

न्यूज गैलरी

तान्हाजी फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड करे सुनवाई : हाई कोर्ट

नई दिल्ली : मराठा सेना में अहम रोल अदा करने वाले तान्हाजी मलौसरे की जीवनी पर आधारित फिल्म तान्हाजी में उनके जीवन का सही चित्रण नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया कि याचिका को प्रस्तावना के तौर पर लेकर सुनवाई करे। पीठ ने कहा कि याचिका समय से पहले दायर की गई है, क्योंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। 10 जनवरी को रिलीज होगी। (जासं)

पीडीपी नेताओं ने महबूबा से मिलने की मांगी इजाजत

जम्मू : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य में रणनीति तय करने के लिए पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मिलने का फैसला किया है। इसके लिए श्रीनगर जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। 4 अगस्त की मध्यरात्रि को हिरासत में ली पीडीपी सचिव अब्दुल हमीद कोशीन ने कहा कि प्रशासन से अभी कोई जवाब नहीं मिला है। (राब्यू)

गांधी की 150 वीं जयंती पर बैठक

नई दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक में बाएं से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा और गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

नेपाल सीमा का दुरुपयोग कर रहे अशांति चाहने वाले लोग : अमित शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुछ ताकतें, जो भारत में शांति नहीं देखना चाहती हैं, वह देश में घुसपैठ के लिए नेपाल से लगती सीमा का इस्तेमाल कर रही हैं। गुरुवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पिछले एक साल में भारत-नेपाल सीमा पर 24 देशों के 54 घुसपैठियों को पकड़ा गया है, जिनमें दो पाकिस्तानी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि एसएसबी के पास नेपाल और भूटान से लगती 1,751 किमी. लंबी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। शाह ने कहा कि नेपाल और भूटान के साथ भारत के बहुत सौहार्दपूर्ण और मैत्रिपूर्ण रिश्ते हैं। सीमा बल ने सुनिश्चित किया है कि इन दोनों देशों के नागरिकों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाए। लेकिन, जैसा कि दुनियाभर में घूमना आसान हो गया है, तो उन देशों के लोग, जो भारत में शांति नहीं देखना चाहते हैं, घुसपैठ के लिए भारत-नेपाल सीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा कि एसएसबी ने पिछले एक साल में 380 करोड़ के प्रतिबंधित सामान को जब्त किया है।

फास्ट ट्रैक के फेर में आरोपितों से न हो अन्याय : सुप्रीम कोर्ट

- दुष्कर्म व हत्या की सुनवाई में आरोपितों को पूरा मौका देने की नसीहत
- नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में सर्वोच्च अदालत ने फैसला पलटा
- अदालत ने एमीकस क्यूरी की नियुक्ति के लिए भी कुछ दिशा-निर्देश तय किए

नई दिल्ली, एएनआइ : देश में दुष्कर्म के बेतहाशा बढ़ते मामलों और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक ले जाने की बढ़ती मांगों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने के लक्ष्य में सावधानी बरतने की जरूरत बताई है। मध्य प्रदेश में नौ साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों की सजा-ए-मौत को खारिज करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए। साथ ही कहा कि न्याय के लक्ष्य का कभी बलिदान नहीं किया जा सकता। फास्ट ट्रैकिंग की प्रक्रिया में न्याय का गला नहीं घोंटा जा सकता है।

जस्टिस यूयू ललित, इंदू मल्होत्रा व कृष्ण मुरारी ने आरोपितों के दोष और सजा को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। गत 18 दिसंबर को पारित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपराधिक मामलों में निश्चित रूप से शीघ्र निपटान की जरूरत है और वह स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा होगा। हालांकि निष्पक्षता के मूल तत्वों की कीमत पर और आरोपितों को दिए अवसर पर ही न्याय का प्रशासन आधारित है।

खंडपीठ ने आगे कहा कि मामले के शीघ्र निपटारे के लक्ष्य में कभी न्याय की बलि नहीं चढ़ने देनी चाहिए। इसमें सबसे आला दर्जे की बात न्याय का कारण है। मूल तत्वों का ध्यान रखते हुए मूल विचार को सुरक्षित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है लेकिन इसकी फास्ट-ट्रैकिंग से कभी भी न्याय को दफन नहीं किया जाना चाहिए।

दोषी अनोखीलाल ने सर्वोच्च अदालत में अपने दोष और सजा-ए-मौत के खिलाफ अपील की थी। 30 जनवरी, 2013 को नौ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इसी आरोप में अनोखीलाल को 4 फरवरी, 2013 तो गिरफ्तार किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में 13 गवाहों के बयान सात दिनों के अंदर ही दर्ज कर लिए और उसके बाद केवल पांच तारीखों में ही सुनवाई हुई और 4 मार्च, 2013 को फैसला सुना दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में पाया कि दोषी के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुनवाई के दौरान पेश आई बहुत सी खामियों को सामने रखा है। जैसे लूथरा ने कहा कि सुनवाई अदालत में उनके मुवक्किल के लिए वकील बहुत देर से नियुक्त किया गया। इसलिए उसे बचाव के लिए बहुत कम समय मिला। लूथरा की दलीलों पर कोर्ट ने सुनवाई के अधिकार व कानूनी मदद के अधिकार पर बल देते हुए कहा, इस मामले में आरोपित के इन अधिकारों को दरकिनार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

दुष्कर्म पर देश की भयावह तस्वीर

- वर्ष 2017 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुलिस ने दुष्कर्म के 32,500 मामले दर्ज किए यानी प्रतिदिन 90 मामले दर्ज हुए। इन दुष्कर्म पीड़िताओं में तीस फीसद बच्चियां हैं।
- भारतीय अदालतों ने उस साल केवल 18,300 मामलों का निपटारा किया। फिर भी वर्ष 2017 के अंत में 1,28,000 से अधिक मामले लंबित थे।
- नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामलों में मध्य प्रदेश सबसे कुख्यात है।
- राजस्थान के जोधपुर शहर में रेप की प्रति कैपिटा दर सर्वाधिक है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली का नंबर आता है।
- मानवाधिकार संगठनों के सर्वे के अनुसार भारत में हर साल हर एक लाख नाबालिगों में 7,200 बच्चियों से दुष्कर्म दर्ज किया जाता है। पुलिस में दर्ज न किए जाने वाले आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं।

अदालत ने कहा, उसकी नजर में सुनवाई अदालत ने सुनवाई की रफ्तार तो बढ़ा ली, लेकिन न्याय के कारण को निभा नहीं सकी। जिन मामलों में मृत्युदंड वैकल्पिक सजा हो सकती है, उसकी सुनवाई के हर चरण में आरोपित को पूरा मौका देना चाहिए। अदालत ने एमीकस क्यूरी (न्याय मित्र) की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश तय किए। कोर्ट ने कहा, जिन अपराधों में म्रकैद या मृत्युदंड हो सकती है, उनमें एमीकस क्यूरी के तौर पर उन वकीलों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो केवल बार में ही दस साल वकालत कर चुके हों।

जनसंख्या नियंत्रण पर नीति आयोग की अहम बैठक आज

- परिवार नियोजन के विकल्पों पर किया जाएगा मंथन, तैयार होगा मसौदा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी थिंकटैंक नीति आयोग जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर शुक्रवार को अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा तैयार किया जाएगा। साथ ही भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के तरीकों पर भी विमर्श होगा।

आयोग की तरफ से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, 'उम्मीद है कि बैठक में गर्भनिरोधक के विकल्पों को बढ़ाने व गर्भधारण करने में देरी के लिए इन विकल्पों को अपनाने संबंधी सूचनाएं महिलाओं तक पहुंचाने आदि मुद्दों पर विमर्श होगा।' पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआइ) की साझीदारी से आयोजित इस बैठक में उन तरीकों पर भी विचार किया जाएगा, जिनके जरिये भारत की जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रम को सशक्त बनाया जा सके।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, 'यह सिर्फ एक परामर्श बैठक है। नीति आयोग विजन 2035 के तहत मसौदा तैयार कर रहा है।' आयोग ने कहा कि भारत अभी उस दौर में है, जहां जन्मदर तो कम हो रही है लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि भारत की 30 फीसद जनसंख्या युवा है और वह प्रजनन आयुवर्ग में आती है। उसने कहा, 'देश में अभी करीब तीन करोड़ महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी आयु 15-49 वर्ष है। इन्हें परिवार नियोजन के लिए गर्भनिरोधक जैसे विकल्पों से अवगत कराने की जरूरत है।'

आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया था। शुक्रवार की बैठक में आनेवाले विचार जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को हासिल करने में नीति आयोग की मदद करेंगे। उसने कहा कि करीब 1.37 अरब जनसंख्या के साथ भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।

देश के सतत विकास के लक्ष्य और आर्थिक अपेक्षाओं को पाने के लिए जरूरी है कि लोगों को गर्भनिरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में बताया जाए। परिवार नियोजन को विकास का सबसे बेहतरीन निवेश बताते हुए आयोग ने कहा कि बैठक में कुछ सामाजिक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। इनमें शादी का समय व गर्भनिरोधक के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं।

आइएमए पोंजी घोटाले में दो आइपीएस अफसरों समेत छह पर शिकंजा

- कर्नाटक के आइएमए पोंजी घोटाले में मुकदमा चलाने की मांगी अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने चार हजार करोड़ के आइएमए पोंजी घोटाले में दो आइपीएस अधिकारियों समेत कर्नाटक सरकार के छह अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इन लोगों पर घोटाले में सहयोग का आरोप है। आइ-मॉनिटरी एडवाइजरी (आइएमए) और इस समूह की दूसरी इकाइयों ने इस्लामिक तरीके से निवेश पर ज्यादा ब्याज का झांसा देकर लाखों लोगों को ठगा है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सीबीआइ ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर आइपीएस अधिकारी हेमंत निंबलकर (1998 बैच) और अजय हिलोरी (2008 बैच) के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। केंद्रीय जांच एजेंसी इन दोनों अधिकारियों के घरों पर सर्च अभियान भी चला चुकी है। निंबलकर तब आर्थिक अपराध शाखा के आइजी थे, जबकि हिलोरी बेंगलुरु पूर्व के उपायुक्त थे। इनके अलावा सीबीआइ ने जिन लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है, उनमें तत्कालीन डीएसपी (सीआइडी) ईबी श्रीधर, कॉमर्शियल स्ट्रीट थाना के प्रभारी निरीक्षक एम. रमेश, उपनिरीक्षक पी. गौरीशंकर तथा बेंगलुरु उत्तर के सहायक आयुक्त एलसी नागराज शामिल हैं।

सीबीआइ का आरोप है कि इनके पास मामले की जांच की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने आरोपितों को गलत तरीके से क्लीनचिट दे दी। अधिकारियों ने बताया कि अगर सरकार की तरफ से इन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिलती है तो सीबीआइ इस मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी।

फाइल

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सीबीआइ ने 30 अगस्त को कंपनी के प्रबंध निदेशक मुहम्मद मंसूर खान समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वह 22 अभियुक्तों के खिलाफ दो आरोपपत्र दाखिल भी कर चुकी है। इनमें समूह के निदेशक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिचौलिये, कंपनी और इसकी सहयोगी इकाइयां शामिल हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया था जब मंसूर खान दुबई भाग गया था और एक वीडियो संदेश के जरिये कहा था कि वह राज्य तथा केंद्र में भ्रष्टाचार के कारण खुदकशी करने जा रहा है। हालांकि, दुबई से लौटते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे 21 जुलाई को नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय ने जून में ही आइ-मॉनिटरी एडवाइजरी (आइएमए) और खान आदि के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर तमाम राजनेताओं और अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हुए थे। इस मामले में सरकार ने त्वरित और निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा था कि किसी भी निवेशक का नुकसान नहीं होगा।

मंथन

मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन का एलान मकर संक्रांति के बाद संभव, समाज का कोई भी उचित गुणवान व्यक्ति हो सकता है पुजारी

दलित हो सकता है प्रस्तावित राम मंदिर का पुजारी

नीलू रंजन, नई दिल्ली

अयोध्या में रामजन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर का पुजारी कोई दलित हो सकता है। इसके लिए संत रामानंद की परंपरा का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कबीर और रविदास जैसे संत हुए थे। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सरकार की ओर से ट्रस्ट का गठन कर दिया जाएगा। इस ट्रस्ट को सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखकर पूरी तरह स्वायत्त बनाया जाएगा। यहां तक कि रामजन्मभूमि के लिए पिछले साढ़े तीन दशक से आंदोलन कर रही विश्व हिंदू परिषद का कोई पदाधिकारी भी ट्रस्ट में नहीं होगा।

राम मंदिर के प्रस्तावित ट्रस्ट के गठन को लेकर सरकार के साथ विचार-विमर्श से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार समाज का कोई भी उचित गुणवान व्यक्ति इसका पुजारी हो सकता है। संत रविदास खुद दलित थे इसीलिए राम मंदिर में दलित पुजारी होने पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि पुजारी का पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

प्रतीकात्मक

वैसे तो अभी तक ट्रस्ट की पूरी रूपरेखा सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट 11 सदस्यीय हो सकता है। जिसमें सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर अयोध्या के जिलाधिकारी या फैजाबाद के कमिश्नर के साथ ही केंद्र सरकार का एक अधिकारी भी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को सदस्य बनाने का निर्देश दिया है। सदस्यों को लेकर विचार-विमर्श का दौर अभी जारी है। इसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को इसमें स्थान न मिले जो मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा समय नहीं दे पाए। इसी तरह सरकार के सामने ट्रस्ट की स्वायत्तता पहली प्राथमिकता है ताकि भविष्य में इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो सके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि भाजपा का कोई भी नेता ट्रस्ट में शामिल नहीं होगा। विहिप ने भी साफ कर दिया है कि उसका कोई पदाधिकारी सीधे तौर पर ट्रस्ट का सदस्य नहीं होगा। लेकिन पिछले तीन दशक से रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण की तैयारी में जुटे रामजन्मभूमि न्यास को इसमें स्थान मिल सकता है और संत नृत्यगोपाल दास को ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है। रामजन्मभूमि न्यास को स्थान मिलने से उसके द्वारा अभी तक मंदिर के लिए तैयार निर्माण सामग्री को ट्रस्ट में स्थानांतरित करना आसान हो जाएगा। न्यास ने प्रस्तावित राम मंदिर का एक नक्शा भी तैयार कर रखा है और उसके अनुरूप 60 फीसद निर्माण सामग्री भी तैयार है।

अमित शाह के राम मंदिर के लिए सरकारी धन के उपयोग नहीं किए जाने के एलान से साफ हो गया है कि इसके लिए आम जनता से धन जुटाया जाएगा। विहिप के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैसे तो धन संग्रह की रूपरेखा ट्रस्ट खुद तय करेगा, लेकिन इसमें जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

एचडीआइएल और उसके प्रमोटरों को चुकाना होगा पीएमसी बैंक का कर्ज

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि एचडीआइएल और उसके प्रमोटरों राकेश वधावन और सारंग वधावन को पंजाब एवं महाराष्ट्र कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक का कर्ज चुकाना होगा। यह बैंक और वहां धन जमा करने वालों के हित में होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा, पीएमसी बैंक और जमाकर्ताओं के हित में एचडीआइएल और वधावन की संपत्ति जल्द से जल्द बेची जानी चाहिए।

जस्टिस रंजीत मोरे और एसपी तावड़े की पीठ वकील सरोश दमनिया द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याची वकील ने ईओडब्ल्यू और ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का तुरंत निपटारा करने और पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं का शीघ्र भुगतान कराने का निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले कोर्ट के पिछले निर्देश पर एचडीआइएल के प्रबंध निदेशक सारंग वधावन ने बुधवार को संपत्ति की सूची के साथ शपथ पत्र पेश किया था। यह भी कहा है कि कंपनी की संपत्ति बेची जाती है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

2005 में झारखंड के पहले विधानसभा चुनाव में केवल दो मुसलमान विधायक बने थे। 2009 में हुए चुनाव में पांच चुने गए। 2014 के विस चुनाव में एक बार फिर से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दो सीटों पर सिमट कर रह गया। प्रदेश में 15 फीसद आबादी मुस्लिमों की है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 20 दिसंबर 2019

कई स्टार प्रचारकों का इंतजार ही करता रहा चुनावी मंच

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव में एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति इरानी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे दिग्गज स्टार प्रचारकों ने ताबड़तोड़ जनसभाएं कीं, वहीं दूसरी ओर चुनावी मंच कई अन्य बड़े स्टार प्रचारकों का इंतजार ही करता रहा। कई छोटे-बड़े दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने झारखंड नहीं आ सके। इनमें कुछ पार्टी के मुखिया भी शामिल हैं।

अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जदयू के प्रत्याशी तरसते रहे। प्रदेश जदयू को उम्मीद थी कि उनके सबसे बड़े नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने झारखंड आएंगे। इसलिए स्टार प्रचारकों की सूची में उनका भी नाम सबसे ऊपर था। लेकिन, नीतीश ने ऐन वक्त पर दो टूक कह दिया कि उनके झारखंड जाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि, उनके निर्देश पर बिहार के कई मंत्रियों और सांसदों ने लगातार पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। पार्टी ने प्रशांत किशोर को भी स्टार प्रचारक में शामिल किया था, लेकिन वे भी चुनाव प्रचार से नदारद रहे। नीतीश की पार्टी झारखंड में 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

इधर, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के अलावा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को भी शामिल किया था। राहुल गांधी तो कई जनसभाओं में शामिल हुए, लेकिन प्रियंका गांधी अंतिम चरण में महज एक जनसभा ही कर सकीं। दूसरी तरफ, सोनिया गांधी तथा मनमोहन सिंह चुनाव प्रचार में नहीं आ सके। इसी तरह, राजद के स्टार प्रचारकों में बिहार की पूर्व मंत्री राबड़ी देवी तथा मीसा भारती का भी नाम था। लेकिन, ये दोनों चुनाव प्रचार में नहीं आ सके।

स्टार प्रचारक के रूप में शामिल तेज प्रताप भी चुनाव प्रचार से दूर ही रहे। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव तथा अखिलेश यादव को स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर रखा था, लेकिन दोनों नेता चुनाव प्रचार करने झारखंड नहीं आ सके। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार करने झारखंड नहीं आ पाईं। कई अन्य दलों के भी बड़े स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करने झारखंड नहीं आ सके। कुछ बड़े स्टार प्रचारक ऐसे भी रहे जो एकाध जनसभा ही कर सके।

हेमंत ने रघुवर दास के खिलाफ की जातिसूचक शब्द कहने की शिकायत

लगाए आरोप ▶ एससीएसटी थाना में खुद जाकर दिया लिखित आवेदन, पेश किए सुबूत

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव
2019

दुमका के एसटीएससी थाना में गुरुवार को एसडीपीओ पूज्य प्रकाश के समक्ष शिकायत करते झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन (पीली जैकेट में) व साथ में बैठे विजय कुमार सिंह। जागरण

- कहा, सदन से लेकर सभाओं में उनके लिए अपशब्दों का उपयोग कर चुके हैं
- एसडीपीओ ने आवेदन लेकर दिया कार्रवाई का आश्वासन

> पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लिखित आवेदन मिला है। जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास पर जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाया है। आवेदन के आधार पर सुसंगत धारा के तहत मामला दर्ज आगे की कार्रवाई की जाएगी।
> **– पूज्य प्रकाश, एसडीपीओ, दुमका।**

जागरण संवाददाता, दुमका

झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास पर जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगाते हुए गुरुवार की शाम एससीएसटी थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। हेमंत ने खुद एसडीपीओ पूज्य प्रकाश को आवेदन दिया। आवेदन के साथ उन्होंने एक समाचार पत्र की कटिंग दी, जिसमें उनके आरोप को दर्शाती हुई खबर प्रकाशित हुई है।

आवेदन में लिखा है कि 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने जामताड़ा जिले के मिहिजाम में चुनावी सभा को संबोधित करते वक्त उनके उपनाम को जाति सूचक गाली दी। उन्होंने पुलिस से मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। हेमंत ने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार सदन से लेकर संथाल परगना की सभाओं में उनके लिए अपशब्दों का उपयोग कर चुके हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

बाहरी छत्तीसगढ़िया ने किया झारखंडी का अपमान : झामुमो

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव में राजनीतिक विरोधियों के प्रति तल्ख भाषा का इस्तेमाल आम हो गया है। मुख्यमंत्री की मिहिजाम की एक सभा का जिक्र करते हुए गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया कि भाजपा बौखला गई है और रघुवर दास मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। रघुवर को राज्य से बाहर का बताते हुए झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एक बाहरी छत्तीसगढ़िया ने झारखंडी का अपमान किया है।

आरोप लगाया कि बुधवार को मिहिजाम में मुख्यमंत्री रघुवर दास को संताल का बेटा, आदिवासी का बेटा कहकर संबोधित किया और अपशब्दों के प्रयोग किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनीतिक विरोधी कोई भी हो सकता है। विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन रघुवर दास ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ अपशब्दों से पूरा संताल समुदाय मर्माहत है। रघुवर दास कभी सदन में अपशब्द बोलते हैं और कभी रोड पर। राज्य में सरकारी तंत्र का पूरा उपयोग किया जा रहा है।

अंतिम दौर में आधा दर्जन सीटें हो गईं हॉट

राज्य ब्यूरो, रांची

लोकतंत्र के जश्न में अब सबकी निगाहें संताल प्रमंडल पर टिक गई हैं। अंतिम दौर में होने वाले इस चरण के मतदान में आधा दर्जन हॉट सीटें हैं, जहां प्रत्याशियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। अंतिम दौर में झामुमो-कांग्रेस-राजद के अलावा भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं आजसू ने भी पूरा जोर लगाया।

आखिरी चरण की अहमियत का अंदाजा इसी से लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभाएं हुईं। स्टार प्रचारकों के बयानों के तेवर भी बदल गए थे। सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है।

दुमका : हेमंत और लुइस की प्रतिष्ठा का सवाल

दुमका संताल परगना प्रमंडल की सबसे हॉट सीट है। इस सीट को भाजपा और झामुमो दोनों ने चुनौती के रूप में लिया है। मंत्री लुइस मरांडी और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। भाजपा के लिए इस सीट की महत्ता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहां से भाजपा ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया। झामुमो ने भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

शिकारीपाड़ा : तो सातवीं बार जीतेंगे नलिन सोरेन

शिकारीपाड़ा झामुमो की परंपरागत सीट है। पूर्व मंत्री नलिन सोरेन यहां से लगातार छह बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार जीत मिली तो वे अपना ही रिकार्ड तोड़ेंगे।

बरहेट : हेमंत को रोकने के प्रयास में भाजपा

झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछला चुनाव भी दुमका के अलावा इस सीट से लड़ा था, जिसमें यहां से उन्हें जीत हासिल हुई थी। भाजपा यहां से भी उन्हें रोकने के प्रयास में है। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई है।

पोड़ैयाहाट : प्रदीप यादव को रोकना बड़ी चुनौती

यह सीट झाविमो के प्रदीप यादव की परंपरागत सीट है। वे कई चुनावों से इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। यहां इस बार भाजपा उन्हें रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। यहां झामुमो भी जोर लगा रहा है। यह सीट बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पाकुड़ : दो पुराने दिग्गज आमने–सामने

पाकुड़ विस सीट से दो पुराने दिग्गज पूर्व स्पीकर आलमगीर आलम तथा अकील अख्तर आमने–सामने हैं। अकील अख्तर इस बार महागठबंधन में सीट चले जाने से झामुमो छोड़ आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने आलमगीर आलम की जीत के लिए कई बड़े स्टार प्रचारकों को उतारा।

सारठ : मंत्री रणधीर सिंह को झाविमो प्रत्याशी दे रहा टक्कर

सारठ सीट भी हॉट हो गई है। यहां झामिवो प्रत्याशी उदयशंकर सिंह भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं, रणधीर सिंह ने भी अपनी सीट बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।

झारखंड में राजद प्रत्याशी पर महिला नेत्री से मारपीट का आरोप

जागरण संवाददाता, पथरगामा (गोड्डा) : महेशलिट्टी पंचायत के तरडीहा गांव में बुधवार रात राजद प्रत्याशी और पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव व उनके समर्थकों पर भाजपा नेत्री सरिता देवी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इसको लेकर गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक अमित मंडल धरने पर बैठ गए। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष लीलीसी हेंब्रम ने बताया कि तरडीहा गांव स्थित उसके आवास पर विधायक अमित मंडल आए थे। रात करीब 12 बजे लौट रहे थे। तभी संजय यादव अपने 20 समर्थकों के साथ वहां आ गए और लाठी-डंडे बरसाते हुए गालियां बकने लगे। हमारे साथ मौजूद वार्ड सदस्य सरिता देवी के साथ हाथापाई की। पथरगामा पुलिस के अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया। वहीं, संजय यादव का कहना है कि सूचना मिली थी कि तरडीहा गांव में किसी के घर में रुपये छुपाकर रखे हैं। वहां पहुंचने पर विधायक के लोगों ने हमले का प्रयास किया। पुलिस ने विधायक की गाड़ी की जांच नहीं की।

आज संताल का रण, 16 सीटों पर पड़ेंगे वोट

दुमका के हवाई अड्डे से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान कराने के लिए गुरुवार को हेलीकॉप्टर से रवाना होते पीठासीन पदाधिकारी। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची

लोकतंत्र का जश्न अंतिम दौर में पहुंच गया है। शुक्रवार को पांचवें चरण में संताल प्रमंडल की 16 सीटों पर पर सुबह सात बजे से वोट पड़ेंगे। इसी के साथ इस चरण के 237 सहित कुल 1,216 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। सभी सीटों का परिणाम 23 दिसंबर को आएगा।

अंतिम दौर में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, मंत्री लुईस मरांडी तथा रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, प्रदीप यादव, सत्यानंद झा तथा पूर्व स्पीकर आलमगीर आलम जैसे दिग्गजों का भाग्य तय होगा। इस चरण में लगभग 40 लाख मतदाता इन दिग्गजों सहित 237 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 29 महिलाएं व 76 निर्दलीय भी शामिल हैं। चुनाव आयोग अंतिम चरण के मतदान के लिए भी सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की है।

इस चरण में भी कुल 5,389 मतदान केंद्रों में 3,690 मतदान केंद्र या तो संवेदनशील या अतिसंवेदनशील हैं। 396 मतदान केंद्र नक्सल कारणों तथा 1,321 अन्य कारणों से अति संवेदनशील हैं। इसी तरह, नक्सल कारणों से 208 मतदान केंद्र तथा अन्य कारणों से 1,765 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इन सभी मतदान केंद्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल या राज्य पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से आठ मतदान केंद्रों के चुनाव कर्मी हेलीकॉप्टर से पहुंचाए गए। वहीं, 124 मतदान केंद्रों के चुनाव कर्मी शुक्रवार को मतदान संपन्न होने के बाद संबंधित कलस्टरों में ही रुकेंगे। इनके सभी चुनावकर्मी शनिवार को ईवीएम के साथ जिला मुख्यालय पहुंचेंगे।

802 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान : इस चरण में राजमहल, गोड्डा, जामताड़ा एवं पाकुड़ में दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 802 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से अपने घरों में ही मतदान किया। इस श्रेणी के कुल 838 मतदाताओं ने इसके लिए आवेदन किया था। चुनाव आयोग ने इनके मतदान के लिए तीन-तीन पदाधिकारियों की टीम गठित की थी। बता दें कि पहली बार झारखंड से यह सुविधा शुरू की गई है। प्रायोगिक तौर पर सात विस क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। इससे पहले चौथे चरण में देवघर, बोकारो एवं धनबाद में यह सुविधा दी गई थी, जिनमें 1,216 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया था।

आखिरी चरण

- हेमंत, लुईस, रणधीर, नलिन, प्रदीप जैसे दिग्गजों की किस्मत
- 40 लाख मतदाता तय करेंगे 237 प्रत्याशियों का भाग्य

फैक्ट फाइल

- दो सीटों महेशपुर तथा पोड़ैयाहाट में एक भी महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रही है।
- इस बार एक वर्तमान विधायक को छोड़कर सभी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान विधायक साइमन मरांडी की जगह उनके बेटे दिनेश विलियम मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं।
- अंतिम दौर के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बूथ एप की सुविधा बहाल नहीं है।

बंपर वोटिंग होने की उम्मीद

अंतिम दौर की सभी सीटों पर बंपर वोटिंग की उम्मीद है। इसका खास आधार भी है। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 81 सीटों में से 27 सीटों पर 70 फीसद से अधिक वोटिंग हुई थी, जिनमें 12 सीटें संताल प्रमंडल की थीं। सबसे पिछड़ी सीट पाकुड़ में राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ था। पाकुड़ और नाला में 80 फीसद से अधिक वोट पड़े थे, जबकि तीसरे स्थान पर महेशपुर विस सीट रही थी।

मप्र हाई कोर्ट से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मिली राहत

नईदुनिया, जबलपुर

संबित पात्रा। फाइल

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को राहत दे दी है। उनके खिलाफ भोपाल की जिला अदालत में दर्ज चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण हाई कोर्ट ने गुरुवार को निरस्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल हेराल्ड मामले में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके परिवार पर आरोप लगाए थे। इसी को लेकर भोपाल विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी एलएल अहिरवार के एमपी नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस ने पात्रा के खिलाफ चालान भोपाल की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया था। जिस पर अदालत ने पात्रा की कोर्ट में उपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। पात्रा ने पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर व भोपाल अदालत द्वारा एमपी नगर थाने की ओर से पेश चालान पर लिए गए संज्ञान को चुनौती दी थी। 20 मार्च को कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। पात्रा की ओर से अधिवक्ता नम्रता अग्रवाल ने दलील दी कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला महज शिकायत के आधार पर दर्ज किया जा सकता है। जबकि इस मामले में पात्रा के खिलाफ किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई थी। लिहाजा, पुलिस को प्रकरण दर्ज करने का और अदालत को इस पर संज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने दलील से सहमत होकर पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआइआर व उस पर अदालत में चल रही कार्रवाई निरस्त करने का निर्देश दिया।

जोगी का जाति मामला

समीरा की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

नईदुनिया, बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति संबंधी प्रकरण में हस्तक्षेपकर्ता बनने के लिए दायर समीरा पैकरा की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

मरवाही विधानसभा क्षेत्र की पूर्व भाजपा प्रत्याशी समीरा पैकरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जोगी की जाति को लेकर हाई कोर्ट में चल रही याचिका में हस्तक्षेपकर्ता बनाने की मांग की थी। समीरा ने अपनी याचिका में कहा था कि जोगी के पुत्र व जकांछ के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी के खिलाफ मरवाही विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा अमित द्वारा जाति को लेकर पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जाति के संबंध में वे भी कोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश कर सकती हैं। ऐसा कर वे कोर्ट की कार्रवाई में मदद कर सकती हैं। गुरुवार को मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत के सिंगल बेंच में हुई। मालूम हो कि जोगी के जाति संबंधी प्रकरण में प्रमुख शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम व अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को हाई कोर्ट ने पहले ही स्वीकार कर लिया है।

मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजयुमो का प्रदर्शन, 200 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार

नईदुनिया, इंदौर: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का एक साल पूरा होने के बावजूद युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने गुरुवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी और प्रदेशभर में 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।

इंदौर में कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार करते पुलिसकर्मी। नईदुनिया

इंदौर में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बेरिकेड लांघने की कोशिश की तो पुलिस ने वज्र वाहन से वाटर केनन (पानी की बौछार) का प्रयोग किया। ठंडे पानी की तेज बौछार से कार्यकर्ता कंपकंपाते रहे। इसके बाद जो कार्यकर्ता नहीं रूके, पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए। पुलिस ने 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुरैना में धारा 144 के बावजूद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। शिवपुरी, दतिया और भिंड में भी ऐसे ही हालात बने। शिवपुरी में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के बेटे के सुरक्षागार्ड सहित भाजयुमो जिलाध्यक्ष को पुलिस ने वैन में बैठा लिया। हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया। दतिया में 77 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। बाद में इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। भोपाल में भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जबलपुर में भी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई।

युवाओं की तरफ कांग्रेस का ध्यान नहीं : भोपाल में भाजयुमो के धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में युवाओं को सपने दिखाए थे। बेरोजगारों को चार हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की बात कही थी। अब बेरोजगार युवाओं की तरफ कांग्रेस सरकार का ध्यान नहीं है।

जम्मू–कश्मीर में फिर आंदोलन की राह पर पंच–सरपंच

राज्य ब्यूरो, जम्मू : पंच-सरपंच फिर से विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू करने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के बैनर तले पंच-सरपंच शुक्रवार से ब्लॉक स्तर पर पहले दिन जम्मू के बिश्नाह और कठुआ के बनी से प्रदर्शनों का आगाज करेंगे। बीडीसी चेयरमैन का मानदेय 15 हजार रुपये किए जाने के बाद अब पंच-सरपंच भी मानदेय में उचित बढ़ोतरी की मांग करने लगे हैं। सरपंचों ने उनके मानदेय में महज 500 रुपये की बढ़ोतरी को महज मजाक करार दिया है।

मनरेगा के बकाया एक हजार करोड़ रुपये जारी करने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर पंच, सरपंच में हाल ही में आठ दिन तक भूख हड़ताल की थी। अब 10 दिन तक ब्लाक स्तर पर तहसील व एसडीएम कार्यालयों के घेराव करेंगे। कश्मीर के पंच-सरपंचों ने भी जम्मू संभाग के पंच-सरपंचों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। पंचायत कांफ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण प्रतिनिधियों का आंदोलन अंजाम तक पहुंचेगा। मनरेगा के बकाया जारी होने व पंचों का मानदेय 5 हजार व सरपंचों का मानदेय 10 हजार होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

हालात

प्रदेश में किसी भी दल की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं अजा और आदिवासी वर्ग

मप्र भाजपा में 30 साल में नहीं पनप पाया अजा–आदिवासी नेतृत्व

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है। पिछले 28-30 साल में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग में पार्टी का नया नेतृत्व स्थापित नहीं हो सका। आदिवासी वर्ग में फग्गन सिंह कुलस्ते का पार्टी के पास आज तक कोई विकल्प तैयार नहीं हुआ। यही हालात अनुसूचित जाति (अजा) वर्ग के साथ है, यहां थावरचंद गहलोत का भी विकल्प पार्टी के पास नहीं है। ये सभी नेता अब 60 से 70 की उम्र के आसपास हैं। भाजपा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसे लेकर चिंतित है।

भाजपा के पास आदिवासी चेहरे के नाम पर एकमात्र आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते और अजा वर्ग में केंद्रीय मंत्री गहलोत हैं। दूसरा ऐसा बड़ा कोई चेहरा नहीं, जिसकी प्रदेश भर में पहचान हो। यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मालवा-निमाड़ से लेकर मंडला-डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल सभी जिलों में भाजपा को भारी नुकसान हुआ। नेतृत्व संकट का बड़ा कारण नए चेहरों को आगे आने नहीं देना रहा। चाहे मालवांचल में विजय शाह, रंजना बघेल, अंतरसिंह आर्य हों या महाकोशल में ज्ञानसिंह जैसे नेता हों। अजा वर्ग में लालसिंह आर्य को पार्टी आगे बढ़ाना चाहे तो बाकी नेता उनकी घेराबंदी कर देते हैं।

फग्गन सिंह कुलस्ते। फाइल

थावरचंद गहलोत। फाइल

> भाजपा सबका साथ–सबका विश्वास की नीति पर चलती है, यही कारण है कि राजनीति में जिन्हें स्थान नहीं दिया जाता था, ऐसे वर्ग को लेकर ही भाजपा आज देश में सबसे बड़ी पार्टी है। नेतृत्व के चयन में सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो।
> **– डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश प्रभारी, भाजपा**

अजा–आदिवासी सीटें हैं निर्णायक: मध्य प्रदेश में अजा और आदिवासी वर्ग ही सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। जब-जब ये दोनों वर्ग भाजपा से दूर हुए, तब-तब सरकार में परिवर्तन होता है। वर्ष 1990 में संयुक्त मध्य प्रदेश के दौर में भी भाजपा की सरकार सिर्फ आदिवासी सीटों के भरोसे बनी थी। 1993 और 1998 में जब यही वोट बैंक कांग्रेस में चला गया तो कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 के चुनाव में आदिवासी भाजपा के साथ आए। तब प्रदेश में आदिवासी सीटों की संख्या 41 थी, जिसमें भाजपा को 34 और कांग्रेस को सिर्फ दो सीट मिली थी। परिसीमन के बाद 2008 के चुनाव में अजा सीट 47 हो गई, भाजपा के खाते में 29 सीट ही आईं। इस चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी। 2013 के चुनाव में फिर भाजपा को 32 और कांग्रेस को 15 सीट मिलीं। पिछले साल में हुए विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने 30 आदिवासी सीट और 17 अनुसूचित जाति की सीट जीतकर भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया।

बोनस को लेकर कमलनाथ और शिवराज में तीखी नोंक–झोंक

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को राज्य के किसानों को गेहूं के बोनस (160 रुपए प्रति क्विंटल) का भुगतान नहीं होने पर जमकर हंगामा हुआ। पक्ष-विपक्ष की ओर से जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोंक-झोंक हुई। कमलनाथ ने विपक्षी भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है। वहीं शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा, 'हमने भी मुंह नहीं चलाया, सरकार चलाई थी।

कमलनाथ ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर सूचित किया है कि बोनस दिया है, इसलिए सात लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी घटा रहे हैं। मप्र से भाजपा के 28 सांसद हैं, लेकिन एक ने भी संसद में यह मुद्दा नहीं उठाया। एक बात याद रखिएगा कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है।

केंद्र से पूछकर वादा किया था? : मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इधर-उधर की बात न करें, यह बताएं कि किसानों को बोनस क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बोनस देने की बात केंद्र से पूछकर लिखी थी? आरोप-प्रत्यारोप के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, कि सरकार हमारा कितना ही मजाक उड़ा लें पर किसान यह जानना चाहते हैं कि बोनस देंगे कि नहीं।'

इस पर वित्त मंत्री तरण भनोत ने कहा कि हम बोनस देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले ही बोनस देने की घोषणा कर दी थी, यह दिया जाएगा। हालांकि, विपक्ष वित्त मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और नारेबाजी करते हुए बहिर्गमन कर दिया।

2830 पाकिस्तानियों को छह साल में भारत की नागरिकता मिली। 912 अफगानी भी नागरिकता पाने वालों में शामिल हैं। इसके साथ ही 172 बांग्लादेशियों को भी भारत की नागरिकता दी गई है।

दिल्ली में कोहराम, गुरुग्राम में 10 किलोमीटर लंबा महाजाम

जासं, गुरुग्राम : नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में मचे कोहराम ने गुरुवार को साइबर सिटी की रफ्तार भी रोक दी। रजोकरी बॉर्डर (दिल्ली) पर वाहनों की जांच की वजह से सुबह लगभग नौ बजे से लेकर दोपहर लगभग एक बजे तक दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर करीब दस किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दोपहर एक बजे के बाद जांच में कुछ छूट दी गई। इसके बाद भी घंटों वाहन रेंगते रहे।

जाम का असर एमजी रोड, सोहना रोड, ओल्ड दिल्ली रोड, गोल्फ कोर्स रोड के अलावा आसपास की सभी सड़कों पर पड़ा। उद्योग विहार एवं साइबर हब के इलाके में जाम का व्यापक असर दिखा। अधिकतर लोग काम पर समय से नहीं पहुंचे। कापसहेड़ा एवं आया नगर बॉर्डर पर भी वाहनों की जांच की वजह से आसपास के इलाकों में पूरे दिन ट्रैफिक का दबाव बना रहा।

सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए नूंह एवं राजस्थान के इलाकों से भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने के लिए गुरुग्राम इलाके से दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। इसे देखते हुए सुबह सात बजे से ही सभी बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए थे।

यही नहीं दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले लगभग आठ बजे से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर रजोकरी बॉर्डर के नजदीक नाके लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। सुबह लगभग साढ़े आठ बजे तक स्थिति सामान्य थी। इसके बाद जैसे ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, कुछ ही देर में जाम पीछे इफको चौक के नजदीक तक पहुंच गया। साढ़े नौ बजे तक जाम सिग्नेचर टावर चौक तक जबकि साढ़े 10 बजे तक जाम झाड़सा चौक तक पहुंच गया था। वाहनों का दबाव इतना बढ़ गया था कि सुबह 11 बजे पीक आवर खत्म होने के बाद भी जाम राजीव चौक तक पहुंच गया था। यह हाल तब था जब अधिकतर लोग हालात को देखते हुए अपने घर लौट गए। जिसे जहां से निकलने का रास्ता मिला, वहां से अपने घर के लिए निकल गया। जाम की वजह से जहां झाड़सा चौक से सिरहौल बॉर्डर तक पहुंचने में वाहन चालकों को लगभग 10 मिनट लगते हैं, वहीं ढाई से तीन घंटे लगे।

दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर भीषण जाम

दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर गुरुवार को हजारों वाहन भीषण जाम में फंस गए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वाहनों के डायवर्जन की वजह से गुरुग्राम में सुबह टोल पर करीब दस किलोमीटर तक वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। कई घंटे तक लोग हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के बावजूद जाम में फंसे रहे। एएनआइ

संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह करवाया जाए : ममता बनर्जी

दो टूक ▶ कहा, यूएन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि को शामिल कर बने कमेटी

प्रधानमंत्री को चुनौती-अगर जनमत संग्रह में हारे, तो देना होगा इस्तीफा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

सीएए और एनआरसी के खिलाफ लगातार सड़क पर उतर विरोध कर रहीं तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है, तो वह सीएए और एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की निगरानी में जनमत संग्रह कराए।

कोलकाता में तृणमूल छात्र व युवा संगठन की ओर से नागरिकता कानून व एनआरसी के खिलाफ आयोजित सभा मंच से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बनर्जी ने कहा, 'पूरे देश में एक जनमत संग्रह हो। आप नहीं करेंगे। तृणमूल के भी रहने की जरूरत नहीं। संयुक्त राष्ट्रसंघ करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि रहेंगे। उनको साथ लेकर कमेटी बनाया जाए। हम भी यह देखना चाहते हैं कि आखिर सीएए और एनआरसी कितने लोगों को मंजूर है। बोलिए हार गए तो इस्तीफा देना होगा। मंजूर है?'

यहां बता दें कि जम्मू-कश्मीर को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लंबे समय से यूएन से हस्तक्षेप की मांग करता रहा है। पाक की ओर से बार-बार वहां जनमत संग्रह कराने की मांग रखी जाती रही है। लेकिन, भारत का रुख स्पष्ट है कि कश्मीर मामले में किसी तीसरे पक्ष की दखलअंदाजी मंजूर नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में कोलकाता में गुरुवार को आयोजित विरोध रैली को संबोधित करतीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (हाथ में माइक लिए)। एएनआइ

जनगणना में भाग लेने से इन्कार

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पहले ही बंद कर चुकी ममता ने गुरुवार को कहा कि अब वे 2021 में होने वाली जनगणना की इजाजत भी राज्य में नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनगणना नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहां जनगणना के नाम पर कुछ और किया जा रहा है। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। यहां बता दें कि एनपीआर में राज्यों की सहभागिता आवश्यक होती है।

बोलीं-किसी की दया की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां हम किसी की दया पर नहीं रहते। सभी को मालूम है कि 1947 में देश आजाद हुआ, वर्ष 1665 में भारत-पाक युद्ध हुआ। लेकिन, सवाल यह कि आजादी के 73 साल बाद हमें फिर से कैफियत देना होगा कि कौन नागरिक है और कौन नहीं है? इस देश में और बंगाल में जो लोग हैं, वे सभी नागरिक हैं।

उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की न्यायिक जांच समेत अन्य मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार एवं पुलिस से जवाब मांगा है। हालांकि, मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने छात्रों के खिलाफ तत्काल कदम नहीं उठाने समेत कोई भी अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया। अंतरिम राहत देने से इन्कार करने पर जनहित याचिका दायर करने वाले कुछ अधिवक्ताओं ने पीठ के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। याचिकाओं पर अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को हिंसा के बाद दायर की गई छह याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ये याचिकाएं अधिवक्ता रिजवान, जामिया की कथित छात्राओं लदीदा फरजाना, नबीला हसन, अयेश रेन्ना व जामा मस्जिद गुंबद के इमाम की तरफ से दायर की गई हैं। रिजवान की तरफ से पेश अधिवक्ता विनय कुमार गर्ग ने कहा कि मामले में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि घायल छात्रों को अपर्याप्त मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता मनोज धीर्यन की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस को वीसी या चीफ प्रॉक्टर ने नहीं बुलाया था। वहीं इमाम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता संजय हेगडे ने कहा कि पुलिस लाइब्रेरी और हॉस्टल में घुसी थी और छात्राओं एवं छात्रों को पीटा था।

आवाज जितनी दबाएंगे उतनी तेज उठेगी : प्रियंका

- राहुल ने भी कहा-सरकार को स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट बंद करने का हक नहीं
- दिल्ली सहित देश के बड़े हिस्से में कश्मीर जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता कानून को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार पर फिर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि किसी भी जगह आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। हर जगह धारा-144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद है। मेट्रो स्टेशन भी बंद हैं। लेकिन जो लोग जनता की आवाज से इतना बौखलाए हुए हैं और सबकी आवाज को बंद कर रहे हैं, वह जान लें कि जितना आवाज दबाएंगे वह उतनी ही और तेज उठेगी।

इस बीच, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि स्कूल-कालेज, इंटरनेट, टेलीफोन बंद करने का सरकार को अधिकार नहीं है। ऐसा करना भारत की आत्मा का अपमान है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश को इस सरकार ने कश्मीर बना दिया है। विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उन्होंने मौजूदा हालात को अघोषित आपातकाल बताया और कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार के जाने का समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि आज देश के प्रत्येक हिस्से में नागरिकता कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यह सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। उन्होंने भाजपा को भारतीय जिद पार्टी बताया। जो गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह जिद अब नहीं चलने वाली है।

प्रियंका गांधी वाड्रा। फाइल

जनता के आक्रोश को समझने की जरूरत है। सिंघवी ने इंटरनेट बंद करने को लेकर एक रोचक आंकड़ा पेश किया और बताया कि इनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 2014 के बाद हुई है। 2012 में सिर्फ तीन बार, 2013 में पांच बार इंटरनेट बंद हुआ था, जबकि 2014 में यह छह बार, 2015 में 14 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 80 बार और 2018 में 134 बार बंद किया गया। वहीं 2019 में अब तक लगभग 95 बार इंटरनेट बंद किया गया है।

एएमयू में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सरकार से जवाब तलब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने इलाहाबाद के मुहम्मद अमन खान की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि हॉस्टल खाली कराया गया है तो कोई पीड़ित छात्र कोर्ट क्यों नहीं आया? यह आरोप है कि कुछ छात्र लापता हैं, ऐसे छात्रों के परिवार के लोग कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? याचिका में मनगढ़ंत निराधार आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर सरकार अपना पक्ष रखे।

याची का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास गेट के अंदर मौजूद थे। बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस छात्रों को उकसा रही थी। पुलिस पर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसने छात्रों को गालियां दीं और छात्रों को बुरी तरह से पीटा। इसमें 100 छात्र घायल हुए हैं। तीन छात्रों की हालत बेहद खराब है।

जनमत मुद्दा

क्या दुनिया की दूसरी सर्वाधिक भारतीय मुस्लिम आबादी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बहुधा आसान निशाना बनती है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

सरकार ने पाकिस्तानी महिला को दी भारत की नागरिकता

देवभूमि द्वारका (गुजरात), एएनआइ : संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) को लेकर आशंकित लोगों का डर दूर करने वाली एक खबर सामने आई है। सरकार ने एक पाकिस्तानी महिला को भारत की नागरिकता प्रदान की है। गुजरात की यह महिला मुस्लिम समुदाय से है।

गुजरात के भनवाड़ तालुका में पैदा हुई और यहीं पली-बढ़ी हसीना बेन 1999 में शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थीं और वहां की नागरिकता ले ली थी। पाकिस्तान में ही उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन बिताया। पति के देहावसान के बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला लिया और दो साल पहले उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया। 18 दिसंबर को उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। द्वारका के कलेक्टर डॉ. नरेंद्र कुमार मीणा के अधिकृत ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट में कहा गया है कि भारत लौट आई हसीना बेन के आवेदन पर विचार करने के बाद जीओआइ (भारत सरकार) ने उनका आवेदन मंजूर कर लिया है। बुधवार को कलेक्टर ने उन्हें भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र सौंपा।

असम में हिंसा को काबू करने में कामयाब रहा केंद्र का दांव

संजय मिश्र, गुवाहाटी

असम में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध आंदोलन में हिंसा पर लगाम लगाने के लिए तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जीपी सिंह को रातोंरात सूबे में भेजने का गृह मंत्री अमित शाह का दांव कामयाब साबित हुआ है। कानून-व्यवस्था के एडिशनल डीजीपी के तौर पर असम भेजे गए सिंह ने कुछ ही घंटों में गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर न केवल लगाम कस दी बल्कि राज्य में हिंसा से पनपा भय का माहौल भी काफी कम हुआ है। बेशक असम में सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी हैं मगर बीते पांच-छह दिनों से तोड़फोड़ या हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है।

संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद 11 और 12 दिसंबर की रात गुवाहाटी में जैसी भयावह हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई वह लोगों के लिए अकल्पनीय थी। इस गंभीर हालात को देखते हुए ही 11 दिसंबर की आधी रात को गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और पुलिस ऑपरेशन के माहिर एनआइए में तैनात आइजी जीपी सिंह को तत्काल विशेष विमान से गुवाहाटी भेजा।

अगले दिन सूर्योदय से पहले गुवाहाटी पहुंचे सिंह ने एडिशनल डीजीपी का पदभार संभालने की औपचारिकता पूरी करने के बजाय पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ सीधे सड़क पर मोर्चा संभाल लिया। 12 दिसंबर की सबसे भयावह हिंसा को थामने के लिए वह खुद जवानों को लीड करते हुए भारी पत्थरबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों से लोहा ले रहे थे। इसी दिन गुवाहाटी में हिंसा के बेकाबू होने के चलते पुलिस को उपद्रवियों पर गोली चलानी पड़ी जिसमें एक किशोर समेत चार लोगों की मौत हुई। पुलिस के गोली चलाने पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए जीपी सिंह ने कहा कि भीड़ जैसी उग्र थी और हर 10 मीटर पर गुवाहाटी जल रहा था, उस समय अगर सख्ती नहीं बरती जाती तो वे आम लोगों के घरों और महिलाओं पर हमला कर सकते थे क्योंकि इसमें शामिल शरारती तत्व अधिकांश बाहरी थे।

जीपी सिंह की तैनाती के दिन ही करीब 2,500 शरारती तत्वों के गुवाहाटी छोड़ने की खुफिया रिपोर्ट से जाहिर है कि बाहर से आए लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि उपद्रवी तत्वों के साथ बरती गई कठोरता के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में कोई हिंसा नहीं हुई। यही वजह है कि पुलिस ने बीते पांच-छह दिनों में एक लाठी तक नहीं चलाई है।

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के मूल निवासी 1991 बैच के आइपीएस जीपी सिंह ने यह भी कहा कि अभी तक 350 से ज्यादा उपद्रवियों को हिंसा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

असम सरकार को मोबाइल इंटरनेट बहाल करने का निर्देश

गुवाहाटी, प्रेट्र : गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को गुरुवार शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस मनोजीत भुइयां और सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने पत्रकार अजित कुमार भुइयां और वकील-बोनोश्री गोगोई, रणदीप शर्मा और देबकांत डोले की चार जनहित याचिकाओं पर यह निर्देश दिया।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा के चलते सरकार ने 11 दिसंबर की शाम को मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। ब्रॉडबैंड सेवा पहले ही बहाल की जा चुकी है।

अदालत ने माना कि विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर भड़काऊ संदेशों और वीडियो का प्रसार रोकने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने यह कदम उठाया। ऐसा नहीं करने पर हिंसा भड़कने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने का खतरा हो सकता था।

वरिष्ठ वकील अरूप बोरबोरा, केके महंत, यूके नैयर और बिमल छेत्री याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। राज्य सरकार की ओर से देबजीत साह और केंद्र की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल एससी केयल ने पैरवी की।

सीएए का विरोध

आंदोलन से रेलवे की संपत्ति को 90 करोड़ का नुकसान

पूर्व-दक्षिण व पूर्वोत्तर रेलवे में हुआ है नुकसान, ट्रेनें रद होने से आय में कमी का रेल मंत्रालय कर रहा आकलन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीसीए) के विरोध में चल रहे रहे देशव्यापी प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप रेलवे संपत्ति को अब तक 90 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अंदेशा है। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्व, दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को हुआ है, जहां आंदोलन के कारण अधिकतर ट्रेनें रद किए जाने के बावजूद रेल संपत्तियों को तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सबसे पहले गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और आंदोलनकारियों ने ट्रेनों तथा रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाना शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप रेल प्रशासन को पूर्वोत्तर की ओर जाने और वापस आने वाली तमाम ट्रेनों को गुवाहाटी में ही रोकना पड़ा और साथ ही तमाम ट्रेनों का संचालन बंद करना पड़ा। बाद में आंदोलन की चिंगारी बंगाल भी पहुंच गई, जिससे कोलकाता और सियालदह जाने व वहां से आने वाली तमाम ट्रेनों का संचालन गड़बड़ा गया। यहां भी आंदोलनकारियों ने ट्रेनों को जमकर अपना निशाना बनाया और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। परिणामस्वरूप पूर्व रेलवे को भी अनेक ट्रेनें रद करनी पड़ीं या डायवर्जन अथवा समय परिवर्तन करना पड़ा। पिछले तीन दिनो में सीएए विरोधी आंदोलन ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है और अब दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के प्रमुख नगरों में भी उग्र प्रदर्शन देखने में आ रहे हैं। आंदोलन के परिणामस्वरूप पिछले नौ दिनों के दौरान रेलवे को 90 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें ट्रेनों के रद होने से यात्री एवं माल यातायात को हुआ नुकसान शामिल नहीं है। माना जाता है कि यह नुकसान संपत्ति के नुकसान से भी ज्यादा होगा। रेलवे बोर्ड की ओर से अभी इसका आकलन किया जा रहा है।

रेलवे बोर्ड के सूत्रों के अनुसार, सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल, बिहार और असम के दो दर्जन स्टेशनों में हुआ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में हरिश्चंद्रपुर, कटिहार तथा भालुका रोड स्टेशन सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। स्टेशनों के अलावा आंदोलनकारियों ने कई रेलवे क्रॉसिंगों और ट्रेनों को भी नुकसान पहुंचाया है। इन सभी जगहों पर 13 से 15 दिसंबर के बीच तोड़फोड़ की सर्वाधिक घटनाएं दर्ज की गईं।

आंदोलन के दौरान मंगलवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान ने आग में घी का काम किया कि रेलवे संपत्ति की रक्षा करना उनका काम नहीं है। माना जाता है कि ममता ने यह बयान रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी के बयान की प्रतिक्रिया में दिया था। अंगड़ी ने उसी दिन कर्नाटक के हुबली में कहा था कि जिन राज्यों में आंदोलनकारी रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं वहां के मुख्यमंत्रियों से कहूंगा कि उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश दें।

बंगाल सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगा रेलवे

जासं, कोलकाता : सीएए को लेकर बंगाल में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में रेलवे को 100 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए रेलवे राज्य सरकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेगा।

रेलवे के सूत्रों के अनुसार रेल अधिकारी यह मानते हैं कि विरोध के नाम पर हुई हिंसा में रेलवे को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उनका मानना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि आंदोलनकारियों को रास्ते पर रोक लिया जाता तो वे लोग रेल पटरियों या स्टेशनों तक नहीं पहुंच पाते और हमले की घटना नहीं घटती।

मुंबई में प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई शिवसेना

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस और राकांपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना मुंबई में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। शिवसेना ने लोकसभा में इस कानून से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन राज्यसभा में मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। शिवसेना के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी।

मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ ने यह पूछे जाने पर कि 'हम भारत के लोग' नामक मोर्चे में शिवसेना क्यों शामिल नहीं है तो उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन एनजीओ ने आयोजित किया है, उनकी पार्टी ने नहीं। गायकवाड़ ने कहा, 'नागरिक समूहों ने कांग्रेस, राकांपा और अन्य पार्टियों को प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अगर कांग्रेस ने यह प्रदर्शन आयोजित किया होता तो हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा का गठबंधन) के सभी साझेदारों को आमंत्रित करते।'

'हम भारत के लोग' मोर्चे के सदस्य फिरोज मीतीबोरवाला ने कहा, 'हम शिवसेना को मंच में शामिल करने को लेकर उसके साथ संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे (शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री) ने आज अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के लिए हमारी मदद की है।'

4 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं जम्मू कश्मीर को मनरेगा के लिए। जल संचय से सिंचाई सुविधाओं में बेहतरी लाने के लिए जम्मू संभाग के सांबा और कश्मीर के कुलगाम जिलों को पंचायत स्तर पर जल संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने, चैक डैम बाकर सिंचाई करने के वर्गों में अवार्ड दिए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 20 दिसंबर 2019

सरकार ने दी सफाई, एनआरसी में साधारण दस्तावेज की ही जरूरत

रखा पक्ष ▶ एनआरसी के लिए लोगों को जन्मदिन और स्थान से जुड़े साधारण ब्योरे ही देने होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से अफवाहों और संशयों की परत हटाते हुए सरकार ने एक बार फिर इन मुद्दों पर लोगों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार देश के लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए केवल अपने जन्मदिन और स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा करना होगा। एनआरसी के लिए वर्ष 1971 से पहले के दस्तावेज या अपने माता-पिता से जुड़े दस्तावेज को देने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि असम की तरह एनआरसी के लिए किसी को भी 1971 से पहले के दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि असम राज्य का मामला दुलर्भ होने के चलते वहां ऐसा करना जरूरी था। भविष्य में देश भर में एनआरसी की व्यवस्था लागू होने के सिलसिले में लोगों को केवल अपने जन्मदिन और संबंधित स्थान से जुड़े साधारण ब्योरे ही देना पर्याप्त होगा। इसमें वह मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा के दस्तावेज, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट, जमीन या मकान से जुड़े सरकारी दस्तावेजों में से भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सरकार को यह स्पष्टीकरण तब देना पड़ा है जब विपक्षी दल और सामाजिक संगठन लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मुसलमानों के प्रति भेदभाव और विभाजनकारी नीतियों के तहत लाया गया है। इन कानूनों के खिलाफ देश भर में विरोध-प्रदर्शन जारी हैं।

सूत्रों ने बताया कि एनआरसी को जब भी और जिस भी रूप में लागू किया जाएगा, उसका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून एक अलग कानून है, जिसे देश की संसद ने पारित किया है जबकि एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है। देश के लिए एनआरसी के नियमों और प्रक्रिया को अभी तय किया जाना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद में कहा था कि एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। लेकिन अब तक इसके समय को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है।

एनआरसी के स्पष्टीकरण में साफ कहा गया है कि अगर कोई निरक्षर है और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं हैं तो गवाहों और सामुदायिक पुष्टि से उसकी जानकारी हासिल की जाएगी। ऐसी किसी भी कवायद के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी भारतीय की नागरिकता उसके किन्नर, दिव्यांग, आदिवासी, दलित आदि होने से नहीं जाएगी।

वहीं, सरकार ने पीआइबी (प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो) के जरिये नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर भी सफाई देते हुए कहा कि असम में किसी का भी निर्वासन नहीं हुआ है। सवाल-जवाब की तर्ज पर नौ सवालों के जवाब देते हुए पीआइबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बताया कि सीएए ने किसी भी विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम,1955 के तहत आवेदन करने से नहीं रोका है। सीएए से भारतीयों के कोई हालात नहीं बदले हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जिन अवैध आव्रजकों के पास पूरे कागज नहीं हैं और वह धार्मिक प्रताड़ना के बाद भारत में शरण लेने 31 दिसंबर, 2014 से पहले आए थे, उन्हें छह साल के प्रवास के बाद भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन बाकी विदेशी नागरिकों के लिए भारत में प्रवास की शर्त कम से कम 12 साल ही रहेगी।

दिल्ली में दिनभर हुआ विरोध प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में बृहस्पतिवार को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग व छात्र-छात्राएं शामिल हुए। पुलिस की अनुमति के बिना लाल किला, मंडी हाउस और जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोगों ने जुटकर विरोध दर्ज कराया।

बिना अनुमति प्रदर्शन व धारा-144 लगे होने के कारण स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव, कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित व जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद समेत बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्हें बवाना स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया। शाम को सभी को रिहा कर दिया गया। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की जांच के कारण दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे और यूपी गेट के पास दिल्ली की सीमा पर भारी जाम लग गया। वहीं, आइटीओ के आसपास भी वाहनों की रफ्तार धीमी रही। मंडी हाउस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर दोपहर करीब एक बजे तक वहां से हटा दिया गया। दोपहर एक बजे के करीब प्रदर्शनकारी दिल्ली गेट स्थित शहीदी पार्क के पास जुटने लगे, जिन्हें पुलिस ने वहां से भी हटा दिया। आइटीओ के पास भी कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुख्ता सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था।

उधर, दक्षिणी दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग इलाके में गुरुवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहा। दूसरी ओर, राजघाट पर बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों ने नए कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। मजनूं का टीला, आदर्श नगर, रोहिणी सेक्टर-11 के कैंपों के ये शरणार्थी बच्चों के साथ राजघाट पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में नारेबाजी की।

लाल किला के पास स्थित सुनहरी मस्जिद के बाहर गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करते छात्र-छात्राएं व अन्य लोग। ध्रुव कुमार

लोकतंत्र को और सशक्त बनाने का संकल्प

राज्य ब्यूरो, देहरादून

संसदीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के संकल्प के साथ देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सम्मेलन में हुए गहन विचार-विमर्श से पीठासीन अधिकारियों को लोकतंत्र के समक्ष खड़ी चुनौतियों का सामना करने, संसदीय और विधायी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों ने जिस सक्रियता से सहभागिता की, उससे साफ है कि वे आने वाले समय में लोकतंत्र के मंदिरों को मजबूत व जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। 'शून्यकाल सहित सभा में उपलब्ध साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना और क्षमता निर्माण' विषय पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि इस बात पर सहमति बनी कि सभी सदस्यों को शून्यकाल में अविलंबनीय लोकमहत्व की बात रखने का अधिकार मिले। इससे विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने सम्मेलन में उठे अन्य बिंदुओं और निष्कर्षों पर भी रोशनी डाली। साथ ही कहा कि देहरादून में हुआ यह सम्मेलन लोकतंत्र के सशक्तीकरण को नई दिशा देगा।

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सदन का एक-एक पल जनता को समर्पित होता है। ऐसे में सदन का समय शोरशराबे और व्यवधान के कारण बर्बाद होता है तो यह जनता के प्रति एक तरह का अन्याय है। सदन में सार्थक बहस और चर्चा होनी चाहिए। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदारी को समझे, लोकतंत्र के अस्तित्व को यह जरूरी है।

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती को इस सम्मेलन के निष्कर्ष मील का पत्थर साबित होंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने लोस अध्यक्ष बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश समेत सम्मेलन में भाग लेने आए पीठासीन अधिकारियों को स्मृति चिह्न भेंट किए।

ऋषिकेश में गुरुवार को त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (दाएं से दूसरे), बाएं से दूसरे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल व उनकी पत्नी शशि प्रभा अग्रवाल। दाईं ओर हैं महापौर ऋषिकेश अनीता ममगाई। जागरण

भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक ब्रिगेड मुख्यालय को क्षति

जेएनएन, श्रीनगर

भारतीय सेना ने अपने दो शहीद जवानों का बदला ले लिया है। कश्मीर के टंगडार और करनाह में गोलाबारी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के ब्रिगेड मुख्यालय को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह ब्रिगेड मुख्यालय टंगडार सेक्टर के सामने एलओसी के पार अथुमकाम में है। जम्मू के हीरानगर, प्लांवाला के अलावा पुंछ के मेंढर, मनकोट और कृष्णाघाटी में सीमा पार से भारी गोलाबारी की गई। प्लांवाला में एक भारतीय सैनिक घायल हुआ है।

सूत्रों ने बताया कि गत बुधवार शाम को पाकिस्तान ने गोलाबारी तेज कर अग्रिम सैन्य चौकियों के अलावा नागरिक बस्तियों को निशाना बनाया था। भारतीय जवानों ने रणनीति बदल टंगडार सेक्टर के सामने एलओसी के पास अथमुकाम और जूड़ा इलाके में जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से रातभर एक-दूसरे के ठिकानों पर गोले बरसते रहे। पाक सेना के ब्रिगेड मुख्यालय के एक हिस्से में भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद पाक सैनिक आठ घंटे तक पूरी तरह शांत रहे। दोपहर बाद दोबारा गोलाबारी की, लेकिन भारत की त्वरित कार्रवाई पर शांत हो गए। अथुमकाम, जूड़ा व साथ सटे गुलाम कश्मीर के अन्य गांवों में दिनभर कोई हलचल नहीं देखी है।

अक्टूबर में आतंकियों के लांचिंग पैड किए थे तबाह : सैन्य अधिकारियों ने अभी तक पाक सेना के ब्रिगेड हेडक्वाटर को नुकसान पहुंचने की पुष्टि नहीं की है। गत अक्टूबर में भारतीय सेना ने गुलाम कश्मीर की नीलम घाटी में पनप रहे अथमुकाम और कुंडलशाही आतंकी लांच पैड तबाह कर दिए थे।

ब्रिगेड मुख्यालय में एसएसजी का यूनिट भी : अथमुकाम में पाक सेना के ब्रिगेड मुख्यालय के अलावा स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप (एसएसजी) का यूनिट मुख्यालय भी है। यही यूनिट कुपवाड़ा व बांडीपोर के अग्रिम क्षेत्रों में कमांडो कार्रवाई के लिए पाक सेना के बैट (बार्डर एक्शन टीम) दस्तों को भेजती है। लश्कर, जैश व हिजबुल मुजाहिदीन के लांचिंग पैड अथुमकाम के अग्रिम हिस्सों में हैं।

पुंछ में पाक ने अर्टिलरी ब्रिगेड तैनात की : भारतीय सेना के लगातार बढ़ते दबाव के बीच जम्मू प्रांत में पुंछ के सामने पाक सेना ने एलओसी पार कोटली क्षेत्र में अर्टिलरी ब्रिगेड को फारवर्ड पोस्टों की पास ऑपरेशनल मोड में तैनात करना शुरू कर दिया है। उसकी यह ब्रिगेड एक माह से कोटली शहर के पास तैनात थी।

प्लांवाला में छह घंटे तक गोलाबारी

जम्मू के अखनूर तहसील के प्लांवाला में ललयाली इलाके में पाक सेना ने सुबह करीब 11 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक गोलाबारी की। जवाबी कार्रवाई के दौरान सेना का एक जवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंटरी के सिपाही विकास भगत घायल हो गया। हालांकि इसकी अधिकारिक रूप से पुष्टि नही हुई है। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के पानसर, छन्न लालदीन, ढगली गांवों में बुधवार रात को भी पाक रेंजरों ने गोलीबारी करने के अलावा मोर्टार शेल दागे।

अग्रिम चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया

सुबह 7 .10 बजे पाक सेना ने पुंछ जिले के मेंढर के मनकोट सेक्टर, कृष्णा घाटी और मेंढर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों में भारी गोलाबारी की। सीमांत क्षेत्रों में दहशत का माहौल है।

एलओसी पर पाक सेना का जमावड़ा, तोपें तैनात

जागरण संवाददाता, राजौरी : संघर्ष विराम के उल्लंघन पर मिल रही जवाबी कार्रवाई से हताश पाकिस्तान पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है। राजौरी से लेकर पुंछ तक नियंत्रण रेखा पार पाकिस्तान ने तोपों, टैंकों के अलावा 50 हजार से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारतीय सेना भी पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं, सेना प्रमुख बिपिन रावत पहले ही इसका अंदेशा जता चुके हैं।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था से आतंकवादियों की घुसपैठ पर रोक लग गई है। पाकिस्तानी सेना गुलाम कश्मीर को लेकर भारत की संभावित कार्रवाई से भी आशंकित है। इसलिए उसने अपने क्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी हैं। पाकिस्तान ने चंद दिनों में 50 हजार से अधिक सैनिकों को एलओसी के पार जगह-जगह तैनात कर दिया है।

सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले एलओसी पर 30 हजार पाक सैनिक तैनात थे अब इनकी संख्या 80 हजार से अधिक हो चुकी है। 30 से अधिक पैदल सेना इकाइयां शामिल हैं जिनमें 30 हजार सैनिक हैं। 25 मुजाहिद बटालियन जिनमें 17 हजार सैनिक हैं। बख्तरबंद टैंक बटालियन को तैनात कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा इकाई के दो हजार से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है। इनके ऊपर चार डिवीजन मुख्यालय व 10 ब्रिगेड मुख्यालय कमान कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेना ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सेना के बड़े अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं।

न्यूज गैलरी

चोकसी को झटका, एंटीगुआ में पूछताछ की मांग खारिज

मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को कोर्ट से झटका लगा है। विशेष अदालत ने चोकसी की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उससे एंटीगुआ में पूछताछ करने का निर्देश देने की मांग की थी। एंटीगुआ में रह रहे चोकसी ने पिछले महीने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि वह भारत आने के लिए चिकित्सीय रूप से ठीक नहीं है और केंद्रीय एजेंसी को उससे कैरेबियाई देश में पूछताछ करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। (प्रेट्र)

रिहाई के लिए अदालत नहीं जाएंगे उमर और फारूक

श्रीनगर : एहतियातन हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंदी बनाए गए नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व सीएम डॉ. फारूक अब्दुल्ला अपनी रिहाई के लिए अदालत का सहारा नहीं लेंगे। नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता व दक्षिण कश्मीर के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि हम लोग डॉ. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से 6 अक्टूबर को मिले थे। उसके बाद से हमारी दोनों नेताओं से कोई मुलाकात नहीं हुई है। (राब्यू)

फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी ने कहा सामवेद जैसी बातें इस्लाम में भी हैं

सुधीर पांडेय, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)

प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी ने सामवेद का उर्दू और अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विद्वानों की अनुमति मिलने के बाद इसका प्रकाशन व विमोचन फरवरी और मार्च के बीच में हो सकता है। वह चाहते हैं कि राष्ट्रपति से इसका विमोचन कराया जाए।

चाईबासा में पढ़े दुर्रानी ने गुरुवार को दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि सामवेद में जो बातें लिखी गई हैं, वैसी ही कुछ बातें इस्लाम में भी हैं। लोगों को दूसरे धर्म के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। आज धर्म के नाम पर लोग बेवजह लड़ते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दूसरे धर्म के बारे में नहीं जानते हैं।

उपहार में मिले वेद से आया अनुवाद का विचार: उन्होंने बताया कि लगभग तीन-चार साल पहले एक फिल्म का लोकेशन (फिल्माने की जगह) देखने उत्तरप्रदेश के एटा गए थे। वहां एक मठ में सामूहिक हवन ने उन्हें आकर्षित किया। मठ में जाकर हवन की पूरी प्रक्रिया देखी। लौटते समय मुख्य पुजारी ने उपहार में चारों वेद दिए। इसके बाद वेदों को पढ़ा। इस पर उर्दू व अंग्रेजी में सामवेद के अनुवाद का विचार आया।

ढाई साल में पूरा हुआ अनुवाद: इसके अनुवाद में ढाई साल का समय लगा। उन्होंने बताया कि अनुवाद के बाद इसकी पांडुलिपि वेद के ज्ञाता पंडितों और विशेषज्ञों को पढ़ने के लिए दी है, ताकि वेद की मूल भावना को ठेस नहीं पहुंचे। प्रकाशन के बाद किसी तरह का विवाद नहीं हो। आगामी फरवरी-मार्च तक इसका प्रकाशन हो जाएगा। टाइपिंग का काम हो गया है।

क्या है सामवेद में : 'साम' शब्द का अर्थ है 'गान'। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय किया जाता था।

इकबाल दुर्रानी। जागरण

दादा थे संस्कृत शिक्षक

वैसे तो इनका पैतृक गांव बिहार के बांका जिले के बौंसी बलुआतरी है। दादा शेख महमूद मोकामा में संस्कृत पढ़ाते थे। उन्हीं की प्रेरणा से सामवेद का उर्दू और अंग्रेजी में अनुवाद कर पाया। दुर्रानी के पिता जगन्नाथपुर में शिक्षक थे। 'कालचक्र', बेताज बादशाह, खुद्दार व धरतीपुत्र जैसी सुपर हिट फिल्मों का निर्देशन कर चुके दुर्रानी अभी एक बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं। दुर्रानी के बारे में फिल्म जगत में कहा जाता है कि वह अपनी फिल्मों में कलाकारों पर विशेष ध्यान देते हैं और उनसे बेहतर अभिनय कराते हैं।

बिजनौर सीजेएम कोर्ट में हत्या की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

जासं, बिजनौर: जिलाधिकारी ने भरी अदालत में हत्यारोपित शाहनवाज की हत्या के प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच एडीएम प्रशासन को सौंपी गई है। वहीं, गुरुवार को जिला जज ने जजी परिसर का मुआयना किया। दिनभर परिसर में कड़ी चेकिंग की गई। सघन तलाशी के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से गेट नंबर तीन को दीवार खड़ी कर बंद करा दिया गया। इसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया।

डीएम रमाकांत पांडेय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि मजिस्ट्रेट जांच एडीएम प्रशासन विनोद कुमार गौड़ को सौंपी गई है। यदि किसी व्यक्ति को कोई लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना है तो वह 15 दिन के अंदर किसी भी कार्य दिवस में कलक्ट्रेट स्थित एडीएम प्रशासन के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। बता दें कि बसपा के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र प्रभारी एवं प्रॉपर्टी डीलर हाजी मोहम्मद एहसान व उनके भांजे शादाब की 28 मई को नजीबाबाद में हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड के हत्यारोपित कुख्यात शाहनवाज अंसारी और जब्बार की सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को पेशी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीन हमलावरों ने शाहनवाज की हत्या कर दी थी।

अश्लील मैसेज भेजने पर सेना के एडीजी सुभाष शरण कार्यमुक्त

निशांत यादव, लखनऊ

एनसीसी बालिका कैडेटों को अश्लील वीडियो भेजने के मामले में आखिरकार वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को पद गंवाना पड़ गया। कोर्ट मार्शल से पहले ही सेना भर्ती मुख्यालय यूपी व उत्तराखंड के एडीजी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के आदेश के बाद एडीजी की सेवा से जुड़ी सारी सुविधाएं रोक दी गई हैं। वहीं, इस घटना से जुड़ा एडीजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब कभी भी एडीजी के कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई जा सकती है।

मेजर जनरल डॉ. सुभाष शरण एक जून 2018 को यूपी एनसीसी के एडीजी बने थे। यूपी से पहले वह गुजरात एनसीसी में इसी पद पर तैनात थे। गुजरात एनसीसी की बालिका कैडेटों ने मेजर जनरल शरण पर मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो और मैसेज भेजने की शिकायत रक्षा मंत्रालय में की थी। शिकायत की जांच आर्टिलरी स्कूल में तैनात लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हुई। दो राज्यों के एडीजी एनसीसी और एक महिला कर्नल ने मेजर जनरल के मोबाइल फोन के बैकअप, वाट्सएप से चैटिंग और गूगल पर स्टोर डाटा की जांच के बाद उनको आरोपी पाया था। समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड शुरू हुई तो मेजर जनरल शरण को एनसीसी से हटाकर यूपी व उत्तराखंड भर्ती मुख्यालय का एडीजी बना दिया गया। करीब एक साल बाद शरण को समरी ऑफ एविडेंस में भी दोषी पाया गया था। अब कोर्ट मार्शल से पहले मेजर जनरल शरण को रक्षा मंत्रालय ने कार्यमुक्त कर दिया है।

डॉ. सुभाष शरण फाइल

कोर्ट मार्शल ऑर्डर से पहले ही सभी सुविधाएं रुकीं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

धीमी जांच से खफा थे सेनाध्यक्ष

इस मामले में एडीजी के खिलाफ धीमी जांच को लेकर सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत से अक्टूबर में एनसीसी छात्राओं ने उनके गुजरात दौरे के दौरान शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सेनाध्यक्ष ने नाराजगी जताई। एक साल से लंबित जांच प्रक्रिया को पूरी कर समरी ऑफ एविडेंस में मेजर जनरल पर आरोप तय कर दिए गए थे।

सौगात

630 रुपये होगा किराया, कालका-शिमला रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़कर छह हो जाएगी, दैनिक जागरण ने 13 दिसंबर के अंक में प्रमुखता से छापा था ट्रेन के बारे में

क्रिसमस से शुरू होगी नई हिमदर्शन एक्सप्रेस

सौरव बत्रा, कालका (पंचकूला)

रेलवे ने वीरवार को कालका-शिमला (विश्व धरोहर) नैरोगेज रेल लाइन पर चलने वाली एक नई ट्रेन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस ट्रेन को हिमदर्शन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इसके साथ-साथ इस रूट पर रेलवे द्वारा चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या बढ़कर छह हो जाएगी। गौरतलब है कि गत 13 दिसंबर के अंक में छपी विशेष खबर विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन तैयार, क्रिसमस से पहले हो सकती है शुरू, पर मुहर लग गई है।

अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक जीएम सिंह व सीनियर डीसीएम हरि मोहन ने बताया कि इस ट्रेन के लिए रेलवे द्वारा 630 रुपये प्रति व्यक्ति किराया निर्धारित किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेन के एक कोच में

15 रिवर्सेबल सीट दी गई हैं, जिससे पर्यटकों सुविधा रहेगी। वहीं इस नए कोच में लगी सीटो में कुशन की सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ नए बनाएं गए इस कोच में दो ऐसी लगे है। वहीं पावर बैकअप के लिए साढ़े सात किलोवाट का जैनसेट लगाया गया है। धूप से बचने के लिए हनिकॉम्ब ब्लाइंड व हर कोच में वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा दी गई है। रेलवे द्वारा आगामी क्रिसमस (25 दिसंबर) 2019 से लेकर अगले वर्ष 24 दिसंबर तक इस ट्रेन को चलाने अधिसूचना जारी की है।

ये रहेगा शेड्यूल

कालका से शिमला 52459	कालका से चलेगी	शिमला पहुंचेगी
	सुबह 7 बजे	दोपहर को 12 : 55 पर
शिमला से कालका 52460	शिमला से चलेगी	कालका पहुंचेगी
	दोपहर 3 :50 पर	रात को 9 :15 पर

कालका-शिमला की बीच चलने वाली नई हिमदर्शन एक्सप्रेस की ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग शुक्रवार से शुरू होने की उम्मीद है। **-गोकुल सिंह, एसएस, कालका रेलवे स्टेशन।**

विभाग के आला अधिकारियों के निर्देश पर इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। इसके संचालन को लेकर विभाग और पर्यटकों में भारी उत्साह है। उम्मीद है कि पर्यटक इसे सराहेंगे। **-अमर सिंह ठाकुर, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, कालका-शिमला।**

हिमदर्शन एक्सप्रेस में होंगे 6विस्टाडोम कोच रेलवे अधिकारी जीएम सिंह ने बताया कि इस ट्रेन में छह विस्टाडोम कोच के साथ-साथ एक एफसीजेडएलआर कोच लगाएं जाएंगे। ट्रेन को अप में कालका से शिमला 52459 नबर और डाउन में शिमला से कालका 52460 नंबर से पहचाना जाएगा।

फतेहपुर की दुष्कर्म पीड़िता की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

हार गई जिंदगी की जंग

- दुष्कर्म के बाद जलाई गई थी युवती, सुबह साढ़े छह बजे ली अंतिम सांस
- गांव नहीं लाया गया शव, सीधे घाट ले जाकर कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार

दुष्कर्म के बाद केरोसिन डालकर जलाई गई युवती छठे दिन जिंदगी की जंग हार गई। कानपुर के एलएलआर अस्पताल में भर्ती पीड़िता के अंगों ने गुरुवार की सुबह करना बंद कर दिया। सुबह साढ़े छह बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। पीड़िता की मौत के बाद फतेहपुर में उसके गांव में बवाल की आशंका पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और शव को सीधे गंगा के रामचंद्रन घाट ले जाया गया, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में युवती के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में आरोपित का पिता भी शामिल हुआ। उधर, पुलिस ने मुकदमे में जानलेवा हमले के प्रयास की रिपोर्ट को हत्या के मुकदमे में तब्दील किया है।

हुसेनगंज क्षेत्र के एक गांव में 14 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे 18 वर्षीय युवती को दुष्कर्म के बाद जलाने का आरोप लगा था। उसे सदर अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया था। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनुराग सिंह व प्लास्टिक सर्जन डॉ. पुष्पेंद्र कनौजिया की देखरेख में इलाज चल रहा था। युवती 80 फीसद जल चुकी थी। चेहरे समेत लगभग पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था। अंदरूनी अंगों में सूजन के कारण सांस लेने में दिक्कत होने पर फेफड़े में ट्रैकास्टमी कर ट्यूब के जरिये ऑक्सीजन दी जा रही थी। चौथे दिन वह कोमा में चली गई थी। बुधवार शाम मल्टी आर्गन फेल्योर की स्थिति होने पर उसे वेंटीलेटर पर रखा गया, लेकिन गुरुवार सुबह तक फेफड़े-किडनी समेत सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसे आधे घंटे सीपीआर भी दी गई, लेकिन सफलता न मिलने पर चिकित्सकों ने सुबह 6.30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम डॉ. आरपी तिवारी, डॉ. नवनीत चौधरी एवं डॉ. एसपी कटियार के पैनल ने किया। रिपोर्ट में मौत की वजह सेप्टीसीमिया और शॉक बताई गई है।

इसके बाद शाम करीब चार बजे शव फतेहपुर के रामचंद्रन घाट ले जाया गया। युवती के भाई का कहना है कि एसडीएम ने शव को गांव ले जाने से मना करते हुए सीधे घाट ले जाने की बात की। परिवार ने भी सहमति दे दी। सभी लोग सीधे घाट पर गए। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करा दी गई है। उधर, डीआइजी कवींद्र प्रताप सिंह भी पल पल की अपडेट लेते रहे। समीक्षा बैठक के लिए आए डीआइजी अंतिम संस्कार की सूचना मिलने के बाद वापस हुए।

278 लोगों को सजा सुनाई गई है हिमाचल प्रदेश में डेढ़ साल में एनडीपीएस एक्ट के 595 मामलों में। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शिक्षण संस्थानों में भी नशे के खिलाफ पाठ पढ़ाया जा रहा है।

न्यूज गैलरी

हैदराबाद दुष्कर्म के आरोपितों के परिजन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपितों के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने, जांच कराने और आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता पीवी कृष्णामचार्य और आर. सथीश के जरिये दायर याचिका में मारे गए चारों आरोपितों के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने और अपने पुत्रों की पुलिस हिरासत में मौत के लिए 50-50 लाख रुपये के हर्जाने की मांग भी की गई है। याचिका में दावा किया गया है, 'चारों मारे गए कथित आरोपित निर्दोष हैं। पुलिस ने लोगों को खुश करने और वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए उद्देश्य से सुबूत नष्ट करने के लिए चारों आरोपितों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। इसकी वजह यह है कि पुलिस वास्तविक दोषियों को पकड़ नहीं पाई।' याचिका में साइबराबाद पुलिस आयुक्त सीवी सज्जनार समेत सभी पुलिस अधिकारियों और तेलंगाना सरकार को सुबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने, मुठभेड़ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के निर्देश देने की मांग भी की गई है। (एएनआइ)

नक्सली पर्चा बांटने वाले छात्रों पर चलेगा यूएपीए का मुकदमा

कोच्चि : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने केरल में नक्सली समर्थक पर्चा बांटने के आरोपित दो छात्रों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया है। एनआइए ने इस मामले में बुधवार को मुकदमा दर्ज किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 27 नवंबर को राज्य में सत्तारूढ़ माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं टी. फजल (24) और ए. सुहैब (20) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दोनों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों से यह जाहिर होता है कि दोनों के माओवादियों से संपर्क हैं। फैजल और सुहैब क्रमशः पत्रकारिता व कानून के छात्र हैं। वे माकपा सदस्य भी हैं। दो नवंबर को कोझिकोड में इनकी गिरफ्तारी की राज्यभर में आलोचना हुई थी। (प्रेट्र)

मुठभेड़ में महिला समेत दो नक्सली ढेर

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सिगनमडगू के जंगल में गुरुवार शाम पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में महिला समेत दो वर्दीधारी नक्सली ढेर हो गए। आइजी बस्तर सुंदरराज पी और एसपी सुकमा शलभ सिन्हा ने बताया कि गुरुवार को चिंतागुफा थाना से डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टुकड़ियां तलाशी अभियान पर निकली थीं। सिगनमडगू के जंगल में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब एक घंटे तक चली जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। मौके से दो नक्सलियों के शव और एक थ्री नॉट थ्री राइफल व एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। महिला नक्सली के वर्दी पर लगे चिह्न से उसे प्लाटून नंबर आठ की सदस्य बताया जा रहा है। उधर, सुकमा जिले में ही एक लाख रुपये के इनामी नक्सली मड़कामी सोमारू ने तोंगपाल थाना प्रभारी विजय पटेल और सीआरपीएफ 227 वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी रामचंद्र राम के समक्ष समर्पण कर दिया। वह कटेकल्याण, बस्तर के दरभा, पखनार और सुकमा के कुकानार एरिया में सक्रिय था। (नईदुनिया)

ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका राकेट का सफल परीक्षण

बालेश्वर : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संयुक्त रूप से ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से गुरुवार दोपहर 12:05 बजे उन्नत संस्करण के पिनाका राकेट का सफलता पूर्वक परीक्षण किया। इससे पिनाका की मारक क्षमता और सटीकता बढ़ गई है। पिनाका को पुणे के अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिसमेंट और हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेब्रोटरी ने मिलकर तैयार किया है। पहले पिनाका में गाइड लाइन सिस्टम नहीं था, जिससे अब लैस किया गया है। पहले इसकी मारक क्षमता 40 किमी थी जो अब बढ़कर 70 किमी हो गई है। गुरुवार को परीक्षण के दौरान चांदीपुर के रक्षा क्षेत्र में रडार इलेक्ट्रो आप्टिकल सिस्टम व टेलीमेट्री सिस्टम ने राकेट के पूरे मार्ग की निगरानी की। (जासं)

उत्तर भारत में ठंड ढाने लगी सितम, कोहरा बना कहर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए बदलाव ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ कंपकंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर जारी है। पंजाब में एक बुजुर्ग की मौत हो गई।

मौसम विभाग के मुताबिक अभी तीन दिन और ऐसा ही मौसम बना रहेगा। राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा होगा। शनिवार को जरूर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को दिल्ली के लोगों ने मौसम की सबसे सर्द सुबह में आंखें खोली। अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री कम 15.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले साल 28 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हवा में नमी का स्तर 82 से 100 फीसद रहा। दिन भर बादल छाए रहे। हिमाचल और उत्तराखंड में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में रुक-रुक कर बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाए रहे। भारी बर्फबारी के कारण एक सप्ताह से रोहतांग दर्रे में लोगों की आवाजाही नहीं हो सकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार व नैनीताल के स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। वैष्णो देवी तीर्थस्थल जाने के लिए बेस कैंप कटरा में रात में तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

रबी फसलों के लिए फायदेमंद : करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक कोहरा पड़ने और तापमान में गिरावट होने से रबी फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। इनमें गेहूं, सरसों, चना, मटर, गन्ने आदि की फसलों को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण नदियों के जलस्तर में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह से पन बिजली इकाइयों में उत्पादन घट गया है। हरियाणा के यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर पर स्थापित बिजली इकाइयों पर बिजली उत्पादन घटकर करीब पांच लाख यूनिट रह गया है, जबकि क्षमता 10 से 12 लाख है।

उत्तर भारत भीषण ठंड के आगोश में है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम बढ़ गया है। गुरुवार को नई दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहा। संजय

शहर और न्यूनतम तापमान

शहर	तापमान
द्रास	-14.4
केलंग	-12.0
श्रीनगर	-2.3
मनाली	1.0
पटियाला	5.5
दिल्ली	5.2
नारनौल	3.5
दतिया	5
कोलकाता	11.9
अंबिकापुर	5

(डिग्री सेल्सियस में)

जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा

जासं, जयपुर : जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों को 11 साल सात माह बाद शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा सजा सुनाएंगे। ब्लास्ट के चारों आरोपितों को बुधवार को दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई। बहस से पहले चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही न्यायाधीश ने न्यायमित्र पैकर फारूख से कहा कि शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। आप जो बहस करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं। इस पर न्यायमित्र ने चारों की सजा में रियायत देने की मांग की। सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद अब शुक्रवार शाम चार बजे सजा का ऐलान किया जाएगा।

गौरतलब है कि 13 मई 2008 को गुलाबी नगरी में आठ जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे। कोर्ट ने मुहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मुहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया है।

पार्किंग की जगह होने पर ही हो वाहन का पंजीकरण

हाई कोर्ट का आदेश ▶ सड़कों पर वाहन लगाने की नहीं दी जाए इजाजत

अदालत ने ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए ठोस नीति तैयार करने का दिया निर्देश

जेएनएन, जम्मू

ट्रैफिक की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने राज्य शासन को ठोस नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि वाहन रजिस्ट्रेशन नियमों में संशोधन करके ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें केवल उन्हीं वाहनों का पंजीकरण किया जाए, जिनके मालिक के पास गाड़ी लगाने के लिए उपयुक्त पार्किंग गैराज हो। यह नियम निजी व व्यावसायिक, दोनों वाहनों पर लागू हो।

हाई कोर्ट ने सड़कों पर वाहनों की पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की नीति तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग और शहर की सड़कों पर वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

जम्मू व श्रीनगर में ट्रैफिक समस्या के निवारण की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जस्टिस अली मुहम्मद व जस्टिस डीएस ठाकुर ने श्रीनगर शहर से उक्त नियमों की शुरुआत करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी कि वह सड़कों को पार्किंग से मुक्त करवाएं। बेंच ने साफ किया कि श्रीनगर नगर निगम या श्रीनगर विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग के चिह्नित सड़कों पर भी किसी वाहन को पार्क करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

बेंच ने पाया कि इस मामले में कोर्ट ने समय-समय पर कई दिशानिर्देश जारी किए, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। बेंच ने ट्रैफिक प्रबंधन के संदर्भ में कई आदेश दिए। वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय प्रमुख थे। साथ ही पेट्रोल और डीजल वाहनों को सीएनजी-एलपीजी में बदलने, श्रीनगर में चल रहे बीस हजार थ्री-व्हीलर को सीएनजी और एलपीजी करने, गैर पंजीकृत थ्री-व्हीलर, सूमो व बस स्टैंड हटाने या महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट पूरा करने के मामले भी अभी लंबित हैं।

बेंच ने कहा कि इतने सारे मुद्दे एक साथ जुड़ने से भी इस केस की उचित सुनवाई व निगरानी नहीं हो पाई। लिहाजा बेंच अब कुछ मुद्दों पर एक वक्त में सुनवाई करेगा।

सीएनजी के लिए निजी कंपनियों से संपर्क करने का आदेश : बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान वाहनों के पंजीकरण, सड़कों पर पार्किंग व सीएनजी-एलपीजी का मुद्दा लिया। सीएनजी-एलपीजी के मुद्दे पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन के वकील ने बेंच को बताया कि कारपोरेशन सीएनजी नहीं देती, कुछ निजी कंपनियां सीएनजी देती हैं। इस पर बेंच ने सरकार को संबंधित एजेंसियों से संपर्क करने का निर्देश दिया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। फाइल

25 साल पुराने वाहनों को हटाने पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करें परिवहन आयुक्त

बेंच ने कहा कि 17 मई 2017 को कोर्ट ने 25 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन यह रिपोर्ट भी अभी तक पेश नहीं की गई। लिहाजा अगली सुनवाई तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यह रिपोर्ट भी पेश करें। बेंच ने काजीगुंड से बनिहाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की दिशा में अब तक हुए काम की रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

ओडिशा में अब किन्नरों के जरिये बीएमसी वसूल करेगा टैक्स

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : भुवनेश्वर महानगर निगम (बीएमसी) ने वर्षों से टैक्स न देने वालों से टैक्स वसूलने का एक नया फार्मूला अपनाया है। बीएमसी ने अपना बकाया वसूलने के लिए किन्नर संगठन से करार किया है। इसके अनुसार बीएमसी टैक्स की अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं के घर पर अब किन्नरों की टोली जाएगी और बकाया वसूलने का काम करेगी। इसके एवज में उन्हें बीएमसी की तरफ से कमीशन का भुगतान किया जाएगा।

बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) श्रीमंत मिश्र और किन्नर स्वयं सहायक गुट के मध्य बुधवार को करार हुआ है। किन्नर स्वयं सहायक गुट की तरफ से ओंकार बस्ती की मेघना साहू ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के अनुसार 40 लाख तक की वसूली पर किन्नर सहायक गुट को एक फीसद धनराशि कमीशन के तौर पर दी जाएगी और अगर वसूली 40 से 60 के मध्य होती है तो कमीशन 1.5 फीसद एवं उससे अधिक होने पर वसूली का दो फीसद कमीशन के तौर पर दिया जाएगा। पहले 10 किन्नरों को इस वसूली योजना में शामिल किया जाएगा। इन्हें इस कार्य के लिए विशेष यूनीफार्म, बैच एवं परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा।

बीएमसी की ओर से इन किन्नरों को सर्वप्रथम प्रशिक्षण दिया जाएगा और बाद में बकाया टैक्स वसूली के काम में नियोजित किया जाएगा। बीएमसी डिप्टी कमिश्नर श्रीमंत मिश्र ने कहा है कि राजधानी में शताधिक लोग हैं जो होल्डिंग शुल्क नहीं दे रहे हैं। उन्हें बार बार नोटिस भेजने के बावजूद उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे में अब किन्नरों को उनके घर भेजा जाएगा।

मिड-डे मील में फिर भेदभाव पुलिस ने शांत कराया विवाद

संवाद सूत्र, गोहर

▶ हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के कशौड़ स्कूल का मामला

▶ देवता का हवाला देकर बच्चों को इकट्ठे भोजन करने से रोका

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सराज इलाके के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील परोसे जाने में जातीय भेदभाव के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब राजकीय उच्च पाठशाला कशौड़ में भेदभाव का मामला सामने आया है। यहां आठवीं कक्षा तक के बच्चों को रोल नंबर आधार पर पंक्ति में बैठाकर मिड डे मील परोसने पर सामान्य वर्ग के अभिभावकों ने आपत्ति जताई। उन्होंने देवता का हवाला देकर स्कूल प्रशासन पर अलग भोजन परोसने का दबाव बनाया है। अनुसूचित जाति वर्ग के अभिभावकों ने औट थाना में इस संबंध में शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया है।

जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर को सामान्य वर्ग के बुधराम, नीलमणि, गिरजा देवी, गोपाल, हुमा देवी व आलमी देवी स्कूल गए। वहां शिक्षकों पर दबाव बनाया कि उनके बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ मिड डे मील के दौरान पंक्ति में रोल नंबर आधार पर न बैठाया जाए। ऐसा करने से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मसला देवता से जुड़ा है। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले करीब 23 अभिभावकों ने पुलिस अधीक्षक मंडी को इस संबंध में शिकायत की है। अनुसूचित जाति वर्ग के अभिभावकों ने थाना औट के प्रभारी ललित महंत को भी 18 दिसंबर को शिकायत पत्र देकर आरोपितों के विरुद्ध एससीएसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की मांग की।

दोनों पक्षों के अभिभावकों के बीच गलतफहमी की वजह से विवाद हुआ था। अब विवाद सुलझा लिया गया है। इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को रोल नंबर आधार पर ही पंक्ति में बैठाया जाता है।
-कृष्ण चंद, एसएमसी प्रधान कशौड़ स्कूल।

शिकायत मिलने के बाद डीएसपी अनिल पटियाल व थाना प्रभारी औट को स्कूल भेजा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभिभावकों ने शिकायत वापस ले ली।
-गुरदेव शर्मा, पुलिस अधीक्षक, मंडी।

गुरुवार को डीएसपी अनिल पटियाल पुलिस टीम के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने वहां पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर दोनों पक्षों के अभिभावकों बयान दर्ज किए और उनकी काउंसिलिंग की। इसके बाद दोनों पक्ष बच्चों को रोल नंबर आधार पर पहले की तरह बैठाने पर सहमत हो गए। स्कूल में अनुसूचित जाति वर्ग के 75 व सामान्य वर्ग के आठ बच्चे हैं।

उधर, उच्च शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि मिड डे मील में भेदभाव की शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।

कुछ और गायब बच्चों के बारे में विजय से राज उगलवाएगी पुलिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

▶ बच्चा चोरी गिरोह के मास्टरमाइंड अस्पताल संचालक विजय को रिमांड पर लेगी पुलिस

▶ मां भगवती अस्पताल से बच्चों को बेचने के अवैध धंधे के भंडाफोड़ के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने शुरू की पड़ताल

बच्चा चोर गिरोह के मास्टरमाइंड विजय कुमार चौधरी से कुछ और गायब बच्चों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। अहियापुर के जीरो माइल से एक बच्चे के लापता होने का मामला इस थाने में सितंबर में दर्ज हुआ है। इस मामले में भी विजय की भूमिका संदिग्ध है। रिमांड पर लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बाबत वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने अहियापुर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

जुटाई जा रही विजय के बारे में पूरी जानकारी : एसएसपी ने कहा कि विजय के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करें। थाने में दर्ज बच्चों के लापता होने के मामले में उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करें। बताया गया है कि करीब एक दशक पहले से विजय भिखनपुर में अस्पताल का संचालन कर रहा था। उसके अवैध धंधे की भनक बहुत ही कम लोगों को थी।

इस बीच मंगलवार को भागलपुर स्टेशन पर जब उसकी सहयोगी महिला मुंगेर की कल्पना पकड़ी गई तो इस बात का पर्दाफाश हुआ कि भिखनपुर से बच्चों को चोरी कर बेचने का एक बड़ा रैकेट संचालित हो रहा है। छापे के दौरान यहां से संचालक व उसकी महिला सहयोगी (कथित पत्नी) सारिका पकड़ी गई। दोनों की निशानदेही पर भागलपुर से एक बच्चे की बरामदगी पूर्वी चंपारण के अरेराज स्थित बहादुरपुर से की गई। मामले में पकड़ी गई खरीदार शोभा चौधरी ने भी बच्चों के सौदागर की पहचान की। अहियापुर थाने में मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी पीके मंडल व अन्य अधिकारियों ने भी विजय से सघन पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और जानकारियां मिलेंगी।

आइएसआइ ड्रोन से बुलेटप्रूफ जैकेट भेजने की तैयारी में

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन

▶ खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में पाकिस्तान की साजिश की जानकारी सामने आने के बाद सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी

▶ पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट से जुड़े हैं मामले के तार, एनआइए की टीम ने आरोपित हरजीत और मनदीप के परिजनों से की पूछताछ

धुंध का फायदा उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ड्रोन के जरिये भारतीय सीमा में दोबारा हथियार भेजने की तैयारी में है। इस बार हथियारों के साथ-साथ बुलेटप्रूफ जैकेट भेजने की भी आशंका जताई गई है। सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई है कि पंजाब में क्रिसमस और नववर्ष पर माहौल बिगाड़ने के लिए हाल ही में पंजाब के कुछ गर्मख्यालियों को विदेश से फंडिंग भी हुई है। हालांकि पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

सूत्रों के अनुसार उसमान नाम के आइएसआइ एजेंट द्वारा पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों को हथियार और बुलेटप्रूफ जैकेटें भेजने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान में बैठा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख रंजीत सिंह नीटा और जर्मनी में बैठा आतंकी गुरमीत सिंह बग्गा भी लगातार आपस में संपर्क में हैं। यह भी बताया जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई के लिए नीटा द्वारा छह से 13 दिसंबर के बीच भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों के साथ संपर्क भी किया गया है।

उधर, एनआइए की टीम गुरुवार को इसी साल चार सितंबर को गांव पंडोरी गोला के खाली प्लॉट में हुए बम ब्लास्ट के मामले में आरोपित हरजीत सिंह हीरा और मनदीप सिंह के घर पहुंची। एनआइए की इस दबिश को भी उक्त मामले के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। टीम के सदस्यों ने दोनों आरोपितों के परिजनों से पूछताछ की है। बताया गया है कि इन दोनों के घरों के अलावा एनआइए की टीम ने गुरजंट सिंह जंटा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी बाबा बलवंत सिंह व रोमनदीप सिंह झब्बाल के परिजनों से भी पूछताछ की है। इस दौरान टीम के कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में रहने वाले उन लोगों के बारे में जानकारी मिलने में आसानी होगी जिनके साथ आतंकी नीटा ने पिछले दिनों संपर्क किया था।

बता दें कि गांव पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट में गांव बचड़े निवासी हरप्रीत सिंह हैप्पी, गांव कदगिल निवासी विक्रमजीत सिंह विक्की की मौत हो गई थी और गुरजंट सिंह जंटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने एक माह की जांच के दौरान सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने चोहला साहिब के समीप 22 सितंबर को चार आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अब इन दोनों मामलों की जांच एनआइए कर रही है।

जानकारी देना जरूरी नहीं : वालिया

एसपी (आइ) जगजीत सिंह वालिया ने कहा कि इस मामले से स्थानीय पुलिस का अब संबंध नहीं है। एनआइए की जांच में पुलिस सहयोग जरूर दे रही है, परंतु इस बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है। वहीं, लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस गंभीरता बरत रही है।

एनआइए ने मांगा रिमांड, अदालत ने याचिका की खारिज

जासं, मोहाली : गांव पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट मामले में वीरवार को एनआइए द्वारा इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों का रिमांड हासिल करने के लिए याचिका लगाई जिसे एनआइए अदालत में खारिज कर दिया। एनआइए आरोपित मस्सा सिंह, हरजीत सिंह, अमृतपाल सिंह और गुरजंट सिंह का आठ दिन का रिमांड मांगा था। एनआइए ने तर्क दिया कि कुछ संदिग्ध लोगों के घरों में छापामारी के दौरान टीम को कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिनके बारे में उक्त आरोपितों से पूछताछ की जानी है। जिस पर बचाव पक्ष के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित से पहले पंजाब पुलिस और एनआइए पहले ही पूछताछ कर चुकी है। एनआइए की विशेष अदालत के जज करुनेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिमांड के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया।

बढ़ता दाम

एक हफ्ते में ही दोगुने से अधिक हुई कीमत, तीस से चालीस रुपये तक बिक रहा है बाजार में, बारिश से बिगड़े हालात, आवक घटने से चढ़े भाव

प्याज के रुलाने के बाद अब आलू भी खा रहा है भाव

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

प्याज तो लोगों को रुला ही रहा था, अब आलू भी भाव खाने लगा है। आलम यह है कि पिछले एक सप्ताह में ही आलू की कीमतें दो गुने से ऊपर निकल गई हैं। कई राज्यों में नया आलू 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। कीमतें चढ़ने की वजह पिछले दिनों हुई बारिश बताई जा रही है। ऐसे में आलू की आवक प्रभावित हुई है, जिससे भाव चढ़ गए हैं।

एक सप्ताह पहले तक दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आलू की कीमत 12 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक थी। अब दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कीमत जहां करीब 30 रुपये प्रति किलोग्राम हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह सबसे महंगा बिक रहा है। यहां कीमतें 40 रुपये के पार पहुंच गई हैं। यहां कीमतों में आई तेजी की वजह दक्षिणी राज्यों में मांग बढ़ने के साथ ही पंजाब से आपूर्ति में कमी आना बताया जा रहा है। आपूर्ति हिमाचल प्रदेश में ही प्रभावित नहीं हुई है, उत्तर भारत के उक्त राज्यों के बाजार में भी आवक घटी है। गत दिनों हुई बेमौसम बारिश इसकी वजह बताई जा रही है। बारिश के कारण खेतों से आलू निकालने में किसान को परेशानी हो रही है। दूसरा, बरसात से फसल को भी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतें 100 रुपये के पार चल रही हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं के लिए यह दोहरी मार के समान है।

उत्तर प्रदेश-बंगाल अव्वल

आलू का उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश और बंगाल सबसे अव्वल राज्य हैं। ज्यादातर राज्यों में इन्हीं दो प्रदेशों से सबसे ज्यादा सप्लाई की जाती है। पिछले दिनों हुई बारिश से दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जिसका असर फसल पर पड़ा है।

आलू तोलता एक सब्जी विक्रेता (फाइल फोटो)।

कहां क्या है कीमत (रुपये प्रति किलो)

राज्य	कीमत (पहले)	(अब)
दिल्ली-एनसीआर	12 से 15	30-35
झारखंड	12 से 15	30 से 32
हिमाचल प्रदेश	15 से 20	40 से 45
छत्तीसगढ़	12 से 15	30 से 35
मध्य प्रदेश	15 से 20	30 से 35
पंजाब	12 से 15	30 से 35
उत्तर प्रदेश	10 से 15	30 से 35

पुराना स्टॉक खत्म ज्यादातर मंडियों में नए आलू की ही आवक हो रही है, क्योंकि पुराना स्टॉक लगभग समाप्त हो गया है। कीमतें बढ़ने की यह भी एक वजह बताई जा रही है। ऐसे में नए आलू की आवक बढ़ने तक कीमतों में गिरावट की गुंजाइश कम है।

सलमान खान को जोधपुर कोर्ट में होना होगा पेश

संवाद सूत्र, जोधपुर

▶ काले हिरण शिकार मामले में स्थायी हाजिरी माफी की राहत नहीं

▶ पूछा-कहां है मुलजिम, सात मार्च को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल, उनको काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की जिला व सत्र अदालत से स्थायी हाजिरी माफी में राहत नहीं मिली है।

गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में काले हिरण शिकार मामले में सलमान की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी ने पूछा कि मुल्जिम कहां है? इस पर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि आप आदेश देंगे तब हाजिर कर देंगे। इस पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि लंबे अरसे से सलमान खान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगली सुनवाई सात मार्च को वे अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित रहें। कोर्ट ने सलमान की तरफ से पेश स्थायी हाजरी माफी की अर्जी पर भी कोई फैसला नहीं दिया।

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उन्होंने जिला व सत्र न्यायालय में अपील की है। इसी की सुनवाई के दौरान उन्होंने स्थायी हाजिरी माफी की अर्जी दायर की थी।

1998 का है शिकार मामला : 1998 में जोधपुर के निकट कांकाणी गांव की सरहद में काले हिरणों के शिकार मामले में इसी साल कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपियों फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व स्थानीय दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

दैनिक जागरण

उचित योजना के अभाव में लक्ष्य प्राप्त करना लगभग असंभव है

राजनीति का शरारती रूप

अब इस पर कोई संशय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के हिंसक विरोध के पीछे अज्ञानता भरे अंदेशे के साथ ही शरारत भरे राजनीतिक दुष्प्रचार की भी एक बड़ी भूमिका है। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों और किस्म-किस्म के गैर राजनीतिक संगठनों ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है, मानो सरकार ने अनर्थ कर दिया हो। हैरानी यह है कि ऐसा माहौल खड़ाकर अराजकता को हवा देने का काम वे दल भी कर रहे हैं जो एक समय नागरिकता कानून में वैसी ही व्यवस्था चाह रहे थे जैसे सरकार ने की और जिस पर संसद ने विधिवत मुहर भी लगाई। नागरिकता कानून के खिलाफ आज आग उगल रही कांग्रेस बड़ी चतुराई से यह भूलना पसंद कर रही है कि वाजपेयी सरकार के समय राज्यसभा में बतौर नेता विपक्ष मनमोहन सिंह बांग्लादेश जैसे देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने में नरमी बरतने की जरूरत जता रहे थे। उन्होंने इन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना देश की नैतिक जिम्मेदारी भी बताया था। अब जब मोदी सरकार ने इसी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर दिया तो कांग्रेस समेत अन्य दल अराजकता का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। कायदे से तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने पर इस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उससे पल्ला झाड़ना ही बेहतर समझा और वह भी तब जब असम से राज्यसभा सदस्य होने के नाते इससे भली तरह परिचित थे कि पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में पड़ोस से आए अल्पसंख्यक कितनी दयनीय दशा में रह रहे हैं।

यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते समय माकपा नेता प्रकाश करात ने उन्हें चिट्ठी लिखकर नागरिकता कानून को इस तरह संशोधित करने की मांग की थी कि बांग्लादेश से आए और परेशान हो रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सके। इस चिट्ठी में उन्होंने मनमोहन सिंह को उनके उस संबोधन की याद भी दिलाई थी जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। आज माकपा और अन्य दल बिना शर्म-संकोच नागरिकता कानून को काला कानून में बताने में लगे हुए हैं। वास्तव में इसी शरारतपूर्ण राजनीति के कारण नागरिकता कानून का हिंसक विरोध हो रहा है। यह भी एक किस्म की शरारत ही है कि शांतिपूर्ण विरोध के बहाने अशांति और अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हिंसक घटनाएं यही रेखांकित कर रही हैं कि अराजकता और उन्माद फैलाने का काम किस सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए हमारे नेता किस हद तक गिरने को तैयार हैं, इसका ही शर्मनाक उदाहरण है ममता बनर्जी की जनमत संग्रह संबंधी मांग।

नशे के खिलाफ मुहिम

हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की बरामदगी बढ़ना चिंतनीय है। हर रोज नशीले पदार्थ बरामद हो रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशा माफिया ने जाल बिछाया है। कई युवाओं का नशे की गर्त में फंसना चिंतनीय है। जिस उम्र में युवा करियर चमकाने के लिए संघर्ष करते दिखने चाहिए, उस दौरान उनका नशे की ओर झुकाव सही नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मगर जरूरत उनमें तेजी लाए जाने की है। जरूरत इस बात की है कि नशा माफिया पर लगाम कसी जाए। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर मामलों में वही लोग पकड़े जाते हैं जिन्हें नशीले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए थोड़े से पैसों का लालच दिया जाता है। ऐसे मामलों में मुख्य सरगना कम ही पकड़ में आते हैं। इसलिए नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में मुख्य सरगना को दबोचने के प्रयास किए जाने चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि चंद पैसों के लिए तस्करी में शामिल होना सही नहीं है। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर सजा के अलावा लोगों को सामाजिक रूप से भी तिरस्कार सहना पड़ता है। उनके परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। असल में नशा नाश की जड़ है। इसलिए समझदारी इसी में है कि नशे से दूरी बनाकर रखी जाए। युवाओं को चाहिए कि वे नशे से दूर रहकर अपना करियर संवारें। अभिभावकों का भी फर्ज है कि यदि उनका बच्चा नशे के चंगुल में फंस गया है तो उसे डांटे, नहीं बल्कि उसका उपचार करवाएं। प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के अभियान को और तेज किया जाना चाहिए। विशेषकर शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जाना चाहिए। नशीले पदार्थों का खात्मा एकजुटता के साथ ही किया जा सकता है। इस दिशा में सुखद खबर यह है कि उत्तर भारत के राज्य अब नशे के काले कारोबार के खिलाफ सामूहिक वार करेंगे। इस दिशा में शिमला में सात राज्यों के पुलिस अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई है। इस बैठक में तस्करों के खिलाफ और सख्ती से निपटने की पुख्ता रणनीति बनाने के अलावा कार्ययोजना तैयार की गई है। इस समन्वय से सूचना और सूचना से सजा तक का रास्ता आसान होने की उम्मीद बंधी है।

एकजुटता से ही नशीले पदार्थों का खात्मा हो सकता है। उत्तर भारत के राज्य यदि इस भाव से नशीले पदार्थों पर वार करेंगे तो इस बुराई को मात दी जा सकेगी

पाकिस्तान में भूचाल लाने वाला फैसला

विवेक काटजू

बाजवा के सेवा विस्तार पर अड़ंगा लगाने के बाद मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाकर न्यायपालिका ने पाकिस्तानी फौज को सख्त संदेश दिए हैं

पाकिस्तान के इतिहास में 17 दिसंबर की तारीख एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज की जाएगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति एवं सेनाप्रमुख परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई। एक जज ने तो यहां तक कहा कि यदि मुशर्रफ मृत पाए जाएं तब भी उनके शव को घसीटकर इस्लामाबाद के चौक पर तीन दिन के लिए सूली पर चढ़ाया जाए। हालांकि उनके साथी जज इससे सहमत नहीं थे। यह टिप्पणी पाकिस्तानी सेना को बहुत चुभने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान की ताकतवर सेना और उसके पिट्ठू माने जाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने मुशर्रफ को बचाने के लिए सारी तिकड़में आजमाईं, लेकिन वे अदालती फैसले को रोकने में नाकाम रहे। तीन न्यायाधीशों द्वारा 2-1 के बहुमत से दिए गए इस फैसले की धमक बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। इससे पाकिस्तान की राजनीति, समाज और सेना में भूचाल सा आ गया है।

मुशर्रफ 2016 से देश के बाहर हैं और आजकल दुबई में गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं। मुशर्रफ को झटका देने वाले इस फैसले का आधार पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद छह और उसके तहत बने कानून हैं। उनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान के संविधान को दरकिनार करने की कोशिश भी करता है तो वह देशद्रोह का दोषी माना जाएगा। इसे 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पहल पर बनाए गए पाकिस्तानी संविधान में शामिल किया गया था। इसमें दोषी पाए जाने पर उम्रकैद या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। भुट्टो ने इसे इस मंशा के साथ लागू किया था ताकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख देश की हुकूमत पर काबिज न हो सकें। उनका मकसद था कि अयूब खान और याह्या खान जैसे फौजी तानाशाह फिर से न उभरें, लेकिन विडंबना यह रही कि उसके शिकार वह स्वयं हुए। इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त जनरल जिया उल हक ने न केवल उन्हें सत्ता से बेदखल किया, बल्कि उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस वाकये के बीस साल बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्तापलट कर स्वयं सत्ता हथिया ली। जिया उल हक और फिर परवेज मुशर्रफ द्वारा किए गए सैन्य तख्तापलट को पाकिस्तान की न्यायपालिका से पूर्ण सहमति मिली।

जिस मामले में मुशर्रफ को सजा मिली है उसकी कड़ियां 2007 से जुड़ी हैं जब वह राष्ट्रपति के साथ-साथ सेना प्रमुख भी थे। तब राजनीतिक वर्ग पर शिकंजा कसने के बाद मुशर्रफ ने न्यायपालिका पर भी दबिश बढ़ा दी थी। इसी सिलसिले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बर्खास्त कर नजरबंद करा दिया था। पाकिस्तान की न्यायिक बिरादरी ने इसका भारी विरोध किया। नवंबर, 2007 में मुशर्रफ ने संविधान को निलंबित कर दिया। छह हफ्ते बाद संविधान की फिर बहाली हुई। इस अवधि में उन्होंने सेना प्रमुख का पद छोड़ा और एक सिविलियन राष्ट्रपति बने। आठ महीने बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद भी छोड़ दिया। उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले ही मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने संविधान के निलंबन को अवैध करार दिया। यही पहलू इस मुकदमे का आधार बना।

जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, इस मामले में पाकिस्तानी फौज ने बेहद तल्ख प्रतिक्रिया जताई। उसने इस फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। फौज का यह आक्रोश बेवजह नहीं। वह मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बाजवा के सेवा विस्तार में अदालती अवरोध को लेकर पहले ही तिलमिलाई हुई है। उनसे जुड़े फैसले में भी अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पाकिस्तानी संसद ने छह महीने में उनकी नियुक्ति को लेकर उचित कानून नहीं बनाया तो उनका सेवा विस्तार अटक सकता है। स्वाभाविक है कि पाकिस्तानी सेना इन अदालती फैसलों को अपनी साख से जोड़कर देख रही है। पाकिस्तानी सेना श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त है। उसे यह मुगालता है कि केवल वही पाकिस्तानी सीमाओं एवं वैचारिक बुनियाद को महफूज रख सकती है। पाकिस्तानी नेताओं के बारे में उसकी धारणा है कि वे कमजोर, अक्षम और भ्रष्ट हैं जो राष्ट्रीय हितों का संरक्षण नहीं कर सकते। नौकरशाही को भी वह नकारा और स्वार्थी समझती है। उसकी नजर में केवल वही एकमात्र ऐसा पवित्र संगठन है जिसे देश और जनता की फिक्र है और जिसका दामन भ्रष्टाचार से बचा है। राष्ट्र की स्वयंभू संरक्षक मानते हुए वह कानून और परंपराओं को तोड़ने से भी गुरेज नहीं करती। इसी कारण पाकिस्तान का इतिहास सेना की कारगुजारियों से भरा है।

अवधेश राजपूत

हालांकि यदाकदा पाकिस्तानी न्यायपालिका ने सेना को असहज करने वाले फैसले भी सुनाए, परंतु यह तभी हुआ जब न्यायपालिका के शीर्ष पर सख्तमिजाज और विधि के लिए समर्पित न्यायाधीश मौजूद रहे हों। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में लापता लोगों के मामले में पाकिस्तानी न्यायपालिका ने सक्रियता के साथ सख्ती दिखाई। कुछ मामलों में तो सैन्य अधिकारियों को फटकार तक लगी, लेकिन सेना के शीर्ष नेतृत्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बलूचिस्तान में उसकी दमनकारी नीतियां यथावत जारी रहीं। इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना ने न्यायपालिका को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब एक पूर्व सेनाध्यक्ष को सजाए मौत और मौजूदा सैन्य मुखिया के सेवा विस्तार पर लटकी तलवार से उसका खीझना स्वाभाविक है।

पाकिस्तानी फौज न्यायपालिका को उसकी हैसियत जरूर दिखाना चाहेगी, पर फिलहाल उसके लिए ऐसा संभव नहीं दिखता। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से दो-चार है। उसकी अंतरराष्ट्रीय साख तार-तार है। मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर भी उसकी चुनौती और बढ़ा दी है। ऐसे में फौज कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि वहां लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बलि दी जा रही है। वह सार्वजनिक रूप से अदालत को पूर्णतः बेइज्जत करने का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है।

सवाल उठता है कि आगे क्या? इसमें संदेह नहीं कि फौज इमरान सरकार के कंधे पर बंदूक रख अपने हित साधेगी। इसमें पहला काम तो बाजवा के सेवा विस्तार के लिए कानून बनाना होगा। बाजवा भी कोई बीच का रास्ता निकालने की सोचेंगे जिससे उनका और फौज का स्वाभिमान कायम रह सके। जहां तक मुशर्रफ के मामले का सवाल है तो ऊपरी अदालतों में इस फैसले को पलटवाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। वैसे भी इस फैसले को अमल में लाना लगभग असंभव है, लेकिन देखना है कि मुशर्रफ देशद्रोह के दाग से मुक्त होते हैं या नहीं? जो भी हो, न्यायपालिका के जरिये फौज को लगे लगातार दो झटकों के बावजूद ऐसे कोई आसार नहीं कि पाक की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव आएगा। भारत नीति फौज अपने हाथ में ही रखेगी। यह छोड़ना उसके लिए नामुमकिन है।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)
response@jagran.com

कुप्रचार का शिकार नागरिकता कानून

भूपेंद्र यादव

नागरिकता कानून लाकर तो सरकार ने वही किया है जिसे करने की मांग मनमोहन सिंह ने 2003 में की थी

संसद के शीतकालीन सत्र में संसद से पारित किए गए विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन विधेयक था, जो अब कानून बन चुका है। किसी भी देश के लिए नागरिकता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न होता है। जब सरकार किसी व्यक्ति को देश के नागरिक के रूप में मान्यता देती है तो वह नागरिक की सुरक्षा और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करती है, ताकि वह देश के नागरिक के रूप में गरिमापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। संसद से पारित इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समूहों-हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के तहत दिए गए अधिकारों में से कुछ सभी को दिए गए हैं, जबकि कुछ केवल देश के नागरिकों को दिए गए हैं। यह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश में है कि कुछ अधिकार सभी के लिए होते हैं और कुछ अधिकार केवल वहां के नागरिकों के लिए होते हैं। इस कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, सरकार को इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा, क्या यह कानून लोगों को नागरिकता प्रदान करने में धर्म के आधार पर भेदभाव करता है? तीसरा, क्या सरकार द्वारा विधेयक लाने की पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक वैधता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के पहले यह समझना होगा कि देश का विभाजन 1947 में धार्मिक आधार पर हुआ। 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके पाकिस्तानी समकक्ष लियाकत अली खान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह दोनों देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित था। नेहरू-लियाकत समझौते पर पाकिस्तान ने कभी अमल नहीं किया। इस कारण बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक पाकिस्तान और बांग्लादेश (उस दौर के पूर्वी पाकिस्तान) से भारत आए। इनके भारत आने का मुख्य कारण धार्मिक उत्पीड़न और उनकी धार्मिक पहचान का खतरे में होना था। इस गंभीर समस्या पर सिर्फ वर्तमान सरकार का ध्यान गया।

2003 से 2014 के बीच संप्रग सरकार ने संसद में अनेक बार यह बात दोहराई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और इसलिए वे भारत आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2003 में जब केंद्र में राजग सरकार थी तब मनमोहन सिंह ने इन पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता

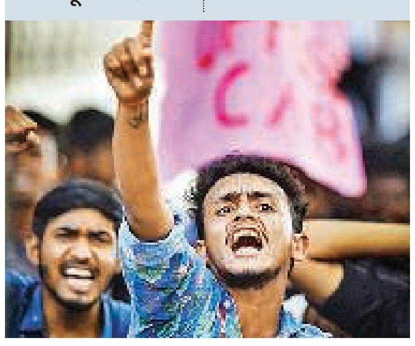

देने का मुद्दा उठाया था। माकपा नेता प्रकाश करात ने 2003 में मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर एक पत्र लिखा। कुल मिलाकर लंबे समय से चली आ रही इस समस्या की तरफ लगभग हर दल के नेताओं का ध्यान गया। सभी ने इस समस्या को एक गंभीर चिंता के रूप में जाहिर किया, किंतु दुर्भाग्य से समस्या को जानते और स्वीकारते हुए भी कांग्रेस ने ठोस समाधान निकालने की कभी कोशिश नहीं की। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लाकर इस समस्या का समाधान किया है।

जहां तक इस विधेयक की संवैधानिक वैधता का प्रश्न है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है। विपक्ष द्वारा इस विधेयक के संबंध में उठाया गया मुख्य मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में है। वे तर्क दे रहे हैं कि पड़ोसी देशों के कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देकर सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। सच्चाई आरोपों से परे है। यदि एक कल्याणकारी सरकार किसी उपयुक्त आधार पर लोगों को वर्गीकृत करती है और फिर समूह के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्रदान करती है तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 के तहत मान्य है। यह लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए एक वर्ग को चिन्हित करने के समान है। यदि देश के दस प्रतिशत लोगों को गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया गया है तो यह नीति देश के करदाताओं के खिलाफ नहीं है। इसी तरह ओबीसी मुस्लिमों को दिया जाने वाला आरक्षण उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ नहीं है।

टीएमए पई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक और भाषाई आधार पर लोगों के वर्गीकरण को संविधानसम्मत स्वीकृत किया था। इसलिए विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे ऐसे मुद्दे निराधार हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह कानून पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ है। यह भी सच नहीं है। सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी 'इनर लाइन परमिट क्षेत्रों' को कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। साथ ही पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को भी इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार ने इस कानून के तहत लोगों को नागरिकता देने के लिए 31 दिसंबर, 2014 की तिथि निर्धारित की है। यानी नागरिकता प्रदान करने के लिए नए प्रवासियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस कानून के तहत केवल उन्हें नागरिकता दी जाएगी जो निर्धारित तिथि या उससे पहले प्रवेश कर चुके हैं। बाहर से आए लोगों को विशेष परिस्थिति में नागरिकता पहले भी दी जाती रही है। 2003 में राजग सरकार और यहां तक कि 2013 में संप्रग सरकार ने सर्कुलर के माध्यम से पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की थी। इसलिए धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर लोगों को नागरिकता देना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। यह कानून लाकर तो सरकार ने लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी हल निकाला है। बिना किसी अधिकार के अनिश्चितता और असुरक्षा का जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को नागरिकता प्रदान करके भारत सरकार ने मानव अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों द्वारा जिस ढंग से नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रामक अप-प्रचार करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 से भारत के किसी भी धर्म के नागरिक को कोई खतरा नहीं है। इस कानून से किसी की नागरिकता पर कोई खतरा होने का सवाल ही नहीं है।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मानवीय गुण

इस दौर में मानव का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसका कारण तमाम तरह की व्याधियों से घिरा होना है। अधिकांश व्याधियों का संबंध मानव मन एवं मस्तिष्क से जुड़ा है। वास्तव में मानव शरीर सद्गुण, रजोगुण एवं तमोगुण से मिलकर बना है। इनकी अलग-अलग विशेषताएं हैं। सद्गुणों द्वारा मनुष्य में ईश्वर के स्वरूप की पहचान रहती है। इससे वह प्रायः प्रसन्न रहता है। रजोगुण की प्रधानता में हर्ष तथा भय साथ रहते हैं। वहीं तमोगुण में मनुष्य पशु के समान केवल स्वयं के स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। इससे वह मानसिक रूप से एकाकी होकर चहुंओर विषैला माहौल पाता है। सनातन धर्म के अनुसार वर्तमान काल को कलयुग कहा जाता है। इसमें मानव में तमो ज्यादा, रजो थोड़ा तथा सद्गुणों का मुख्य रूप से अभाव ही होता है। मनुष्य तत्वज्ञान तथा योग के द्वारा तमो और रजो गुणों के प्रभावों से मुक्त होकर सद्गुण अपनाकर किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है।

इन सद्गुणों कों पतंजलि के अष्टांग योग एवं ईश्वर भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर भक्ति सतयुग में योग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा द्वारा प्राप्त की जा सकती है, परंतु यही ईश्वर भक्ति कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए कलयुग के स्वरूप को समझते हुए रामचरितमानस में कहा गया है कि इस युग में मानसिक पुण्य तो होते हैं, परंतु मानसिक पाप नहीं होते। ऐसा इसलिए, क्योंकि सभी जगह ऐसा ही माहौल है जहां सर्वत्र पाप एवं अप्रिय दृश्य उत्पन्न होते रहते हैं। इनके कारण कभी-कभी बुरे विचार मनुष्य को घेर लेते हैं जिन्हें वह पाप समझकर अपराध बोध में गिरा रहता है। ऐसी स्थिति में वह ईश्वर भक्ति तथा विवेक से इन मानसिक पापों से निवृत्त होकर सकारात्मक विचारों से स्वयं को ऊर्जावान बना सकता है। संभवतः इसीलिए कलयुग को सबसे अलग काल माना जाता है, क्योंकि इसमें वह थोड़े से प्रयास से ही अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए मनुष्य को यह राह अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए।

कर्नल शिवदान सिंह

असामाजिक होता सोशल मीडिया

अंशुमाली रस्तोगी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि अनाप-शनाप लिखकर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करें

हमारा देश आखिर किस दिशा में जा रहा है? हिंसा और अविश्वास का भाव हावी है। परस्पर प्रेम और भाईचारे का तानाबाना टूटता जा रहा है। यह अब कैसे और किस तरीके से जुड़ेगा, यह कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया को भी इसके लिए कुछ तक हद दोषी माना जा सकता है जहां अफवाहों को तूल दिया जा रहा है। देश में बोलने-लिखने की आजादी है तो क्या उसका इस तरह बेजा फायदा उठाया जाएगा। हमें इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा।

क्या सोशल मीडिया पर हम सब यही करने के लिए आए थे! यह मंच हिंसा और भावनाएं भड़काने के लिए तो नहीं था! इसके रूप में हमें एक जरिया मिला था अपनों से जुड़े रहने का। दुनिया को खुद से जोड़े रखने का। दूरियों को कम करने का। अपनी बात को अपने तक ही सीमित न रख, पूरी दुनिया में फैलाने का। नए रिश्ते कायम कर उन्हें नया नाम, नई पहचान देने का। अपने विचारों को लिखने और दूसरे के विचारों को पढ़ने का। तर्कपूर्ण बहस करने का। कुछ अच्छा पढ़ने का, किंतु हमने तो इस खूबसूरत माध्यम को अपनी कुत्सित राजनीति और सांप्रदायिक सोच से नष्ट कर डाला। जो सोशल मीडिया पर व्याप्त इन मूर्खताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने इसे त्याग दिया और कुछ ऐसा करने की तैयारी में हैं। उनके पास आखिर क्या विकल्प है?

कोई भी संवेदनशील व्यक्ति किसी भी तरह की हिंसा और उपद्रव को सहन और उसका समर्थन नहीं करेगा। अपने ही देश, समाज और नागरिकों को उपद्रव की आग में जलते देखना किसे अच्छा लगेगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से पहले हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही अपने उन हमदर्दों की हकीकत भी समझें जो अपने हितों के लिए अक्सर हमारा इस्तेमाल करते हैं।

हर मसले को 'राजनीतिक रंग' देने की हमने कितनी खराब आदत बना ली है। नेताओं का तो काम ही राजनीति करना है, लेकिन हमें तो कम से कम उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचना चाहिए। नेता तो राजनीतिक दांव खेलकर अपने हित साधकर निकल जाएंगे, मगर हम और आप कभी धर्म तो कभी जाति की दीवारों में बंटते चले जाएंगे। हमें यह नहीं भूलना होगा कि हमारी पहचान गांधी और विवेकानंद से होती है, हिटलर या मुसोलिनी से नहीं। हमें उन क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों के पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए इतने यत्न किए।

ऐसे में हमारा दायित्व है कि अपने देश में ऐसा कुछ भी गलत न होने दें कि पड़ोसी मुल्क हम पर हंसे। हमें बदनाम करे। हालांकि हम ऐसा कुछ भी देश के संग कभी होने नहीं देंगे। निरंतर फैल रही हिंसा को हमें ही रोकना होगा। बड़े लोकतांत्रिक देशों में हमारा नाम आता है, कम से कम उसी की लाज रख लें। यह मुल्क हम सब का है। सबकी साझा विरासत है। इस विरासत को बचाना होगा। हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कम से कम सोशल मीडिया के सार्थक उपयोग से हम सौहार्द की बुनियाद तो रख ही सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

नागरिकता कानून को समझने की दरकार

अज्ञानता से उपजा हिंसक विरोध शीर्षक लेख के तहत रामिश सिद्दीकी ने नागरिकता कानून के बारे में यह बताने की कोशिश की है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है और मुस्लिमों द्वारा इसका विरोध करना उचित नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के बारे में कहा था, 'मेरा विश्वास युवा शक्ति पर है। इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे, जो अपने पराक्रम से विश्व को बदल देंगे।' युवा वर्ग का देश के विकास, देश और समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्र और समाज को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए युवाओं की सोच अहम भूमिका निभाती है। इस बात का गवाह तो इतिहास भी है, लेकिन यह तभी संभव है जब देश में रहने वाले हर धर्म के युवाओं की सोच अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अनुकूल हो। नागरिकता कानून पर जो हिंसक विरोध उपजा इसका कारण अज्ञानता के साथ-साथ इस कानून पर होने वाली संकीर्ण राजनीति और मुस्लिम समाज के कुछेक धर्म के ठेकेदारों की अपनी झूठी शान भी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि यह कानून न तो मुस्लिम समाज के लिए और न ही अन्य किसी धर्म के लोगों के खिलाफ है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए मोदी सरकार को इस कानून की कमियों को दूर करने के उपाय अपनी हठधर्मिता को छोड़कर करने चाहिए, ताकि इससे देश को कोई नुकसान न हो। देश में प्रत्येक धर्म के लोगों को संकीर्ण राजनीति से हमेशा बचकर रहना चाहिए, धर्म-संप्रदाय पर राजनीति करने वाला का मकसद हमेशा अपना वोट बैंक ही होता है। इस कानून का विरोध करने वालों को इसका भान अवश्य होना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

विरोध के पीछे राजनीति

नागरिकता संशोधन कानून का किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। यह बात इस्लामिक मामलों के जानकार रामिश सिद्दीकी ने अपने आलेख में मुस्लिम समाज को समझाने की कोशिश की है। बुधवार को जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी यही बात कही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कायदे में इस विरोध के पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं, जिनकी जमीन खिसक चुकी है। वे इसी बहाने स्वयं को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। असम से तो खबर आ रही है कि कुछ उग्रवादी व कट्टरपंथी संगठन आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन को हिंसक बना रहे हैं। दिल्ली में भी कई मुस्लिम नेताओं ने प्रदर्शन में भाषण दिए, लेकिन उनका दावा है कि उस प्रदर्शन में हिंसा जैसी कोई बात नहीं थी, फिर हिंसा कौन कर रहा है? जाहिर है कुछ गलत लोग इसमें प्रवेश कर गए हैं, वे आंदोलन के जरिये अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले नागरिकता कानून के प्रावधान को पढ़ना चाहिए। किसी की कही बात पर उबल पड़ने से बेहतर है खुद इसकी सही जानकारी हासिल करें। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह पाकिस्तान व बांग्लादेश के उन नागरिकों को भी नागरिकता का अधिकार देता है जो बहुत पहले यहां आकर बस गए हैं। यह कानून केवल भविष्य में किसी घुसपैठ को रोकने के लिए है तो इसमें बुराई क्या है। अमेरिका जैसा देश भी अपने यहां किसी को आसानी से नहीं आने देता है। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं और उसने इस मामले में सुनवाई करना स्वीकार भी कर लिया है। इसके बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है।

डा. शोभा भारद्वाज, दिल्ली

सुधार के लिए स्वयं करनी होगी पहल

अगर देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ही ऐसे लोगों को टिकट देंगी जिनके विरुद्ध दुष्कर्म के मुकदमे चल रहे हैं तो उनका कोई हक नहीं बनता कि वे किसी भी दुष्कर्म की घटना का विरोध करें। उनकी खुद की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इससे सिर्फ एक बात साबित होती है कि वे सब राजनेता, जो संसद और संसद के बाहर आक्रोश जाहिर कर रहे थे, उनका विरोध सिर्फ घड़ियाली आंसुओं जैसा ही है। यह भी सर्वविदित है कि केवल मीडिया के दबाव के कारण ही भाजपा को अपने उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। जब तक इन पार्टियों की महिला नेता अपने दलों पर दबाव नहीं बनाएंगी तब तक बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

211 फर्जी मुठभेड़ होने की शिकायतें मिली थीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जनवरी 2015 से लेकर 20 मार्च 2019 के बीच। इस दौरान सबसे अधिक ऐसी शिकायतें आंध्र प्रदेश से मिलीं।

आजकल

हिंसक विरोध के पीछे सुनियोजित साजिश

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैल जाना, इस बात की ताकीद करता है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां देश को अशांत करने पर तुली हुई हैं। राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि किसी भी मुस्लिम परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से यह कानून उनके विरोध में नहीं है। ऐसे में विरोध-प्रदर्शन अत्यंत ही दुखद और चिंताजनक है

श्रीनिवास
राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री, एबीवीपी

नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में गुरुवार को एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। वहां भीड़ में अधिकांश छात्र नजर आ रहे थे। कम उम्र के छात्रों का हिंसा में शामिल होना इस बात की पहचान है कि उनके दिमाग में जहर उड़ेला जा रहा है। चंद लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनकी मासूमियत का गलत प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के जामिया मिल्लिया के बवाल में पाया गया कि कैंपस के भीतर असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर पत्थर फेंके गए और सरकारी संपत्ति को तहस नहस किया गया। कुछ विधायकों ने भी हिंसा को बढ़ाने की पहल की। इस बीच स्वयं को लिबरल विचार के अनेक ठेकेदारों ने देश के विरोध में आंदोलन करने की आम जनता से अपील की है। अलीगढ़ और जामिया में छात्रों ने जिस तरीके से कानून हाथ में लिया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वह एक अपराध है।

इस कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर के लोगों को भी बरगलाया गया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते असम गण परिषद के साथ जो असम समझौता हुआ था उसमें मुद्दे क्या थे? जब इस सरकार ने सबके हित को ध्यान में रखते हुए एनआरसी को लागू किया तो उस पर बवाल मचा। उसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक जब कानून बन गया तो उसके माध्यम से धार्मिक विद्वेष फैला कर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद आंदोलन की अगुआई की है। इससे असामाजिक तत्वों को बल मिला और वे देश की व्यवस्था को चुनौती देने लगे। यही दिल्ली के जामिया मिल्लिया में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाकों में सामाजिक सौहार्द तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

अजीब संयोग और दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने मुस्लिम समुदाय की बुनियादी कमियों और दुर्गुणों को दूर कर उनको मजबूत बनाने की कोशिश की है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो उनके कुनबे के बल पर सत्ता में आना चाहती हैं, सामाजिक ताने-बाने को तोड़कर देश को राजनीतिक रूप से अस्थिर करना चाहती हैं, लेकिन वे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देश उनकी दोहरी राजनीति और मौकापरस्ती को समझ चुका है। देश सच और अफवाह को भी जानता है। यह केवल राष्ट्र विरोधी शक्तियों का जमघट है जिनकी तादाद बहुत अधिक नहीं है। यहां कुछ बातें स्पष्ट दिख रही हैं। कैसे कैंपस की राजनीति में जहर घोला जा रहा है।

देखा जाए तो छात्र देश का भावी कर्णधार है। पहले जेएनयू में फीस को लेकर कैंपस से लेकर संसद तक हंगामा किया गया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया, फिर नागरिकता कानून को लेकर जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ में बवाल मचाने की कोशिश की जा रही है। फिर इनको एक सूत्र में पिरोकर देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की साजिश रची जा रही है जिसमें कांग्रेस जैसी कई पार्टियां हैं जिनकी दुकानें मुस्लिम राजनीति की वोट बैंक पर चलती थीं।

इस तरह की अव्यवस्था फैलाकर देशव्यापी अराजकता की स्थिति को पैदा करने वाले और कोई नहीं, बल्कि शहरी नक्सली ही हैं। कभी मॉब लिंचिंग को लेकर, तो कभी कैंपस में शुल्क वृद्धि को लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। इस कुत्सित मानसिकता के पीछे वही शक्तियां प्रभावी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं। शहरी नक्सलियों का मकसद कैंपस के छात्रों को उत्तेजित कर देश को विकास के रास्ते से नीचे धकेलना है। भारत विरोधी ताकतों की एक मजबूत शृंखला है। कैंपस से लेकर संसद तक इनके तार जुड़े हुए हैं। उदारवादी विचारधारा के नाम पर देश के राजनीतिक ढांचे को तोड़ना इनका शगल है। जिस तरीके से एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक पर कुछ दलों ने विरोध की राजनीति की और धर्म को अपना आधार बनाया, वह अपने आप में भारत विरोध की ही तस्वीर पेश करता है। ये राजनीतिक शक्तियां अपने आप को लिबरल थॉट की मानती हैं यानी उदारवादी सोच देश को तोड़ने और कमजोर करने के लिए बनाया गया है। संसद में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और कैंपस में उनके बुद्धिजीवी मसीहा हैं, जिनकी सोच कश्मीर को पाकिस्तान सौंपने की है और राष्ट्र के सपने को खंडित करने की है।

शहरी नक्सलवाद पैदा कैसे होते हैं? इस बात को समझना अब आम जनता के लिए मुश्किल नहीं है। देश में छात्रों की आड़ में राजनीति को मानवीय शक्ल देने का ढोंग उदारवादी बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाता है। देश के राष्ट्रीय खजाने से विदेशों में मौज करने वाली यह जमात विदेशों में अपने ही देश को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचते हैं और वहां पर अपनी शान बटोरते हैं। देश ऐसे लोगों को पहचान चुका है। लिबरल थॉट के बुद्धिजीवी जिनकी तादाद बहुत नहीं है, लेकिन उनका विस्तार जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में जरूर है। इनकी ठेकेदारी अन्य संस्थाओं में भी चलती है। जेएनयू के अनेक अध्यापक भारतीय रकम पर विदेशों में जाकर अपने ही देश की आलोचना को अपनी बौद्धिक संपदा मानते थे। प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय ने गुजरात दंगों के बाद वाशिंगटन में वर्ष 2002 में वहां की सरकारी समिति 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' के सामने भारत सरकार के खिलाफ गवाही दी। इस कमीशन की सुनवाई का उद्देश्य अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा था। इसी प्रकार के कई बुद्धिजीवियों का अड्डा विदेशों के विश्वविद्यालयों में सक्रिय है जो भारत विरोधी मुहिम में शामिल हैं। उसमें से एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक खेमा है जो स्टीम फॉर्मर के द्वारा चलाया जाता है। इसका नाम 'इंडो-यूएस रिसर्च' है। इनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम करना है। भारत के कई तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवी इस ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं।

देश आज दुनिया के सामने एक नई पहचान के साथ खड़ा है। राष्ट्र अपनी विस्मृत सांस्कृतिक धरोहर को बटोरकर दुनिया को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। वर्ष 2014 के बाद कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां से एक अलग भारत की दास्तान शुरू होती है। भारत का उभरना कई किस्म के लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए विद्रोह का ताना-बाना तैयार किया जा रहा है। देश के लिए यह बड़ी चिंता का विषय है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को दिल्ली में बैरिकेडिंग के जरिये रोकती पुलिस। रायटर

आशंकाओं को दूर करे सरकार

रिजवान अंसारी
लेखक व स्तंभकार

यह पहला मौका है जब भारत के एक राज्य असम में नागरिकों की पहचान को लेकर एनआरसी की कवायद की गई। यह भी पहला मौका है जब भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत धार्मिक आधार पर लोगों को नागरिकता देने के लिए खुलकर सामने आई है। और इसलिए, यह भी पहला ही मौका है कि भारत सरकार पर नागरिकता संबंधी संवैधानिक मामलों पर सांप्रदायिकता की परत चढ़ाने का आरोप लग रहा है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को समाज के कई तबकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन, कई विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन व तमाम अन्य जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन इसके उदाहरण हैं। इस कानून के आने के बाद पूरा देश दो धड़े में बंटता हुआ दिख रहा है जो 'आइडिया ऑफ इंडिया' के विपरीत है। भारत की गंगा-जमुनी तहजीब की साझी विरासत गौरव करने लायक है। लेकिन किसी कानून से सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचना भी उचित नहीं है। एक बात स्पष्ट है कि भारतीय मुसलमानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे नागरिकता दी जा रही है और किसे नहीं। इस संशोधित कानून में भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे भारतीय मुसलमानों को डरने की जरूरत है। सरकार एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम को अलग-अलग बता रही है। सरकार का दावा है कि यह अधिनियम लोगों को नागरिकता देने के लिए है न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए।

पहली नजर में ये दोनों ही चीजें अलग दिखती भी हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर एनआरसी और नागरिकता कानून में गहरा संबंध है, और इस पूरे विरोध की वजह यही है। सरकार एनआरसी को पूरे देश में लागू करने की बात कह रही है। ऐसे में नागरिकता कानून लागू हो जाने के बाद यह समझा जा रहा है कि एनआरसी से भारतीय मुस्लिमों को नुकसान हो सकता है। यानी जब तक सरकार एनआरसी लागू नहीं करती है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन एनआरसी लागू होने पर भविष्य की आशंकाएं बढ़ जाती हैं।

सवाल यह भी हो सकता है कि यह कैसे संभव है कि आपकी कई पीढ़ियों के भारत में जिंदगी गुजारने के बावजूद आप जरूरी दस्तावेज न दे पाएं। जवाब यह है कि असम में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें लोगों ने सरकारी सेवाओं तक में काम किया है, पर उनका नाम सूची में नहीं है।

यह सब इसलिए भी मुमकिन है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां कई राज्य हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं और लाखों घर पानी में बह जाते हैं। ऐसे घरों में किसी कागजात की बात तो दूर, राजमर्रा की चीजें भी नहीं बच पातीं। देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं करा सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू होने के बाद नागरिकता को लेकर समस्या केवल मुस्लिमों के सामने खड़ी होंगी। और यही कारण है कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है।

यह सच है कि नागरिकता कानून भारतीय मुस्लिमों से भेदभाव करने की बात नहीं करता है। लेकिन अगर एनआरसी पूरे देश में लागू की जाती है तो भेदभाव का आधार स्वतः तैयार हो जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार को एनआरसी के इरादे पर पुनर्विचार की जरूरत है।

कोशिश यह होनी चाहिए कि सभी धर्मों की तरह मुस्लिमों को भी समान कानूनी संरक्षण मिले। सरकार हर हाल में यह सुनिश्चित करे कि अल्पसंख्यक समुदाय में किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना पैदा न हो। अगर सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करती है तो यही उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। बहरहाल सरकार को ऐसी ठोस कवायद करने की जरूरत है जिससे वह देश के अल्पसंख्यकों को भरोसा दिला सके कि एनआरसी और नागरिकता कानून से उनकी नागरिकता को कोई आंच नहीं आएगी।

खरी-खरी

शादियां बचाने की खातिर कुछ सुझाव

पीयूष पांडे

शादी संपन्न होने के दौरान एक-दो नाटक जरूर होते हैं। एक परमानेंट नाटक फूफा की तरफ से होता है। फिर दूल्हे के पिता या बड़े-बूढ़े मना कर फूफा को बारात में ले आते हैं। दूल्हे के दो-चार दोस्त उन्हें पैग बनाकर दे देते हैं। इसके बाद कई शादियों में दूल्हे के टुन्न फूफा को नागिन नृत्य करते हुए भी देखा गया है।

नई परेशानी यह है कि अब शादियों में दूल्हा-दुल्हन और साले-सालियां भी रूठने लगे हैं। सालियां रूठें तो फिर भी गुदगुदी होती है, मगर ये साले? इनके रूठने पर तो देह में खुजली भी न हो। इनको रूठने की क्या जरूरत? मुजफ्फरनगर में एक शादी सिर्फ इस बात पर टूट गई कि सालियों ने जूता चुराने की रस्म के बाद दूल्हे से ज्यादा पैसे मांग लिए। दूल्हे और सालियों में कहासुनी हो गई और शादी टूट गई।

मैंने अपनी साली से पूछा कि ऐसे कित्ते रुपये मांग लिए होंगे लड़कियों ने? वो जवाब देने के बजाय अपना दर्द छलकाने लगी, 'आप तो बोलो ही मत। आपने अपनी शादी में तो चिरौरी करके मुश्किल से हम पांच सालियों को एक हजार रुपये दिए थे। जबकि उस वक्त भी शादियों में प्रति साली ढाई हजार रुपये का भाव चल रहा था।'

मुझे डिफेंसिव मोड में आता देख वह और अफेंसिव हुई, 'दूल्हे कंजूस होते हैं। सालियों के लिए जेब से दो कौड़ी निकालने में इनकी जान जाती है। मैं तो दीदी के चक्कर में चुप रह गई, वरना आप अब तक कुंवारे घूम रहे होते।'

एक पल को मेरे मन में ख्याल आया, काश मैंने यही किया होता। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सका है भला? हर शादी में जूता चोरी में नौटंकी जरूर होती है। सालियों की मांग दूल्हे को नाजायज लगती है और दूल्हे द्वारा की जा रही सौदेबाजी सालियों को। ऐसे में, होना यह चाहिए कि दूल्हा सालियों को अपना वह फॉर्म-16 दिखाए, जिसमें उसकी तनख्वाह लिखी होती है। इससे सालियां खुद समझ जाएंगी कि इस बापड़े लुटे-पिटे को और क्या लूटना!

ऐसी छोटी रस्मों से शादियां टूटेंगी तो शादी होना ही मुश्किल हो जाएगा। विवाह में ठंडा तेल बेचने वाले स्टॉल लगाए जाएं। घराती-बाराती की चंपी हो, ताकि दिमाग भन्नाए नहीं। रूठने की संभावना वाले लोगों को मेडिटेशन कोर्स करवाया जाए। लेन-देन वाली रस्मों की रकम पहले से फिक्स हो।

ट्वीट-ट्वीट

नागरिकता कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला है तो भारतीय मुसलमान क्यों हों परेशान? एनआरसी नागरिक और घुसपैठिये की पहचान के लिए है, भारतीय मुसलमान को क्या नुकसान?
रोमाना इस्सार खान@romanaisarkhan

नागरिकता कानून को लेकर ममता बनर्जी संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की सलाह दे रही हैं। भारत जम्मू-कश्मीर के मसले पर एक बार यह गलती कर चुका है। ऐसे में उम्मीद यही है कि भारत यह गलती दोबारा कभी नहीं करेगा।
गौरव सी सावंत@gauravcsawant

भारत के आंतरिक मामले में यूएन? राजनीतिक विरोध-विद्वेष सब ठीक है दीदी, जमकर करिए, जोरदार करिए, सब साथ आएंगे, पर देश के आंतरिक मतभेद में विदेशी पंच बुलाने की बात बेहद घटिया और खेदजनक है। यहीं लड़िए.. जीतिए.. कानून बनाइए.. बदलिए बाकी यूएन या किसी भी विदेशी पंच की ऐसी की तैसी।
कुमार विश्वास@DrKumarVishwas

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या विपक्षी दलों द्वारा सरकार से नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग करना उचित है?

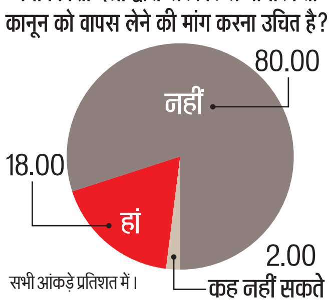

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

कुछ स्थानों पर बिगड़ते हालात को देख मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित करना सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चचा मुशर्रफ पर गिरी न्यायालय की गाज,
तड़प उठी सेना वहां चलता जिसका राज।
चलता जिसका राज चचा को यदि लटकाया,
तो कल जानो आप स्वयं का नंबर आया।
मियां बाजवा कांप उठे यह निर्णय सुन तब,
मृत्युदंड का न्याय सुने जब चचा मुशर्रफ।
– ओमप्रकाश तिवारी

अनूठी पहल के जरिये वृक्षों को जिंदा रखने की कवायद

रेणु जैन
स्वतंत्र टिप्पणीकार

प्रदूषण की मार झेलते शहरों के लिए पेड़ों की कमी भी जिम्मेदार है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण के कई कारण पाए गए हैं, लेकिन पेड़ों की संख्या का भारत के बड़े शहरों में कम होते जाना निश्चित रूप से एक बड़ी वजह के रूप में सामने आ रही है। ऐसे में पेड़ों को बचाने के लिए इन दिनों देश के कई हिस्सों में एक नई पहल की गई है, जिसे पेड़ों पर टंगे विज्ञापनों और पेड़ों पर ठोकी जाने वाली कीलों से जोड़कर देखा जा सकता है। यह अभियान मुख्य रूप से तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चल रहा है। चेन्नई में यह नियम बनाया गया है कि पेड़ों पर कीलें, विज्ञापन, बैनर तथा लाइट आदि लगाने पर तीन वर्ष की जेल तथा 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है।

उधर मुंबई में पेशे से इंजीनियर एक नौजवान द्वारा छेड़े गए पेड़ों से कीलें निकालने का अभियान इतना सफल हो रहा है कि वहां विभिन्न तबकों के लोग विभिन्न पेड़ों से कई हजार कीलें निकाल चुके हैं। पुणे के पास स्थित पिंपरी-चिंचवाड के निगम आयुक्त ने संबंधित विभागों को एक प्रस्ताव भेजा है कि यदि वृक्षों पर कीलें लगी पाई गईं तो संबंधित लोगों को तीन माह कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

पर्यावरणविदों का कहना है कि पेड़ों पर कीलें ठोकने और उन पर लाइट लगाने से उन्हें कई तरह के रोग हो जाते हैं। पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से शाखाएं नहीं बढ़ पाती हैं। कीलें ठोकने वाले स्थान पर छाल गिरने लगती है जिससे पेड़ बीमार होने लगते हैं। पेड़ों के बढ़ने की गति भी कम हो जाती है। ऐसे पेड़ बाहर से भले हरे-भरे दिखें, लेकिन अंदर-ही-अंदर खोखले होते जाते हैं। पेड़ों पर लगी लाइटों से उनकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में बदलाव आने लगता है। पेड़ों पर पक्षियों के घोसले होते हैं। ज्यादा प्रकाश के कारण उन्हें दिन-रात की समझ नहीं रहती जिससे उनका जीवन चक्र भी प्रभावित होता है। कई बार देखने में आता है कि एक पेड़ पर कई छोटे-बड़े बोर्ड टंगे रहते हैं जिसमें कई कीलों का इस्तेमाल होता है। ऐसे पेड़ अक्सर सूखते चले जाते हैं।

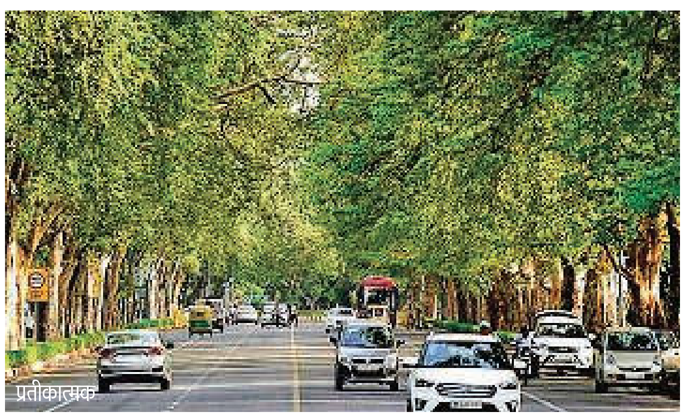

प्रतीकात्मक

कम होते पेड़ों के बारे में 'नेचर' जर्नल की एक रिपोर्ट चिंतनीय है कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, तब से मौजूद पेड़ों की संख्या में अब तक 46 फीसद की कमी आ चुकी है। दुनिया भर में हर वर्ष 10 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि हर सेकेंड में एक फुटबॉल के मैदान जितना जंगल काटा जा रहा है। यदि दुनिया में जंगलों के खात्मे की गति यही रही तो इस सदी के आखिर तक समूची दुनिया से जंगलों का सफाया हो सकता है।

इस रिपोर्ट की मानें तो दुनिया भर में एक व्यक्ति के लिए 422 पेड़ मौजूद हैं। पेड़ों की संख्या के मामले में रूस सबसे आगे है। कनाडा दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर ब्राजील है। इसके बाद अमेरिका का स्थान है। भारत इस मामले में बहुत पीछे है।

माना जाता है कि पेड़ों की कतार धूल मिट्टी को 75 फीसद तक कम कर देती है और 50 फीसद तक शोर को कम कर देती है। जो इलाका पेड़ों से घिरा होता है वह दूसरे इलाकों की तुलना में नौ डिग्री अधिक ठंडा रहता है तथा वहां का एक पेड़ इतनी ठंडक पैदा करता है जितना एक एसी दस कमरों में 20 घंटों तक चलने पर करता है।

कम होते पेड़ों की वजह से कई और दुष्प्रभाव होते सामने आए हैं जिसमें प्राकृतिक बाधाएं भी शामिल हैं। वनों के विनाश के कारण वन्यजीव खत्म हो रहे हैं, वहीं पेड़ों की कई प्रजातियां भी लुप्त होने की ओर हैं। वनों की कटाई का प्राकृतिक जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। बारिश भी अनियमित हो जाती है। इससे 'ग्लोबल वार्मिंग' को बल मिलता है। रेगिस्तान फैल रहा है। नदियों का पानी उथला तथा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि उनके किनारों व पहाड़ों पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जंगल के लिए आदिवासियों का अस्तित्व आवश्यक है। जंगल का उपयोग कैसे करना है आदिवासियों को इसकी पूरी जानकारी रहती है, क्योंकि वनसंरक्षण के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान होता है। पौधरोपण की कमी के कारण इस अनमोल प्राकृतिक संपत्ति का तेजी से क्षरण हो रहा है जो जीवन और पर्यावरण के संतुलन को खराब कर रहा है।

वैसे भारत में कुछ ही दशक पहले 'चिपको आंदोलन' काफी चर्चित हुआ था जिसके अगुवा सुंदरलाल बहुगुणा थे। दरअसल यह आंदोलन इसलिए प्रारंभ किया गया था कि भारत के उत्तरी क्षेत्रों में सरकार ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई प्रारंभ कर दी थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने सैकड़ों की संख्या में इस आंदोलन को काफी सफलता मिली थी। आज हमें देश भर में न केवल पेड़ों को बचाना है, बल्कि करोड़ों की संख्या में नए पेड़ लगाने पर ध्यान देना होगा।

हैदराबाद एनकाउंटर

सामने आए मुठभेड़ का सच

अपराधी को सजा देने में देरी होने पर अभियुक्तों का एनकाउंटर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारा देश संविधान से ही चलेगा और वह जनभावना के ज्वार से नहीं चल सकता

चंदन कुमार चौधरी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद एनकाउंटर की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए एक जांच आयोग का गठन किया है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वीएस एस सिरपुरकर की अगुवाई में तीन सदस्यीय एक जांच आयोग का गठन किया है। एनकाउंटर की जांच के लिए बने आयोग का ऑफिस हैदराबाद में बनाया जाएगा और इस आयोग के सभी सदस्यों को सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है और तेलंगाना सरकार को आयोग का पूरा खर्च उठाने का आदेश दिया है। आयोग के दो अन्य सदस्यों में एक बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज रेखा बल्दोता, जबकि दूसरे पूर्व सीबीआइ डायरेक्टर डीआर कार्तिकेयन होंगे।

दरअसल हैदराबाद एनकाउंटर का मामला एक महिला पशु चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और फिर हत्या मामले में अभियुक्त बनाए गए चार युवकों के कथित एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना पुलिस के अनुसार वह इन चारों अभियुक्तों को अपराध वाली जगह पर लेकर गई थी। वहां से अभियुक्तों ने भागने की कोशिश की और फिर पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने दावा किया था कि इस दौरान जवाबी कार्रवाई में चारों अभियुक्त पुलिस की गोली के शिकार हो गए।

इस एनकाउंटर पर सोशल मीडिया में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई और चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कुछ लोगों ने जहां इस एनकाउंटर का समर्थन किया वहीं कुछ लोगों ने इसे गलत ठहराया और पुलिस एवं तेलंगाना सरकार की मंशा एवं एनकाउंटर के तरीके पर कई तरह के सवाल उठाए। पुलिस जहां इस घटना को एनकाउंटर बताती रही है, वहीं कई संगठन और लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहे। इस तरह के लोगों को लगता रहा कि पुलिस के एनकाउंटर की कहानी में कुछ खामी है। ऐसे में जांच लिए आयोग के गठन का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें एनकाउंटर की सच्चाई का पता चल सकेगा।

ऐसा नहीं है कि देश में पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर हमेशा सही ही रहा है, बल्कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब पुलिस को फर्जी मुठभेड़ में दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक एक जनवरी 2015 से लेकर 20 मार्च 2019 के बीच उसे देश भर में फेक एनकाउंटर से जुड़ी 211 शिकायतें मिली हैं। इस अवधि के दौरान उसने ज्यादा 57 फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें आंध्र प्रदेश में दर्ज की। उत्तर प्रदेश इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा और इस अवधि में यहां 39 मामले दर्ज किए गए। हैदराबाद मुठभेड़ मामले में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और एनएचआरसी ने तुरंत एक टीम को घटनास्थल पर जांच के लिए जाने का निर्देश दिया था। हालांकि एनकाउंटर की खबर सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस का स्वागत किया और जश्न मनाया। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसका निर्णय अदालत करेगी और अगर वे अपराधी हैं तब भी पुलिस को एनकाउंटर की इजाजत नहीं दी जा सकती और अदालत के फैसले के आधार पर ही अपराधी को सजा दी जाएगी। भारत के संविधान में किसी अपराध के लिए न्याय की बात कही गई है, बदले की बात नहीं कही गई है। अगर यह मान लिया जाए कि यह एनकाउंटर फर्जी था और तेलंगाना पुलिस ने उन अभियुक्तों को मार दिया तो निश्चित रूप से पुलिस ने कानून अपने हाथ में लिया और इसके लिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए।

शायद यही वजह है कि मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में अभियुक्त बनाए गए चार युवकों के कथित पुलिस एनकाउंटर के संदर्भ में कहा था कि न्याय कभी बदला लेने में तब्दील नहीं होना चाहिए। अगर यह बदला लेने में तब्दील हो जाए, तो न्याय अपना चरित्र खो देता है। समाज में घट रही अपराध की घटनाओं, विशेषकर दुष्कर्म जैसे जघन्य मामलों में सजा की तामील होने में देरी को लेकर जनाक्रोश को समझा जा सकता है। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही यौन हिंसा और अपराध की घटनाओं ने आधी आबादी को भयाक्रांत कर रखा है। हमें उसे एक सुरक्षित समाज देना होगा जिसमें वे खुल कर सांस ले सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। हमें उनके मन से भय निकालना होगा और इसके लिए ऐसे अपराधों में त्वरित सजा देने के लिए कार्रवाई करनी होगी। हमें अपने न्यायिक प्रणाली में सुधार करना होगा और उसकी खामियों को दूर करना होगा ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके।

प्रतीकात्मक

यह सच है कि लोगों के मन में न्यायालय को लेकर एक छवि बनी हुई है और इसे बदलने और इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इसका मतलब बदला लेना नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोगों के मन में न्यायालय की जो छवि बनी हुई है उसे बदलने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा था कि हाल में हुई कुछ घटनाओं के बाद यह चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए।

जब हम एनकाउंटर की बात करते हैं तब हमें भारतीय संविधान की ओर भी देखना होगा। भारतीय कानून में एनकाउंटर को वैध ठहराने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर अपने नियम-कानून बनाए हुए हैं। संविधान में कुछ ऐसे नियम-कानून जरूर हैं जो पुलिस को यह ताकत देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की मौत को सही ठहराया जा सकता है।

64 हजार पेड़ काटने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी के किनारे डिफेंस एक्सपो के लिए 64 हजार पेड़ों को काटे जाने प्रस्ताव है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 20 दिसंबर 2019

रेत पर लिख रहे हरित क्रांति का नया अध्याय

काव के तटीय इलाके में आलू की फसल के लिए खेत तैयार करते किसान। जागरण

प्रमोद टैगोर, संझौली (रोहतास)

- बिहार में रोहतास जिले के रोजगारविहीन तटीय इलाके में लौटी खुशहाली
- परदेस से लौटकर गांव पहुंचे लोग खेती से संवार रहे अपना भविष्य

गरीबी उन्मूलन

रेत पर हरित क्रांति का यह एक नया अध्याय है। बिहार के रोहतास जिले में काव नदी का तटीय इलाका कभी अपराधियों की शरणस्थली था। डेढ़ दशक पहले तक वहां दिन में भी बंदूकें गरजती थीं। अब किसानों की मेहनत और हिम्मत ने इलाके की रंगत ही बदल दी है। बंजर पड़ी छह हजार एकड़ से अधिक जमीन पर फसलें लहलहा रही हैं। अपराधियों की सरपरस्त बनी आबादी अब खेती-किसानी में मशगूल है। किसानों के घर धन-धान्य से भर गए तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। निजी-सरकारी नौकरियों में भी कई युवा अच्छे ओहदेदार बन गए हैं। लोग परदेस से लौटकर बंजर पड़ी भूमि पर खेतीबाड़ी शुरू कर विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।

संझौली, काराकाट, नासरीगंज, राजपुर, सूर्यपुरा और दावथ प्रखंडों को छूते काव नदी के तटीय इलाके में आज हरियाली ही हरियाली नजर आती है। किसानों ने बंजर पड़ी करीब पांच हजार एकड़ जमीन को उपजाऊ बना दिया। इटढ़ियां, बेनसागर, चरपुरवा, छुलकार, बाजितपुर, बुकनाव, चैता बाल, रामोडीह, चवरियां, करूप, मंझरिया समेत दावथ और राजपुर प्रखंडों के करीब तीन दर्जन गांवों के लोग बंजर पड़ी भूमि पर रबी, खरीफ और नकदी फसल के रूप में सब्जियों की खेती कर रहे हैं।

फसलों के साथ लगाए गए बाग : इस क्षेत्र में फसलों के साथ कई जगहों पर अमरूद और आम के बागीचे भी लगाए गए हैं, जिसका फल बेचकर आर्थिक मजबूती तो मिल ही रही, पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है। अब तो कृषि विभाग भी जमीन को उपजाऊ बनाने और उन्नत बीज देने में सहायक बन रहा है। परदेस से लौटे बली सिंह, संजय सिंह, कामता पासवान व अर्जुन चौधरी बताते हैं कि आज वह अपनी मिट्टी पर बेहतर जीवन बिता रहे हैं। परदेस में 10-15 हजार रुपये की जिल्लतभरी नौकरी करने से यहां की खेतीबारी बहुत अच्छी है। अब खेतों में बिजली के खंभे भी लगने लगे हैं, जिससे खेती में और सहूलियत हो जाएगी।

मन में नहीं रहा गन का डर : एक दशक पहले मंझरिया में पुलिस उपाधीक्षक अखिलेश्वर प्रसाद और सुकहरा में मेजर केपी शर्मा की हत्या से नदी का तटीय इलाका खौफनाक हो गया था। इलाके से अधिकांश युवक पलायन कर गए थे, लेकिन युवाओं की सकारात्मक सोच से एकजुटता आई। उनके तेवर बदले। मेहनत का रोलर चला तो सब कुछ बदल गया। अब तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। बेटियां भी साइकिल से पढ़ाई करने गांव के नजदीक कस्बों तक जाने लगी हैं।

अब युवा नहीं रह जाते हैं कुंवारे : इस तटीय क्षेत्र के गांवों में लोग बेटियों की शादी करने से कतराते थे। इसके कई कारण थे, मसलन बंजर जमीन और यहां के लोगों का बेतरतीब जीवन स्तर, शराब का सेवन, शिक्षा व सड़क का अभाव ...। आज धीरे-धीरे सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। अब युवा कुंवारे नहीं रह जाते हैं। गांव मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ गए हैं। सभी गांवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित हो गए हैं। आतंक का माहौल समाप्त हो गया है। इसी वर्ष मंझरिया के जयकिशन ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र को एक अलग पहचान दी है।

इतिहास के झरोखे से इलाका : 350 वर्ष पूर्व काव नदी धान के कटोरे के लिए शोक के रूप में जानी जाती थी। दूर तक कोई गांव नहीं था, चारों तरफ पानी ही पानी था। 1762 के सर्वे के मुताबिक तटीय क्षेत्र में मात्र छह गांव थे। इटाढ़ी, कुलरी, मझारी, परसूनगर, अमरीय और बेनसारि। 1911 के सर्वे में दर्जनों छोटे-छोटे गांव बस गए। रेतीली जमीन ही किसानों के नाम हुई। फिर लोगों ने हाड़तोड़ मेहनत करके झाड़-झंखाड़ को साफ कर उसे उपजाऊ बनाया। नतीजतन, आज इस क्षेत्र में फसलें लहलहा रही हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

सब सुन रहे हैं होनहार कीर्ति के हौसले की 'कीर्ति'

जागरण विशेष ▶ हरियाणा की बेटी ने एड़ी कटने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, रिंग में उतरकर विरोधी किए परास्त

विजय गाहल्याण, पानीपत

मन में यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो शारीरिक अक्षमता भी सफलता की राह नहीं रोक पाती। ऐसा ही उदाहरण पेश कर रही हैं हरियाणा स्थित पानीपत की कीर्ति। 2014 में बुआना लाखू गांव की होनहार बेटी कीर्ति के पैर की एक एड़ी ट्रैक्टर से कुचल गई। बॉक्सिंग के रिंग में चीते सी फुर्ती के साथ विरोधियों को परास्त करने वाली कीर्ति के लिए यह समय बहुत ही दुखदायी साबित हुआ।

डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद हिदायत दी कि अब वह कभी नहीं खेल पाएगी। एड़ी पर दबाव पड़ा तो वह फिर से टूट जाएगी। पिता संजय के पास बेहतर इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। हालात से समझौता कर कीर्ति ने घुट-घुटकर जीना सीख लिया, मगर दिल में बॉक्सिंग में नाम कमाने की चाहत कम नहीं हुई। कीर्ति के कोच सुरेंद्र के लिए भी यह स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कीर्ति का हौसला बढ़ाते रहे। आगे बढ़ने की जिद और कोच के हौसले का असर ही था कि कीर्ति ने वह कर दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।

प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय फलक तक न केवल उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, बल्कि पदकों से झोली भी भर ली। 17 से 22 नवंबर तक दिल्ली में हुई 65वीं स्कूल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 54 से 57 किलोग्राम में तो उसने पांच बॉक्सरों को नाकआउट कर स्वर्ण पर कब्जा जमाया। इसी के दम पर कीर्ति का चयन नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक में हुआ है। आइटीबीपी ने भी कीर्ति के हुनर को पहचाना और दिल्ली के द्वारका में 11वीं कक्षा की मुफ्त में पढ़ाई का इंतजाम कराया।

रजनी से ली प्रेरणा, ट्यूशन से बंक मारकर पहुंची रिंग में : कीर्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गांव की अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर रजनी के जज्बे को सराहा। रजनी को बॉक्सिंग करते देख वह भी रिंग में उतरी। उसने ट्यूशन से बंक मारा और रिंग में अभ्यास के लिए चली गई। पता चलने पर पिता ने डांटा, मगर मां ने साथ दिया। उसने पहली ही स्कूली प्रतियोगिता में पदक जीता तो पिता ने खेलने की अनुमति दे दी। स्पैट में भी चयन हुआ और 1200 रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद भी मिली। इससे खुराक का प्रबंध हुआ और सफलता भी मिली।

लड़कों की तरह रहना पसंद, पंजे के बल करती हैं अभ्यास : बॉक्सिंग कोच सुरेंद्र मलिक ने बताया कि 2014 में ट्रैक्टर की चपेट में आने से कीर्ति ने पैर की एड़ी गंवा दी। वह पंजे के बल हर रोज छह घंटे अभ्यास करती है। वह मजबूत पंच से विरोधी बॉक्सर को नाकआउट कर देती है। कीर्ति को लड़कों की तरह रहना पसंद है। पहले उसके पहनावे पर लोग तंज कसते थे, मगर उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वह कामयाबी होती चली गई।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

कोच सुरेंद्र मलिक (बाएं) के साथ कीर्ति। जागरण

मध्य प्रदेश के विदिशा में 800 हेक्टेयर जंगल पर पत्थर माफिया का कब्जा

चिंताजनक हालात ▶ संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने में नाकाम वन विभाग

उच्च गुणवत्ता वाले लाल और काले पत्थर की है भरमार

अजय जैन, विदिशा

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील में करीब 800 हेक्टेयर जंगल पर वर्षों से पत्थर माफिया का कब्जा है। यहां 100 से अधिक पत्थर खदानें चल रही हैं। संरक्षित वन क्षेत्र होने के बावजूद वन विभाग और जिला प्रशासन अवैध खनन रोकने में नाकाम है।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 1971 में विदिशा और रायसेन जिले की सीमा पर हलाली बांध (सम्राट अशोक सागर परियोजना) का निर्माण हुआ था। बांध में वन विभाग की जमीन डूब गई थी। बदले में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने वन विभाग को गंजबासौदा तहसील में 800 हेक्टेयर जमीन दी थी। यहां घना जंगल विकसित करना था, लेकिन पूरा क्षेत्र पथरीला होने के कारण 48 वर्षों के दौरान वन विभाग ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। यह क्षेत्र उदयपुर, पठारी, घटेरा और त्योंदा तक फैला है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां अंदर तक पहुंचना काफी मुश्किल है। बाहरी व्यक्ति के आने पर पत्थर माफिया के लोग घेर लेते हैं। इन खदानों में लगभग 18 हजार मजदूर कार्यरत हैं।

गंजबासौदा तहसील में वन भूमि पर संचालित अवैध पत्थर खदान। नईदुनिया

रसूखदारों का कब्जा : इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला लाल और काला पत्थर पाया जाता है, जो विदेशों में निर्यात होता है। इसके अलावा हरा और पीला पत्थर भी है। इसी कारण यहां अवैध खनन बढ़ता गया। अवैध खनन में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेता व अन्य रसूखदार भी शामिल हैं। वर्तमान में पूरी वन भूमि पत्थर माफिया के कब्जे में है। विदिशा से लेकर भोपाल तक आला अफसरों को जानकारी होने के बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती।

शासन को राजस्व का नुकसान : हर साल इन खदानों से करोड़ों रुपए का पत्थर निर्यात होता है, लेकिन शासन को कुछ नहीं मिलता। जिला खनिज अधिकारी एमएस रावत के मुताबिक, इन अवैध खदानों के कारण शासन को हर साल तीन से चार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वन विभाग के रेंजर सुरेश शर्मा ने बताया कि अवैध खदानों पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। खदान संचालक और मजदूर भाग जाते हैं, इसलिए नामजद कार्रवाई नहीं हो पाती। अमले की कमी से भी दिक्कतें हैं।

पुनः राजस्व विभाग को सौंपने के प्रयास : सूत्रों के अनुसार वर्ष 1981 में यह जमीन पुनः राजस्व विभाग को सौंपने की तैयारी हुई थी। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रयास भी हुए, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली।

गंजबासौदा के संरक्षित वन क्षेत्र में चल रही अवैध पत्थर खदानों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। यह जमीन राजस्व विभाग को सौंपने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में स्थायी रूप से अवैध खनन रोका जा सके।
– कौशलेंद्र सिंह, कलेक्टर, विदिशा

सीकरी में क्यूआर कोड देगा लाइन की झंझट से मुक्ति

जागरण संवाददाता, आगरा : ताजमहल और आगरा किला के बाद अब सीकरी में भी पर्यटकों को टिकट के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। टिकट विंडो पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन टिकट बुक कराया जा सकता है। सीकरी में यह व्यवस्था 7 दिसंबर से शुरू कर दी गई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने नवंबर में ताजमहल और आगरा किला पर स्कैन एंड पे व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके फायदे को देखकर अब यह व्यवस्था फतेहपुर सीकरी में भी शुरू कर दी गई है। टिकट विंडो के पास स्कैन एंड पे के बोर्ड लगाए गए हैं। पर्यटक स्कैन एंड पे के साथ ही वेबसाइट https://asi.payumoney.com/quick/taj से भी टिकट बुक करा सकते हैं।

अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी पर स्कैन एंड पे व्यवस्था शुरू की जा चुकी है।

ऐसे बुक कर सकते हैं टिकट: क्यूआर कोड स्कैन करें। राष्ट्रीयता का चयन करें। टिकट संख्या और मोबाइल नंबर डालें। आगे बढ़ें, भुगतान करें और मोबाइल पर टिकट प्राप्त करें। यह टिकट केवल उसी दिन के लिए मान्य होगा।

ताज पर नेटवर्क की समस्या: ताज पर स्कैन एंड पे व्यवस्था से टिकट बुक कराने में नेटवर्क की समस्या है। कमिश्नर के निर्देशों के बाद बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क में सुधार किया है।

नफीस की मेहनत से बंजर भूमि उगल रही सोना

मनीष कुमार, हरिद्वार

- आठ वर्ष पूर्व किराये पर पांच बीघा भूमि लेकर नफीस ने शुरू की थी कैलिफोर्निया स्ट्राबेरी की खेती
- सफलता से उत्साहित होकर अब नौ बीघा तक किया खेती का विस्तार, दस लोगों को दे रहे रोजगार

ख्वाहिशें तूफान हों तो अफसाने भी हकीकत में बदल जाते हैं। हरिद्वार जिले के जमालपुर कलां निवासी नफीस ने लगन एवं मेहनत से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर इस उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है। वह इस भूमि पर कैलिफोर्निया स्ट्राबेरी की कैमरोजा प्रजाति की खेती कर स्वयं तो अच्छी-खासी कमाई कर ही रहे हैं, दस लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।

मूलरूप से मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले नफीस काफी समय से जमालपुर कलां गांव में अपने मामा के पास रहते हैं। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने आठ साल पहले जमालपुर-सराय मार्ग पर पांच बीघा भूमि किराये पर ली थी। भूमि बंजर होने के कारण शुरुआत में निराशा हाथ लगी, लेकिन फिर उन्होंने इस पर स्ट्राबेरी की खेती शुरू कर दी। मेहनत रंग लाई और धीरे-धीरे इस 'लाल सोने' की डिमांड आसपास के बाजारों में बढ़ने लगी। इससे उत्साहित नफीस ने अब पांच के बजाय नौ बीघा भूमि में स्ट्राबेरी उगानी शुरू कर दी है।

नफीस से प्रेरित हो आठ लोग कर रहे स्ट्रॉबेरी की खेती : कैलिफोर्निया स्ट्राबेरी की कैमरोजा प्रजाति अपने चटख रंग और रसीले स्वाद से हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। बकौल नफीस, 'जनवरी से फसल आनी शुरू हो जाती है, जो शुरुआत में यह 300 से 400 रुपये प्रति किलो तक बिक जाती है। हालांकि, इसका सीजन मार्च-अप्रैल तक रहता है। वर्तमान में मैं दूसरे किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। नतीजा, जिले में आठ लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए हैं। मैं उन्हें रियायती दर पर पौध भी उपलब्ध करा रहा हूं।'

हरिद्वार के जमालपुर कलां निवासी नफीस ने स्ट्राबेरी उगाकर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया तो दूसरों को भी दिखाई राह। खेत में उगी स्ट्राबेरी की फसल दिखाते नफीस। जागरण

लगातार बढ़ रही चक्रवात की संख्या और तीव्रता

आयुष शर्मा, देहरादून

- भारतीय राष्ट्रीय कार्टोग्राफिक संघ की कांग्रेस में डॉ. राजा घोष ने अपनी शोध रिपोर्ट में दी जानकारी
- कहा, तटीय शहरों के लिए खतरनाक है यह बदलाव

विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के चलते साल दर साल न केवल चक्रवात (साइक्लोन) की तीव्रता बढ़ती जा रही है, बल्कि संख्या में वृद्धि हुई है। यदि समय रहते इससे निपटने के विकल्प नहीं तलाशे गए तो यह बदलाव तटीय शहरों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। भारतीय राष्ट्रीय कार्टोग्राफिक (मानचित्रकार) संघ (आइएनसीए) की 39वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस मे कोलकाता स्थित खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राजा बोस ने अपनी शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करते कहा कि चक्रवात की तीव्रता और उनसे हुई तबाही में लगातार बढ़ रही है।

डॉ. राजा ने ओडिशा को आधार बनाकर पिछले 20 वर्षों में आए चक्रवात पर शोध किया है। डॉ. राजा ने बताया कि 1999 में आए सुपर साइक्लोन की अधिकतम रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जबकि अक्टूबर 2019 में आए फैनी की तीव्रता लगभग 250 किलोमीटर प्रतिघंटा। अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले 20 वर्षों में साइक्लोन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। जो समुद्र तट पर बसे शहरों को खत्म करने के लिए काफी है।

ये चक्रवात रहे खतरनाक

नाम, साल, तीव्रता (किमी प्रति घंटा में), नुकसान (अरब डॉलर में)

सुपर साइक्लोन, 1999, 200, 4.44

हुड्हुड, 2014, 215, 3.58

फैनी, 2019, 250, 8.1

ऐसे हो सकता है बचाव : डॉ. राजा कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए तैयारी जरूर की जा सकती है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही भवन निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग कम करने के उपाय करने सर्वाधिक जरूरी हैं।

परियों को भाया हरियाणा का आंगन, खुशी से ठुमका मन

बलवान शर्मा, भिवानी

परवान चढ़तीं उम्मीदें

- पिछले साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक हजार बेटों पर 910 बेटियां पैदा हुईं, इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 920 बेटियों का जन्म हुआ, आगे एक हजार करने का लक्ष्य

हरियाणा परियों को भाने लगा है। एक दशक पहले तक यहां के आंगन में वे उतरने से कतराती थीं। यह भी कह सकते हैं कि उतरने ही नहीं दी जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं। हर वर्ष नन्ही परियों की संख्या बढ़ती जा रहा है। बड़ी बात यह है कि समाज की मानसिकता बदल रही है। बेटियां को आंगन में चहचहाते देख अब माता- पिता का मन भी खुशियों से ठुमकने लगा है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इसे रेखांकित कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक हजार बेटों पर 910 बेटियां थीं, इस साल अक्टूबर में यह अनुपात बढ़कर 920 पहुंच गया है।

वैसे लक्ष्य तो एक हजार बेटों पर एक हजार बेटियों का है, हालांकि वह अभी दूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हासिल न किया जा सके। बस पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर इसी तरह सतत प्रयास होते रहें। जिस तरह से सरकार ने कन्याहंताओं पर शिकंजा कसा है। कोख में बेटियों को मारने वालों को, लिंग जांच करने वालों को गिरफ्त में लिया जा रहा है, यह उसी का सुपरिणाम है। इस अभियान को और तेज किए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डा. दयानंद बागड़ी इसे स्वीकार भी करते हैं। वह बताते हैं कि सरकार इस अभियान को और तेज करने का प्रयास कर रही है। जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता हम ये प्रयास पूरी शिद्दत से जारी रखेंगे।

अब बेटी के जन्म पर बांटे जाने लगे हैं लड्डू, होता है कुआं पूजन : समाज में आए बदलाव स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अब बेटी के जन्म पर भी लड्डू बांटे जाते हैं। कुआं पूजन होता है। प्रमुख लोग इसके लिए उदाहरण पेश करते हैं। जैसे पिछले दिनों भिवानी के जिला उपायुक्त ने पौत्री के पैदा होने के बाद एक क्विंटल लड्डू बंटवाए थे।

पंचकूला व अंबाला ने किया शानदार प्रदर्शन: इस बार पंचकूला, अंबाला, झज्जर, पानीपत व फतेहाबाद जिलों में लिंगानुपात सुधारने के लिए शानदार प्रयास किए गए हैं। इसके विपरीत सिरसा व भिवानी सबसे निचले पायदान पर आ गए हैं। ये दोनों जिले कभी अग्रणी होते थे।

1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2018 व एक जनवरी से 31 अक्टूबर 2019 तक जिलों में आया सुधार

जिला	2018	2019	बढ़ोतरी
पंचकूला	912	970	58
अंबाला	902	951	49
झज्जर	862	908	46
पानीपत	891	936	45
फतेहाबाद	887	924	37
महेन्द्रगढ़	895	923	28
पलवल	904	932	28
रोहतक	888	910	22
हिसार	910	927	17
जींद	931	943	12
गुरुग्राम	900	911	11
रेवाड़ी	905	913	08
फरीदाबाद	916	919	03

योजना

हिमाचल प्रदेश में पांच रुपये किलो बिकेगा देसी गाय का गोबर, आठ रुपये लीटर में गोमूत्र, किसानों के बनेंगे संसाधन भंडारण, 10,000 रुपये दी जाएगी सब्सिडी

गोमूत्र और गोबर से मालामाल होंगे किसान

मुकेश मेहरा, कुल्लू

अब हिमाचल प्रदेश के किसान गोमूत्र और गोबर से मालामाल होंगे। देसी गाय का गोबर पांच रुपये प्रति किलोग्राम व गोमूत्र आठ रुपये लीटर बिकेगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत सरकार ने इसके दाम तय किए हैं। देसी गाय के संरक्षण के लिए भी सरकार ने बड़ी पहल की है। किसान प्राकृतिक खेती के इस्तेमाल के लिए बनने वाली जीवामृत व घनजीवामृत खाद 12 व दो रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेच सकेंगे।

प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो छोटे किसान घरों में प्राकृतिक खेती से संबंधित खाद तैयार नहीं कर सकते हैं उनके लिए सरकार संसाधन भंडारण बनाएगी। जो किसान इसके लिए आवेदन करेगा उसे 10,000 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। किसान जीवामृत, घनजीवामृत सहित अन्य खाद तैयार करेगा और उसे बेच सकेगा। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र भी इसमें शामिल किया गया है।

कई छोटे किसान या आम लोग जिनके पास अधिक जमीन नहीं होती तथा प्राकृतिक खाद नहीं बना पाते उनके लिए सुविधा होगी। जिला कुल्लू में ही अभी तक 15 किसानों ने संसाधन भंडारण के लिए आवेदन किया है।

किचन गार्डनिंग के लिए बेहतर

प्राकृतिक खादों की बिक्री का सबसे अधिक लाभ शहरी क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। किचन गार्डनिंग के लिए उनको सस्ते दामों पर बेहतर प्राकृतिक खाद उपलब्ध हो जाएगी। किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इन खादों के निर्माण में किसानों को अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना है।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत संसाधन भंडारण बनाए जाएंगे। इसमें देसी गाय के गोबर, गोमूत्र सहित प्राकृतिक खादों को किसान बेच सकेंगे। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
–अमरजीत, एसएमएस शून्य लागत प्राकृतिक खेती कुल्लू।

प्राकृतिक खाद व दाम

देसी गाय का गोबर	पांच रुपये प्रति किलो
घनजीवामृत खाद	12 रुपये किलो
गोमूत्र	आठ रुपये लीटर
नीम मरहम	छह रुपये किलो
जीवामृत खाद	दो रुपये लीटर
बीजामृत	पांच रुपये लीटर
नीमास्टर	2.50 रुपये लीटर
ब्रह्मास्टर	25 रुपये लीटर
अग्निास्टर	35 रुपये लीटर
दशपर्नी अरक	35 रुपये लीटर
खट्टी लस्सी	आठ रुपये लीटर
सप्तध्यानांकुर अरक	चार रुपये लीटर
जंगल की कंडी	एक रुपये लीटर
सोंथास्टर	तीन रुपये लीटर।

अब हर महीने बैठक करेंगे भारत-नेपाल के अधिकारी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : भारत और नेपाल सीमा से लगे वन क्षेत्रों में होने वाले अपराधों को रोकने तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए गुरुवार को दोनों देशों के वन अधिकारियों ने बैठक की। जिसमें तय हुआ कि दोनों देश संयुक्त रूप से अपराध संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। हर महीने दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक आहूत की जाएगी। दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने पर भी खास जोर रहा। टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज के मुस्तफाबाद गेस्टहाउस में गुरुवार दोपहर वर्ल्ड वाइड फंड संस्था के तत्वावधान में इंडो-नेपाल को-आर्डिनेशन मीटिंग आयोजित हुई। जिसमें वन अपराध रोकने एवं मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने पर वार्ता हुई। बैठक में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के परियोजना अधिकारी नरेश कुमार ने कहा कि हर माह दोनों देश के अधिकारियों की बैठक होना चाहिए।

दैनिक जागरण
सबरंग

प्लान वीकेंड के

नई दिल्ली, शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

सांत्वना निगम द्वारा निर्देशित सहेज के सरगम नाटक का एक भाग है...बस सिर्फ इसलिए...उसी नाटक का दृश्य है यह। जहां एक पति, अपनी पत्नी से क्षमा मांगना चाहता है और वह नाराज बैठी है।

'स्प्लेंडर इन द ग्रास' विलियम इंगे द्वारा रचित स्प्लेंडर इन द ग्रास का हिंदी रूपांतरण किरणदीप शर्मा द्वारा किया गया है... इस नाटक में आपको हास्य, फुल ड्रामा, रोमांस और मर्म सब मिलेगा।

साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी गजब के होते हैं... कौशिक बोस निर्देशित 'कंपंशन' (मलाल) नाटक भी कुछ ऐसा ही है।
सभी तस्वीरें : सौजन्य : श्रीराम सेंटर

इस बार यहां चलें

मेरे सपने, मेरी दुनिया

दिव्यांग बच्चे कूची से कैनवस पर अपनी भावनाएं उकेरेंगे। बच्चों के मन के भाव समझने, देखने के लिए मेरे सपने, मेरी दुनिया बेहतरीन अवसर है। जिसमें दीपाश्रम संस्था के बच्चों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी।
- कहां : अपर्णा फाइन आर्ट गैलरी, 4/6 सिरीफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया।
- कब : 20–22 दिसंबर, सुबह 11 से शाम सात बजे तक।
- प्रवेश–निश्शुल्क

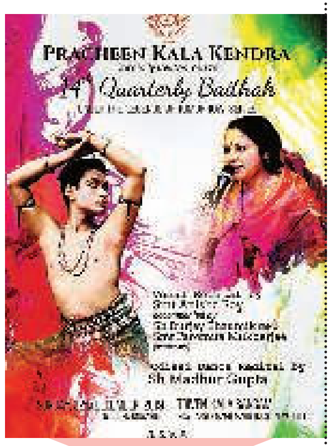

लिजेंड्स ऑफ टूमॉरो

दिल्ली में संगीत व नृत्य की महफिल सजेगी। युवा कलाकारों की प्रस्तुति समां बांध देगी। अनीशा रे, दुर्जय भौमिक, प्रोमिता मुखर्जी सरीखे कलाकार प्रस्तुति देंगे। यही नहीं मधुर गुप्ता की प्रदर्शनी दर्शकों का दिल जीत लेगी। प्राचीन कला केंद्र द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम दिल्लीवालों के सप्ताहांत को सुखद बनाएगा।
- कहां : त्रिवेणी कला संगम, मंडी हाउस।
- कब : 22 दिसंबर, शाम साढ़े छह बजे।
- प्रवेश–निश्शुल्क

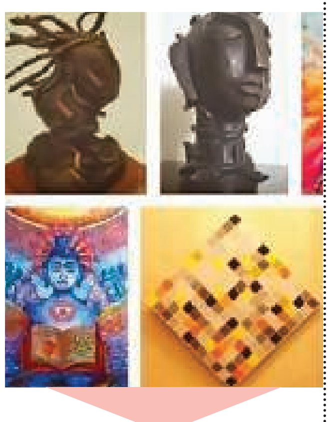

द वॉयस

कलाकृतियां चुप रहते हुए भी बहुत कुछ सुनाती हैं। वो कहानी कहती हैं, ना सिर्फ कलाकार की बल्कि समाज की। द वॉयस ऐसे ही कलाकारों की एक कोशिश है, जिसमें कलाकृतियां दर्शकों से संवाद करती नजर आएंगी। इसमें आलोक शंकर, ए श्रीधरन, विनय कुमार, देवयानी कपूर, कमल शर्मा, नरोत्तम पटेल, संजीव कुमार स्तुति जैन सरीखे कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी।
- कहां : इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड।
- कब : 22 दिसंबर तक, सुबह दस से रात आठ बजे तक। ● प्रवेश–निश्शुल्क

वेयर कल्चर मीट्स

एक ऐसी जगह जहां संस्कृति मिलती है। जी हां, कतर और भारत की यह संयुक्त कला प्रदर्शनी संस्कृतियों को दर्शाती है। हमद अल और आयशा अल सादाह ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया एवं वहां की दिलचस्प जानकारियों को कलाकृतियों के जरिए सामने रखा है। ये कलाकृतियां आम लोगों की जिंदगी, ऐतिहासिक इमारतों पर आधारित हैं।
- कहां : द सेंटर अर्ट्रियम, लोदी रोड।
- कब : 12 जनवरी तक, सुबह 11 से रात आठ बजे तक। ● प्रवेश : निश्शुल्क

नाट्य उत्सव

रिश्तों को परखेगा रंगमंच

कलाकार अपने पात्र में रम चुके हैं। हर संवाद का अनुसरण कर चुके हैं। मंच भी तैयार है। चित विचलित कर देने वाली...वेदनाएं...आत्मा तक को झकझोर कर जगा देने वाले पात्रों के संवाद...रिश्तों की अबूझ पहेलियों को सुलझाने वाली कहानियों के साथ नौ दिवसीय पन्ना भारत राम नाट्य उत्सव शुरू होने जा रहा है। सबरंग के इस अंक में उत्सव में मंचित होने वाले खास नाटकों की कहानियों से रूबरू करा रहे हैं **संजीव कुमार मिश्र** :

रंगमंच रिश्तों को परखेगा भी और निखारेगा भी। यहां पिता का प्यार तो झलकेगा ही एक अटूट प्यार की डोर में बंधी कहानी भी होगी। सामाजिक तानेबाने में बुनी कहानियां दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ ही सामाजिक संदेश भी देंगी। शुरुआत फैसल अल्काजी के 'स्प्लेंडर इन द ग्रास' से करते हैं जो दर्शकों के लिए भरपूर मनोरंजन लेकर आएगा। विलियम इंगे द्वारा रचित स्प्लेंडर इन द ग्रास का हिंदी रूपांतरण किरणदीप शर्मा द्वारा किया गया है। इस नाटक में आपको हास्य, फुल ड्रामा, रोमांस और मर्म सब मिलेगा। इसकी कहानी दो स्कूली बच्चों के इर्दगिर्द घूमती है, जिनके नाम सनी और विशु हैं। इनके प्यार में कटुता आने पर सनी की बहन घर लौटती है, तब समस्या उत्पन्न होती है। किशोरवय के रोमांस, मध्यम वर्गीय मूल्यों और पीढ़ियों के टकराव की इस दिलचस्प कहानी में अगले कुछ महीनों में क्या होता है? यह यह आपके लिए देखना बेहद दिलचस्प होगा। नाटक में 16 कलाकारों का दमदार अभिनय दिखेगा। निर्देशक फैसल कहते हैं कि दिल्ली के दर्शक इसे पसंद करेंगे। क्योंकि इसकी कहानी बहुत अलग है। दिल्ली के दर्शक नए प्रयोगों को देखना पसंद भी करते हैं। यहां नाटकों के मंचन के बाद कई बार दर्शक मिलकर बधाई देने आते हैं जिससे निर्देशक ही नहीं कलाकारों का भी उत्साह बढ़ता है। नाटक का मंचन 21 दिसंबर को होगा।

रंगमंच पर अग्नि और बरखा : आग और बरखा...बारिश और अग्नि मंच पर कैसे लगेंगे न? बहुत मुश्किल भी है थियेटर के मंच पर दोनों को एक साथ नाटक में देखना भी अद्भुत अनुभव होगा। निर्देशक केएस राजेंद्रन कहते हैं कि 'अग्नि और बरखा' का नाट्यशास्त्र बहुत जटिल है और किसी भी निर्देशक के लिए एक चुनौती है जो पाठ को मंच पर जीवंत करना चाहता है। नाटक में कई कथाएं एक साथ चलती हैं। मुझे पौराणिक पात्रों के माध्यम से मानवता के शाश्वत सवालों से निपटना पसंद है। यह नाटक दरअसल एक पुरानी लोककथा पर आधारित है। महान ऋषि रैभ्या, उनके पुत्रों परवसु व अरवसु, परवसु के चचेरे भाई यावक्री, परवसु की पत्नी विशाखा और अरवसु की प्रेमिका नीतिलई पर केंद्रित है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे शक्ति का दंभ और पद की लालसा लोगों को सही पथ से भटकाती है। कहानी के अंत में भगवान इंद्र का प्रकट होना... सत्य एवं प्रेम की विजय ही इसका मूल है। इस नाटक को प्रतिष्ठित नाटककार गिरीश कर्नाड ने लिखा है।

बकौल केएस राजेंद्रन दिल्ली में इसके मंचन का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि यहां थियेटर प्रेमियों में समकालीन रंगमंच को लेकर खासी समझा है। वो नाटक के बाद परिचर्चा सेशन में भी भाग लेते हैं। इस नाटक को दर्शक 22 दिसंबर को देख सकेंगे।

सहेज का सरगम... : सांत्वना निगम द्वारा निर्देशित यह नाटक आपको चार भागों में देखने को मिलेगा। हर भाग एक अलग कहानी और संदेश को अपने अंदर समेटे होगा। पहला भाग...पहली पौडी, दूसरा... बस सिर्फ इसलिए, तीसरा...भाग पंख और चौथा...साथ होगा। पहली पौडी में बच्चों की पढ़ाई के खर्चे नहीं उठा सकने वाले अभिभावकों का दर्द झलकेगा। जिसमें तीन मुख्य किरदार दिखेंगे। एक मध्यम आयु की महिला, उसकी दादी और दादा। दादी मां, अपनी पोती को पुरानी बातें बताती हैं, जब उनके रिश्तेदारों के घर से आने वाले कई विद्यार्थी और दूर के रिश्ते वाले बच्चे भी परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार का मुखिया पेशे से वकील और स्वभाव से कंजूस है, लेकिन नए विद्यार्थियों को भोजन और आवास देने की बात पर वह खुशी से सहमत हो जाता है।

बस सिर्फ इसलिए : इसमें एक आदमी और औरत अपने लंबे समय के रिश्ते को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि आदमी ने धोखा दिया है और वह क्षमा भी चाह रहा है। औरत ने अपने पति से रिश्ता खत्म करने की हिम्मत की है और वह अपने दो बच्चों के साथ अकेले रह रही है।

पंख : इसमें एक महत्वाकांक्षी महिला का संघर्ष झलकेगा। जो समाज में आजाद और अर्थपूर्ण स्थिति चाहती है, केवल अपने पति के अधीन नहीं रहना चाहती है। महिलाओं से घृणा करने वाला उसका पति उनकी आकांक्षा को पसंद नहीं करता है और उसकी उड़ान को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इससे उस महिला को और दृढ़ता मिलती है। आखिरी प्रस्तुति अंश होगी। जिसमें एक दंपती कहानी के केंद्र बिंदु में होगा। यह दंपती छोटी-छोटी बातों पर झगड़ता रहता है। तमाम मनमुटाव के बावजूद उनके बीच एक प्रेम की डोर है जो उन्हें बांधे रहती है। ऐसा अक्सर आजकल मेट्रो सिटी के कल्चर में सामान्यत देखने को मिलता है।

रिश्तों का मलाल : साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी गजब के होते हैं। इस नाट्य उत्सव में आपको एक नाटक ऐसा भी देखने को मिलेगा। कौशिक बोस निर्देशित 'कंपंशन' (मलाल) नाटक खेला जाएगा। जिसमें अपराधबोध या उसके अभाव की मानवीय मनोदशा दर्शकों को रोमांचित कर देने वाली है। इस नाटक में हत्या की सनसनीखेज भुलाए जा चुके मामले सामने आते हैं और इसका सेतु बनती है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दीपा थॉमस। अपने एक रोगी ओमर के उपचार के दौरान वो हत्या के इन सब मामलों से मुखातिब होती है। इलाज के आगे बढ़ते रहने के साथ नए नए रहस्य सामने आते हैं। व्यक्तिगत तौर पर दीपा अपने असफल विवाह से संघर्ष कर रही है और अपनी बेटी त्रिशा के साथ रिश्ते में भी। पेशेवर तौर पर वह उन मामलों को सुलझाने के लिए समय के विपरीत चल रही है और अपने परिजनों के जीवन को खतरे में डाल देती है। इसका मंचन 24 दिसंबर को होगा।

- आयोजन : पन्ना भरत राम थियेटर फेस्टिवल
- कहां : श्रीराम सेंटर फॉर परफार्मिंग आर्ट।
- कब : 21 से 29 दिसंबर, प्रतिदिन शाम सात बजे से।
- प्रवेश : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा प्रवेश, प्रति व्यक्ति 100 रुपये।
- नजदीकी मेट्रो स्टेशन : मंडी हाउस।

अगले साल से 15 दिन का हो सकता है आयोजन

श्रीराम सेंटर फॉर परफार्मिंग आर्ट के वर्तमान एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की मां पन्ना भारत राम के नाम से आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत 2014 से हुई है। पदाधिकारी बताते हैं कि पहले यह सात दिनों तक आयोजित होता था। लेकिन दर्शकों की मांग पर बाद में इसे नौ दिन कर दिया गया। अगले साल 15 दिवसीय होने की उम्मीद है। इस उत्सव में नाटकों का चयन दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किया जाता है।

क्रिसमस ईव : हो जाओ रेडी

जायका

इस बार क्रिसमस वीक डेज में है तो क्यों न क्रिसमस पार्टी इसी वीकेंड पर कर ली जाए? वैसे भी दिल्ली-एनसीआर के रेस्त्रां में क्रिसमस पार्टी का पूरा माहौल बन चुका है। रंग, रोशनी फूड और ड्रिंक्स के साथ सैंटा तैयार है। वैसे भी यहां के रेस्त्रां क्रिसमस पार्टियों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। रेस्त्रां लाल, हरे और सफेद रंगों से सजने लगे हैं। क्रिसमस ईव को सेलीब्रेट करने के लिए रेस्त्रां अनपल्ग्ड कोर्टयार्ड पूरी तरह तैयार है। इसमें वेज व नॉनवेज स्टार्टर्स के साथ बिरयानी व डेजर्ट इसे खास बना रहे हैं। इसके साथ अनलिमिटेड लिकर क्रिसमस पैकेज में दिया जा रहा है। यहां पर डीजे नील लोगों को अपनी बीट्स पर झुमाने को तैयार हैं। रेस्त्रां के दिनेश अरोड़ा ने बताया कि इसके लिए क्रिसमस थीम पर रेस्त्रां को सजाया जा रहा है जिसमें क्रिसमस ट्री से लेकर स्नो और गिफ्ट्स की सजावट लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सीपी स्थित इस रेस्त्रां में 24 दिसंबर को फोर प्लस फोर स्टार्टर, वन प्लस वन बिरयानी और एक डेजर्ट दिया जा रहा है।

हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स : कड़कती ठंड में गरमागरम डिशेज व हैंडक्राफ्टेड कॉफ्टेड मॉकटेल्स का मजा लेना है कि तो ला रोका बेहतरीन क्रिसमस पार्टी प्लेस साबित होने वाला है। योरोपियन, इटालियन से लेकर एशियन डिशेज में भारतीय मसालों का तड़का भी मिलेगा। स्पाइसी कॉर्न, एवोकाडो टोस्टस, हाढ शेल टाको, पॉर्क, पॉन्डीचेरी पॉर्क बैली, ट्रफल मशरूम रिसोटो, लैंब मलय करी, होल रोस्टेड चिकन व स्पाइसी वेज पेट पार्टी का मजा दोगुना कर देंगे। म्यूजिक कलाकार बिड्जी की धुनों पर थिरकने का भी अवसर मिलेगा।

त्योहार पारंपरिक का अनुभव : अगर क्रिसमस का पारंपरिक अनुभव व स्वाद लेना हो तो कैफे देहली हाइट्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। यहां पर खानपान के साथ इसकी सजावट देखने लायक होगी। बटरफ्लाई थीम पर हुई सजावट व फूड के इनोवेटिव प्रिपरेशन से आपकी पार्टी में जान आ जाएगी। यहां पर सीक्रेट सैंटा आकर आपको सरप्राइज गिफ्ट्स भी देगा। रोस्टेड वेजीटेबल्स बिस्क, ताजे अंगूर, एवोकाडो और अरुगला सैलेड, श्रिंप के अलावा स्टार्टर में इंडोनेशियन स्टाइल में बने हल्के से मैरीनेटेड एशियन चिकन स्क्यूवर्स को मॉजरेला चीज और स्पाइसी राटाटुई से भरे मार्गेरेटा रिसोटो बॉल्स के साथ परोसा जाएगा। मेन कोर्स में लैंब शैंक को फॉन्डैंटो पोटैटो के साथ सर्व किया जाएगा। इसके अलावा मक्खनी पालक के साथ शैलो रेड वाइन पार्टी का मूड को बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही है। क्रिसमस की खास पारंपरिक डिश में रोस्टेड टर्की भी यहां मिलेगी। नए आने वाले आलू से बनी की डिश ग्रिल्ड फिल स्वाद की नई दुनिया में ले जाएगी। व्हाइट वाइन क्रीम सॉस में डूबे स्पार्गस, कॉटेज चीज सालसा वर्दे व ग्रिल्ड मशरूम, पेन्ने पोमोडोरिनी सॉस व पास्ता रेलेनो पंपकिन के साथ गोट चीज रेविओली के साथ ही डेजर्ट में किटकैट चीज केक बच्चों से लेकर बड़ों तक को त्योहार के पारंपरिक रंग में रंग देगा। रमी पुडिंग केक बी मिलेगा जो कि रम व वनीला के साथ बनाया जा रहा है। रेस्त्रां के संचालक विक्रांत बतरा का कहना है कि क्रिसमस का पारंपरिक फील देने के लिए वे सजावट से लेकर मिठाइयों तक में नए प्रयोग कर रहे हैं।

पारंपरिक स्वाद के साथ मॉडर्न ट्विस्ट : क्रिसमस पर अगर आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न फूड का टेस्ट एक साथ चाहते हैं तो इस अवसर के लिए पापाया बेस्ट है। दिल्ली के इस रेस्त्रां में सुशी से लेकर ऐसपर्गस क्रीम चीज, स्पाइसी वेजीज, हॉरेंसो गोमी सैलेड, तपस विद क्रिस्पी कॉर्न कर्ड, तोफू, हॉटडॉग व डिमसम को क्रिसमस पार्टी मेन्यू में शामिल किया गया है। चिकन व कॉर्न की डिश और कैंटोनीज चिकन सूप इस मौसम में आपको बेहद पसंद आएगा।

टर्की व चिंजाबी प्रॉन, रबड़ी जलेबी का स्वाद : अगर आप क्रिसमस का खास बनाने के लिए बुफे की तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह तलाश पूरी होगी रेस्त्रां 'मेड इन पंजाब' में। यहां पर क्रिसमस की डिशेज का पंजाबी अंदाज आपको खूब भाएगा। यहां के क्रिसमस मील बुफे में वेज चिकन मांचाऊ सूप से शुरुआत होगी। यहां के लाइव चाट काउंटर पर पर फुचका चाट, दही गुझिया, सैलेड, तीन मिर्च पनीर टिक्का, चिंजाबी (चाइनीज व पंजाबी), तंदूरी टर्की, चिंजाबी प्रॉन, पिश मेथी मलाई, जैसे स्टार्टर के साथ मेन कोर्स में दाल एमआइपी, पिंडी छोले, मक्की की रोटी और सरसो का साग, रोगन जोश, बटर चिकन, रायता और रोटी परोसी जाएंगी।

– **प्रियंका दुबे मेहता**

प्लम केक। सौजन्य : हिल्टन, साकेत

क्रिसमस केक। सौजन्य : ला-ओपेरा।

रेड स्नैपर

डिशेज व ड्रिंक्स के खास कॉम्बीनेशन

क्रिसमस की विशेष मॉकटेल्सइस क्रिसमसी बयार में बेहतरीन व्यंजनों के साथ अगर लिकर का स्वाद न मिले तो त्योहार का पूरा लुत्फ कैसे लिया जा सकेगा। दिल्ली के फर्जी कैफे में क्रिसमस मॉकटेल्स नेम जिंजर ब्रेड यगनॉग, समालेदार वाइन, विंटर ब्लिस, रम व स्पाइस्ड ऐप्पल सांगरियाके अलावा नॉन अलकोहलिक लोग क्रैनबैरी सांगरिया और क्रीमी नॉग का आनंद उठा सकते हैं। बेहतरीन स्वाद के साथ टेस्टी ड्रिंक्स का स्वाद लेना है तो ऐरोसिटी और जनपथ स्थित प्लम बाय बेंटचेयर आपके लिए परफेक्ट पार्टी प्लेस साबित होगा। द ग्रिंच, मेयर मे हू, वैसे भी स्पेशल एक्जोटिक कॉकटेल हैं। इस त्योहार की शाम इन ड्रिंक्स का स्वाद इन रेस्त्रां में लिया जा सकता है। रेस्त्रां संचालक प्रियंका सुखीजा का कहना है कि यहां पर त्योहार को यादगार बनाने के लिए डिशेज व ड्रिंक्स के खास कॉम्बीनेशन बनाए गए हैं।

टर्की विद बेबी पोटैटो। सौजन्य : हिल्टन, साकेत

दिल्ली के भटूरे और कबाब... रहते हैं हमेशा याद

बातचीत

मुस्कुराहट है इनकी पहचान। हर उम्र के प्रशंसक हैं इनके हजार। 200 से ज्यादा फिल्में की और टीवी शो से बनाई अलग ही पहचान। हम बात कर रहे हैं अभिनेता टीकू तलसानिया की। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में आई फिल्म प्यार के दो पल से की थी। फिल्मी करियर में तमाम तरह के किरदार निभाए लेकिन लोग आज भी उन्हें उनके कॉमेडी रोल्स के लिए जानते हैं। टीकू लंबे अर्से बाद दिल्ली में थियेटर कर रहे हैं। 'तेरा क्या होगा वालिया' का मंचन में मंडी हाउस में इसी रविवार इन्हें मंचन करते देख सकते हैं। इरी नाटक समेत दिल्ली से जुड़े किस्सों पर **टीकू तलसानिया** से **संजीव कुमार मिश्र** ने विस्तार से बातचीत की प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

● परिवार में सभी डॉक्टर रहे, शायद आपसे भी यही उम्मीद रही होगी, लेकिन आप कलाकार बन गए?

मेरे परिवार में कई डॉक्टर रहे। पिता, मामा और बहनें सब डॉक्टर। मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। क्योंकि डॉक्टरी के लिए बहुत पढ़ाई करनी होती है। पढ़ना मुझे पसंद नहीं था। खैर, इसी जद्दोजहद के बीच एक दिन एक परिचित ने प्रोफेशनल थियेटर में काम करने के लिए बुलाया। बस फिर क्या था, तभी से एक्टिंग का ऐसा चस्का लगा कि इसे ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया।

● सुना है आपके थियेटर ज्वाइन करने के बाद पिता को यह टेंशन थी कि आपकी शादी हो भी पाएगी या नहीं?

जी हां, ये सच है। हमारे गुजराती समाज में यदि कोई अभिनेता बन जाता है तो उसे नाटकिया कहकर बुलाते है। यह माना जाता है कि यह थियेटर आदि में ही काम कर पाएगा और कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई अभिभावक लड़की देना पसंद नहीं करता था। हांलाकि, मैं लकी हूं। मेरी शादी सकुशल हुई और दो खूबसूरत बेटे हैं।

● शुरुआत गुजराती थियेटर से हुई, फिर हिंदी सिनेमा में आना हुआ। कैसे?

मैंने शुरुआत गुजराती थियेटर से की थी। एक दिन एक नाटक का मंचन हो रहा था, जिसका नाम किसमिश था। यह एक अंग्रेजी प्ले का एडाप्शन था। नाटक देखने फिल्म निर्देशक कुंदनशाह आए थे। नाटक के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि एक फिल्म में काम करोगे? इस तरह 'ये जो जिंदगी है' में रोल मिला। मैंने हामी भर दी...यहीं से सिलसिला शुरू हो गया।

तेरा क्या होगा वालिया

● नाटक : तेरा क्या होगा वालिया, ● कहां : कमानी आडिटोरियम, मंडी हाउस।, ● कब : 21 दिसंबर शाम तीन बजे एवं सात बजे। 22 दिसंबर दोपहर 1 बजकर 30 मिनट बजे।, ● प्रवेश : आनलाइन बुकिंग द्वारा, टिकट 399 रुपये से शुरू।, ● नजदीकी मेट्रो स्टेशन : मंडी हाउस।

टीकू तलसानिया सौजन्य : आयोजक

● तेरा क्या होगा वालिया, में अपने रोल के बारे में थोड़ा बताएं?

बहुत ही दिलचस्प नाटक है। मेरा रोल दर्शकों को पसंद आएगा। एक आदमी की दो पत्नियां हैं। वो किसी तरह मैनेज कर रहा है? उसकी जिंदगी दो पत्नियों के बीच पिस जाती है। किसी तरह वो मैनेज कर रहा है लेकिन अचानक एक सड़क हादसा नाटक को रोमांचक बना देता है। क्या वालिया पकड़ा जाता है? क्या होता है उसके साथ? ये तो आप संडे को थियेटर जाकर देखिएगा।

● पहली बार दिल्ली आने या किसी खास आयोजन से जुड़ी यादें साझा करना चाहे तो?

मैं ट्रेवलर हूं। बाइक से यात्राएं करता रहता हूं। लद्दाख तक जा चुका हूं। पहली बार दिल्ली भी घूमने के लिए ही आया। फूडी बहुत हूं। दिल्ली आने पर यहां के जायके बहुत पसंद आए। छोले भटूरे, कबाब...हमेशा के लिए मेरी पसंद बन गए। बहुत पहले एक सीरियल किया था, जिसका नाम था और फिक्र ने कहा...यह अखबार में फिक्र जी के प्याज के छिलके नाम के कॉलम पर आधारित थी। हमने इसकी शूटिंग दिल्ली में मई महीने में की थी। इतनी गर्मी में शूटिंग का अनुभव आज तक जेहन में कैद है।

● दिल्ली में कहां घूमना, कोई खास खाना आपको पसंद हो।

दिल्ली से अब तो दिल का रिश्ता बन गया है। यहां घूमने लायक कई जगह हैं। खाने की इतनी वैराइटी है कि कहा ही क्या जाए। मैं तो दिल्ली की हर गली घूमना चाहता हूं।

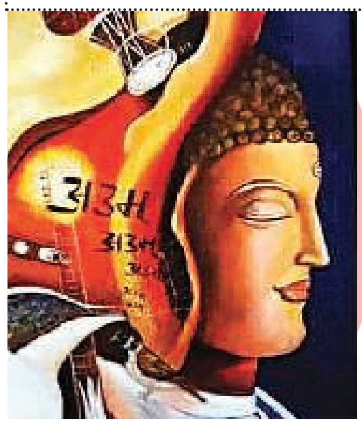

समूह प्रदर्शनी

यह समूह प्रदर्शनी कई मायने में खास है। शो में 26 कलाकारों की 100 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यही नहीं कला के विभिन्न आयाम...कला का संरक्षण, कला की अवधि, कला के माध्यम से संचार, वाणिज्यिक कला, सामाजिक संदेश के लिए कला, फ्यूजन कला और कला सामग्री के चयन आदि विषयों पर परिचर्चा का भी आयोजन होगा।
- कहां : आर्टिजन आर्ट गैलरी, आइटीओ।
- कब : 20–22 दिसंबर, सुबह दस से शाम सात बजे तक। ● प्रवेश : निश्शुल्क

खास इंटीरियर के बीच

रोहित बल द्वारा डिजाइन इसका इंटीरियर ग्राहकों को पसंद आता है। यहां नार्थ इंडियन जायका लाजवाब है। जिसका स्वाद चखने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि एनसीआर से लोग आते हैं। यहां की दाल मखनी, बटर चिकन, बिरयानी और पनीर, चिकन कस्तूरी कबाब, फिश अमृतसरी सरीखे कई आइटम बेहतरीन है।
- कहां : कनॉट प्लेस। ● कब : दोपहर 12 से रात 11 बजे तक। ● प्रवेश : प्रति दो व्यक्ति लगभग 1600 रुपये।

मसाला हाउस

आचारी अरबी, दही के कबाब, पनीर टिक्का, परातवाला पनीर, अनारकली टिक्की, डोरा कबाब, तवे की चाप, कुरकुरे चाट, टिक्की समेत कई जायके बेमिसाल है। यहां का शांत वातावरण और लाजवाब जायका आपका सप्ताहांत यादगार बना देगा।
- कहां : 4, सुंदर नगर।
- कब : दोपहर 12–शाम पांच, शाम साढ़े छह से रात साढ़े ग्यारह बजे तक।
- प्रवेश : प्रति दो व्यक्ति लगभग 1800 रुपये।

एनएमडीसी को मिले दो कोल ब्लॉक

नई दिल्ली : देश की अग्रणी लौह अयस्क निकालने वाली कंपनी एनएमडीसी को झारखंड में दो कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इससे सरकारी कंपनी को कोल वाशरीज स्थापित करने में मदद मिलेगी। कंपनी के चेयरमैन और एमडी एन. ब्रजेंद्र कुमार ने बताया कि कोल मंत्रालय ने कंपनी को दो कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं। यह ब्लॉक रोहने और टोकीसूद में स्थित हैं। इनमें रोहने ब्लॉक की क्षमता 19.10 करोड़ टन और टोकीसूद की क्षमता 80 लाख टन प्रति वर्ष है। (प्रेट्र)

बहुत कम टैरिफ में अत्यधिक उपभोग की स्थिति ने देश के टेलीकॉम सेक्टर को संकट में डाल दिया है। हमें एजीआर पर राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।

— सुनील मित्तल, चेयरमैन, भारती इंटरप्राइजेज

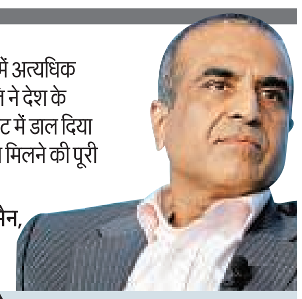

सेंसेक्स 41,673.92 ▲ 115.35	निफ्टी 12,259.70 ▲ 38.05	सोना प्रति दस ग्राम ₹ 38,804 ▲ ₹12	चांदी प्रति किलोग्राम ₹ 45,649 ▼ ₹65	डॉलर ₹71.03 ▲ ₹0.06	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 66.24

उद्योग जगत ने वित्त मंत्री से मांगी कारोबारी माहौल में सुधार की सौगात

मशविरा ▶ चुनिंदा उद्योगपतियों ने की बजट-पूर्व विमर्श के तहत सीतारमण से मुलाकात

नीतिगत निश्चितता और स्थिरता को बताया उद्योगपतियों ने अहम मुद्दा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों संग बजट पूर्व बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (दाएं) से बातचीत करते आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती। एएनआइ

देश ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भले ही काफी सुधार किया हो, लेकिन उद्योगपतियों की सबसे बड़ी मांग यही है कि घरेलू स्तर पर कारोबार के माहौल में सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। उद्योग जगत का मानना है कि सरकार को नीतिगत स्थिरता पर भी ध्यान देना होगा। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के कुछ नामी गिरामी उद्यमियों के साथ बजट पूर्व बैठक की थी जिसमें अलग-अलग स्तर पर इन बातों को रखा गया।

देश के दो बड़े उद्योग संगठनों सीआइआइ और एसोचैम के प्रमुखों ने परोक्ष तौर पर उद्योग जगत के बेहतर प्रदर्शन के लिए ज्यादा आजादी की मांग की। उद्योगपतियों ने कहा कि टैक्स से लेकर नीति तक में यदि सुनिश्चितता बनी रहे तो कारोबारियों को लंबी अवधि की अपनी रणनीति बनाने में आसानी होगी। उद्योग जगत उम्मीद कर रहा है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री इन बातों पर ध्यान देंगी।

सीआइआइ के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने अपने प्रजेंटेशन में ऑटोमोबाइल, खनन, रिटेल और ऊर्जा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां नीतियों में अस्थिरता की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (केफ-1) का उदाहरण दिया जिसे फरवरी, 2017 में लागू किया, जबकि दूसरे देशों में इसके लिए कम से कम सात वर्षों का समय दिया गया था। उनका कहना था कि रिटेल कारोबार में सोर्सिंग के नियमों में लगातार बदलाव किए गए और इसी तरह से रिन्युएबल एनर्जी कंपनियों के लिए नियम बदले जा रहे हैं। नियमों में इस तरह की अस्थिरता से निवेशकों का भरोसा नहीं बन पाता। सीआइआइ ने कारोबार के स्तर पर पैदा हो रही कई तरह की कानूनी दिक्कतों की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि उद्योग जगत से जुड़े कानूनी मसलों पर त्वरित फैसले की व्यवस्था करना मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। जाहिर है कि बड़े उद्योग कॉरपोरेट टैक्स की रेट में की गई कटौती से आगे भी बहुत कुछ चाहते हैं

दो वर्ष पहले तक देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती टेलीकॉम के मुखिया सुनील भारती मित्तल ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, 'मैं सिर्फ एक मांग लेकर इस बैठक में शामिल हुआ और वह है भारत में कारोबार करने को आसान बनाना। उद्योग जगत को काम करने की ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए ताकि वह अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। वित्त मंत्री और उनके सहयोगियों ने हमारी बात बहुत मन से सुनी है और मुझे उम्मीद है कि आगामी बजट में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा।' मित्तल ने दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति पर वित्त मंत्रालय को पूरी जानकारी दी। एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका ने भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बहुत काम हुआ है लेकिन अंतिम स्तर पर राज्यों की तरफ से कुछ कदम उठाने की जरूरत है। गोयनका समूह के संजीव गोयनका ने भी बताया कि कारोबार करने के माहौल में सुधार करने से बड़ा मुद्दा अभी कोई नहीं है। हालांकि वे सरकार की तरफ किए गए प्रयासों से काफी संतुष्ट दिखे। एसोचैम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी ने बैठक में फंड कमी कमी, जीएसटी और कराधान को रियल एस्टेट सेक्टर की तीन बड़ी समस्याओं के तौर पर गिनाया।

बड़े राज्यों का जीएसटी कंपेंसेशन बोझ 70,000 करोड़ तक

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष में नौ बड़े राज्यों का जीएसटी कंपेंसेशन 70,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। रेटिंग एजेंसी इकरा द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र और केरल समेत नौ बड़े राज्यों का जीएसटी कंपेंसेशन दोगुना बढ़कर 60 से 70 हजार करोड़ रुपये के बीच पहुंचने का अंदेशा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों को मिलने वाली राशि का वक्त उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। भुगतान में देरी के चलते इन राज्यों के कैश-फ्लो में दिक्कत आ सकती है।

▶ **इकरा ने कहा- राज्यों को मिलने वाली इस राशि का वक्त उनके लिए होगा महत्वपूर्ण**

रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों को केंद्र से मिलने वाला टैक्स (सीटीडी) भी 59 हजार से 77 हजार करोड़ के बीच रहने की आशंका है, जो कि बजटीय प्रावधान से कम है। इस वजह से चालू वित्त वर्ष में राज्यों के सामने राजस्व की चुनौती खड़ी हो गई है। इससे राज्यों के पूंजीगत खर्च में भी कमी हो सकती है। इकोनॉमिक सुस्ती और जीएसटी रेट में कटौती से अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान जीएसटी कलेक्शन में 3.7 परसेंट की कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष में राज्यों द्वारा जुटाया जाने वाला राजस्व (एसजीएसटी)जीएसटी एक्ट 2017 के सुरक्षित स्तर से कम रहने की आशंका है। इस वजह से राज्यों को केंद्र से अधिक कंपेंसेशन की जरूरत होगी।

नहीं बढ़ेगी 'सबका विश्वास' स्कीम की तारीख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **31 दिसंबर है आखिरी तारीख, सरकार इसे बढ़ाने के मूड में नहीं**

▶ **उत्पाद शुल्क और सर्विस टैक्स के लंबित विवादों के निपटारे को आई थी स्कीम**

▶ **अब तक 29,557.3 करोड़ रुपये के 55,693 आवेदन सरकार को मिले**

मुकदमेबाजी और विवादों में लंबित पड़े उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए आई 'सबका विश्वास' स्कीम की अवधि को आगे बढ़ाने के मूड में सरकार नहीं है। इस स्कीम की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। वित्त मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी आयुक्तों से कहा है कि शेष बची अवधि में ज्यादा से ज्यादा करदाताओं को शामिल करने पर गंभीरता से काम करें।

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 16 दिसंबर को सभी प्रधान व मुख्य आयुक्तों और प्रधान महानिदेशकों को इस विषय में एक पत्र लिखा गया है। उन्हें कहा गया है कि वे आखिरी तारीख से पहले ज्यादा से ज्यादा संभावित करदाताओं की तलाश कर उन्हें स्कीम के दायरे में लाने की कोशिश करें। मंत्रालय का मानना है कि यह स्कीम करदाताओं और विभाग दोनों के लिए फायदेमंद है। करदाताओं को बरसों से लंबित मामलों से एक ही बार में छुटकारा मिल जाएगा और विभाग को रेवेन्यू की प्राप्ति हो जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक इस वर्ष पहली सितंबर को शुरू हुई इस स्कीम में अभी तक 55,693 आवेदन मिल चुके हैं। इन सभी आवेदनों में 29,557.3 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इस स्कीम में करदाताओं की रुचि को देखते हुए सीबीआइसी ने अधिकारियों से मुहिम की रफ्तार को और तेज करने और 31 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा करदाताओं तक पहुंचने को कहा है।

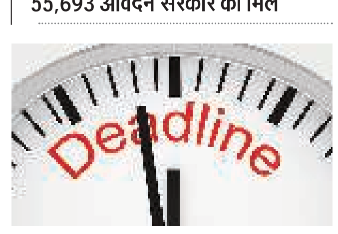

प्रतीकात्मक

अधिकारियों का मानना है कि अभी तक की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि करदाता भी अधिक समय तक मुकदमेबाजी में उलझे नहीं रहना चाहते। स्कीम शुरू करते वक्त 1.83 लाख मामलों में सरकार के 3.6 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए थे।

स्कीम के तहत 50 लाख रुपये और इससे कम के मामलों में 70 परसेंट तक की राहत देने का प्रावधान है। 50 लाख रुपये से अधिक की राशि पर राहत की दर 50 परसेंट रखी गई है। यह राहत उन लंबित मामलों के लिए है जिनमें करदाता 30 जून 2019 तक ड्यूटी की राशि स्वीकार कर चुके हैं।

न्यूज गैलरी

प्याज जमाखोरों के खिलाफ राज्यों ने बरती ढिलाई : तोमर

नई दिल्ली : प्याज की आपूर्ति घटने के कारण इसके भाव में उछाल की समस्या एक हद तक नियंत्रण में रखी जा सकती थी, यदि राज्य सरकारों ने जमाखोरों के खिलाफ प्रभावी तरीके से कार्रवाई की होती। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बार-बार जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गुजारिश की। उन्हें कहा गया कि सीमा से बाहर उनके स्टॉक का प्याज जब्त करें और बाजार में जारी करें। लेकिन, यह सब करने की जगह वे (मुख्यमंत्रियों ने) इस मसले को राजनीतिक रंग देने में लगे रहे। तोमर से जब पूछा गया कि पिछले दो महीनों से देश में प्याज की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए तो उन्होंने जवाब दिया, 'सरकार ने फौरन प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी और बफर स्टॉक का माल बाजार में जारी करना शुरू कर दिया।' (आइएएनएस)

कपड़ा उद्योग हब बनाने में मदद देगी नई टेक्सटाइल पॉलिसी

नई दिल्ली : सरकार ने कहा है कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी से देश को कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात का हब बनाने में मदद मिलेगी। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नीति-निर्माण में जुटी है। जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी में गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल और हाथ से बने सूत के उत्पादन और निर्यात पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार ने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए टेक्सटाइल मंत्रालय की वेबसाइट पर 15 जनवरी तक सुझाव दिए जा सकते हैं। (प्रेट्र)

माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में हैं बहुत संभावनाएं : केपीएमजी

कोलकाता : केपीएमजी ने कहा है कि देश के माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में तेज वृद्धि की क्षमता है। इस कंसल्टेंसी कंपनी ने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान माइक्रोफाइनेंस सेक्टर ने 48 परसेंट की तेज गति से विकास किया है। लेकिन यह अभी बाजार के एक चौथाई हिस्से तक ही अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सका है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी इस सेक्टर के विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। सेक्टर के विकास में देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्से की भागीदारी बहुत अधिक है। सेक्टर के 35 परसेंट लोन पोर्टफोलियो इन्हीं क्षेत्रों से हैं। (प्रेट्र)

छोटी अवधि के बांड्स जारी कर रहा रिजर्व बैंक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **ज्यादा ब्याज वाले लंबी अवधि के बांड्स को खरीदने और उनकी जगह कम परिपक्वता अवधि के बांड्स होंगे जारी**

कम अवधि की ब्याज दरों को रेपो रेट व अन्य वैधानिक दरों को घटाकर नीचे लाने की कोशिश के बाद केंद्रीय बैंक की नजर अब लंबी अवधि की ब्याज दरों पर है। इस उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो फार्मूला दूसरे बैंक आजमाते हैं उसे ही आरबीआइ ने भी अपनाया है। गुरुवार को आरबीआइ ने वर्ष 2029 में परिपक्व होने वाले 10 हजार करोड़ रुपये के बांड्स को खरीदने और वर्ष 2020 में परिपक्व होने वाले 10 हजार करोड़ रुपये के बांड्स जारी किए हैं।

आरबीआइ का यह फैसला लंबी अवधि के बांड्स पर ब्याज दरों को कम करेगा। अभी रेपो रेट और लंबी अवधि के बांड्स पर देय ब्याज दर का अंतर 1.50 फीसद के करीब है। इस बारे में केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि इससे बाजार में तरलता की स्थिति बेहतर होगी। बैंकिंग सेक्टर में उक्त प्रक्रिया को ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से जाना जाता है। लंबी अवधि के सरकारी बांड्स पर देय ब्याज दरों को घटा कर केंद्रीय बैंक लंबी अवधि के ब्याज दरों को कम करने का रास्ता साफ करते हैं क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दरों के आधार पर ही लंबी अवधि के कर्ज की दरों के लिए भी ब्याज दरों का निर्धारण होता है। बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का कहना है कि अगर आरबीआइ इस तरह का आपरेशन ट्विस्ट आगे भी जारी रखता है तो यह 20 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के फिक्स्ड होम लोन या 10 वर्ष से ज्यादा अवधि के दूसरे लोन की दरों को कम करने में मदद करेगा। इससे उद्योग जगत को भी लंबी अवधि के कर्ज मौजूदा दर से कम दरों पर मिलने की राह खुलेगी।

केंट ने उतारा जीरो वाटर वेस्टेज आरओ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वाटर प्योरिफायर ब्रांड केंट ने 'जीरो वाटर वेस्टेज टेक्नोलॉजी' के साथ बाजार में एक नया वाटर प्योरिफायर पेश किया है। अपनी तरह के पहले जीरो वाटर वेस्टेज केंट आरओ में पानी को इस तरह रिसाइकल किया जाएगा कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। आरसी प्रोसेस के माध्यम से शुद्ध पानी की प्राप्ति भी 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकती है।

पारंपरिक वाटर प्योरिफायर में एक लीटर शुद्ध पानी के लिए तीन लीटर अतिरिक्त पानी बर्बाद हो जाता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी में चार लीटर पानी से दो लीटर शुद्ध पानी मिलता है और शेष दो लीटर पानी को रिसाइकल कर लिया जाता है। इस तरह इस टेक्नोलॉजी वाले आरओ से पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। केंट आरओ सिस्टम्स के चेयरमैन महेश गुप्ता ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी से पुराने आरओ सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा सकेगा। पुराना सिस्टम इस्तेमाल कर रहे ग्राहक कुछ राशि देकर अपने आरओ को जीरो वाटर वेस्टेज सिस्टम में तब्दील करा सकते हैं।

महंगे प्याज के कारण सस्ता नहीं हुआ कर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्याज की आसमान छूती कीमतों के चलते भी आरबीआइ ने मौद्रिक नीति की पिछली समीक्षा बैठक में ब्याज दर नहीं घटाई थी। गुरुवार को जारी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के ब्योरे से यह जानकारी सामने आई। ब्योरे के मुताबिक एमपीसी की बैठक में प्याज की महंगाई पर प्रमुखता से चर्चा हुई थी। घरेलू बाजार में इस साल सितंबर से प्याज के भाव बढ़ने शुरू हुए और दिल्ली में हाल-फिलहाल तक प्याज के भाव 130-140 रुपये प्रति किलो रहे।

मुख्य नीतिगत दरें यथावत रखने के पक्ष में एमपीसी की बैठक में वोटिंग के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था, 'सितंबर-अक्टूबर में खुदरा कीमतों के हिसाब से महंगाई दर तेजी से बढ़ी। सब्जियों के भाव में अचानक तेज बढ़ोतरी इसकी वजह रही, क्योंकि देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश की चलते खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके कारण खासतौर पर प्याज के भाव तेजी से बढ़े।' इससे पहले देश में महंगाई करीब-करीब नियंत्रण में थी और अर्थव्यवस्था सुस्त रहने की वजह से रेपो रेट में एक बार फिर कटौती की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन, इस बीच महंगाई बढ़ने और आगे चलकर यह समस्या और गहराने की आशंका की वजह से पांच दिसंबर को छह सदस्यों वाली एमपीसी ने नीतिगत दरें यथावत रखने का फैसला किया।

अहमदाबाद में एक व्यापारी के गोदाम में प्याज की छंटाई करती महिला। एपी

दास के अलावा एमपीसी के अन्य सभी सदस्यों-चेतन घाटे, पामी दुआ, रवींद्र एच. ढोलकिया, मिशेल देवब्रत पात्रा और विभू प्रसाद कानूनगो ने एकमत से रेपो रेट 5.15 प्रतिशत पर यथावत रखने के पक्ष में वोट किया। बैठक में दास की राय से सहमति जताते हुए आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर कानूनगो ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में बेमौसम बारिश के कारण कुछ खास फसलों को काफी नुकसान हुआ और इस वजह से मंडियों में इनकी आवक प्रभावित हुई।

उन्होंने कहा, 'नतीजतन थोड़े समय के लिए मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन गड़बड़ा गया और खासतौर पर प्याज महंगा हो गया।'

धीरे-धीरे सुधरेंगे हालात

केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि कुछ अनिश्चितताओं के कारण अर्थव्यवस्था और महंगाई का आउटलुक प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, 'प्याज की कीमतों में उछाल के कारण पिछले तीन महीनों में खाने-पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने का असर अन्य चीजों पर भी हो सकता है। जैसे ही लेट खरीफ की फसल मंडियों में पहुंचने लगेगी, धीरे-धीरे यह ट्रेंड पलटने की उम्मीद है।'

रियल एस्टेट सेक्टर में नौ प्रतिशत बढ़ा निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस वर्ष जनवरी से अब तक भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश लगभग नौ प्रतिशत बढ़कर 43,780 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म कोलियर्स ने यह अनुमान लगाया है।

▶ **43,780 करोड़ रुपये तक पहुंच गया सेक्टर में निवेश**

▶ **अगले वर्ष निवेश और बढ़ने की उम्मीद**

▶ **कॉमर्शियल और ऑफिस प्रॉपर्टी पर रहेगा फोकस**

प्रतीकात्मक

कोलियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल रियल एस्टेट सेक्टर में हुए कुल निवेश में 46 प्रतिशत यानी 19,900 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी अकेले ऑफिस प्रॉपर्टी की रही। रिपोर्ट में कहा गया है, '2018 के मुकाबले 2019 के दौरान भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश 8.7 प्रतिशत बढ़कर 620 करोड़ डॉलर (करीब 43,780 करोड़ रुपये) हो गया।' इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस साल घरेलू रियल एस्टेट सेक्टर में जितना निवेश हुआ, उसमें निवेश फंडों की हिस्सेदारी लगभग 78 प्रतिशत रही, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

2020 में निवेश और बढ़ने की उम्मीद : कोलियर्स ने अनुमान लगाया है कि 2020 के दौरान भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़कर 46,170 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। कोलियर्स इंटरनेशनल इंडिया के एमडी एवं चेयरमैन सैंकी प्रसाद ने कहा, 'हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निर्माणाधीन ऑफिस प्रॉपर्टी समेत तमाम ऐसी संपत्तियों पर गौर करें, जिनकी आइटी सेक्टर से जुड़े बाजारों में बड़ी मांग हो सकती है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर निवेशकों को जोरदार मौके दे रहे हैं।'

ऑफिस प्रॉपर्टी पर फोकस : कंसल्टेंट फर्म ने उम्मीद जताई है कि निवेशक अगले तीन वर्षों तक कॉमर्शियल ऑफिस प्रॉपर्टी पर फोकस जारी रखेंगे। इस क्षेत्र में मजबूत मांग और किराये में बढ़ोतरी की उम्मीद इसकी वजह होगी। मुंबई और दिल्ली और बेंगलुरु इस मामले में आकर्षक बाजार बने रहेंगे।

बेंगलुरु ने दिल्ली को पछाड़ा : इस साल रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के मामले में दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) को पछाड़कर बेंगलुरु अब मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस दौरान बेंगलुरु में 4,650 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में इस साल सबसे ज्यादा 25 प्रतिशत निवेश हुआ है।

कार के फास्टैग से टोल नाके क्रॉस कर रहे ट्रक

नईदुनिया, मुरैना

▶ **मप्र के मुरैना के छौंदा टोल नाके से पकड़े गए उत्तराखंड और यूपी के ट्रक**

▶ **एनएचएआइ को कंपनी ने भेजी रिपोर्ट, ताकि सभी को किया जा सके सचेत**

अब फास्टैग से भी टोल कंपनियों को फटका लगाया जा रहा है। देशभर में टोल टैक्स के भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था 'फास्टैग' को ठीक से लागू करने में जुटे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) और टोल कंपनियों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल भारी व्यावसायिक वाहनों पर कारों और हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए जारी किए गए फास्टैग लगाकर उन्हें देशभर के टोल नाकों से निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना के छौंदा टोल नाके पर बीते दिन में ऐसे तीन ट्रक पकड़े गए हैं।

ट्रकों व अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों पर 250 रुपए से लेकर 450 रुपये तक टोल टैक्स वसूला जाता है। लेकिन कार व हल्के वाहनों के फास्टैग से ट्रक मात्र 45 से 90 रुपए चुकाकर टोल नाकों से आगे बढ़ रहे हैं। मुरैना के छौंदा टोल नाके पर एक ट्रक गुजरा जो उत्तराखंड का था और दिल्ली से टोल नाके पार करते हुए वहां तक पहुंच गया था। यह ट्रक सात-एक्सल था, जिसका टोल टैक्स 420 रुपये बनता है, लेकिन ट्रक जब लेन में आया तो सिर्फ 105 रुपये ही उसके खाते से कटे। इस पर टोल कर्मचारियों को शक हुआ। कर्मचारियों ने पाया कि सात-एक्सेल के लिए निर्धारित टैग की जगह यह ट्रक हल्के व्यावसायिक वाहन का टैग लगाए हुए था। इसी तरह पकड़ा गया एक अन्य ट्रक आगरा से टोल नाके पार करते हुए छौंदा टोल पर पहुंचा था। यह ट्रक तीन-एक्सल का था। इस हिसाब से ट्रक के टैग से 240 रुपये कटने थे, लेकिन सिर्फ 65 रुपये ही कटे। कर्मचारियों ने जांच की तो कार का फास्टैग लगा मिला। पकड़े गए सभी टैग वाहनों की विंड स्क्रीन पर प्लास्टिक टेप से चिपके हुए थे।

जीएसटी कटौती का फायदा देने में ब्रांड्स बेहद सुस्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : जीएसटी में कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलने की रफ्तार बहुत सुस्त है। लोकल सर्किल के कंज्यूमर सर्वे में कहा गया है कि ब्रांड्स अपने ग्राहकों की रेट कटौती का लाभ देने में देर लगा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक केवल 12 परसेंट उत्तरदाता ऐसे थे, जिन्होंने कहा कि रेट कट का पूरा लाभ ग्राहकों को मिल रहा है।

इस दौरान 23 परसेंट लोगों ने कहा कि ग्राहकों को आंशिक तौर पर इसका लाभ दिया जा रहा है, जबकि 47 परसेंट लोगों ने माना कि जीएसटी रेट कट का लाभ ग्राहकों को नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान 18 परसेंट उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इसको लेकर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। टैक्स सुधारों को नजर में रखते हुए देश के टैक्स ढांचे को आसान बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू किया गया था। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद इसकी काउंसिल ने कई बार बैठक की है।

लेखाजोखा

सेंसेक्स का रिकॉर्ड सफर जारी, पिछले सत्र में भी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए थे प्रमुख सूचकांक, एनर्जी, ऑटो, टेक, और आइटी सेक्टर में हुई जमकर खरीदारी

सेक्टर-केंद्रित शेयरों में उछाल से बाजार चमके

मुंबई, प्रेट्र : सेक्टर-केंद्रित स्टॉक्स में निवेशकों के रुझान के दम पर घरेलू शेयर बाजार एक और सत्र में रिकॉर्ड सफर पर बढ़ते रहे। एनर्जी, आइटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में जमकर हुई खरीदारी के चलते दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 115.35 अंक उछाल के साथ 41,673.92 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 38.05 अंक की तेजी देखी गई। यह 12,259.70 के सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। पिछले सत्र में भी प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए थे।

सेंसेक्स पैक में यस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 6.74 परसेंट का उछाल आया। टीसीएस, टाटा मोटर्स, एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आरआइएल के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए। वहीं वेदांता, एचडीएफसी, सन फार्मा और इंडसइंड बैंक के शेयरों में 2.26 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में टेलीकॉम, एनर्जी, ऑटो, टेक, ऑयल एंड गैस और आइटी सेक्टर के शेयर 1.98 परसेंट तक की बढ़त दर्ज करने में सफल रहे। हालांकि कैपिटल गुड्स, फाइनेंस, रियल्टी और बैंक के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अभियोग से जुड़ी खबरों के चलते शुरुआत में निवेशक कुछ सावधान दिखे। लेकिन बाद में विदेशी निवेशकों द्वारा जमकर निवेश किया गया, जिससे मुख्य सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में सफल रहे। पिछले सत्र में भी विदेशी निवेशकों ने घरेलू बाजारों में 1,836.81 करोड़ रुपये का निवेश किया था। गुरुवार को एशिया के अन्य बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। वहीं यूरोप के शेयर बाजार सत्र के शुरुआती कारोबार में लाल निशान पर रहे।

प्रतीकात्मक

यस बैंक की रेटिंग में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडिया रेटिंग्स और इकरा ने यस बैंक की रेटिंग गिरा दी है। बैंक द्वारा फंड जुटाने में अनिश्चितता के चलते रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग में कमी की है। इंडिया रेटिंग्स ने बताया कि फंड जुटाने के मामले में यस बैंक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। बैंक की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने की वजह से असेट पर नियंत्रण और देनदारियों में चूक का खतरा पैदा हो सकता है। इस दौरान रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि यस बैंक की इन्सॉल्वेंसी प्रोफाइल भी कमजोर हुई है। गौरतलब है कि बैंक ने 52 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना पेश की थी। लेकिन यह अब तक इस पर आगे नहीं बढ़ सका है।

टाटा ग्रुप के शेयरों में रिकवरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले सत्र में गिरावट के बाद गुरुवार को टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तीन परसेंट तक का इजाफा दर्ज किया गया। हालांकि शुरुआती कारोबार में ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर दबाव में रहे। टीसीएस 2.83 प्रतिशत, टाटा मोटर्स 2.55, टाटा कॉफी 0.98 और टाटा ग्लोबल बेवरेज के शेयर 0.67 प्रतिशत सुधार के साथ बंद हुए। टाटा स्टील, टाइटन और टाटा कम्यूनिकेशन के शेयर भी बढ़त दर्ज करने में सफल रहे। गौरतलब है कि एनक्लैट द्वारा टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद ग्रुप के शेयरों में दबाव देखा गया था। एनक्लैट ने टाटा संस को निर्देश दिया है कि वह मिस्त्री को चेयरमैन के पद पर वापस बहाल करे।

आइएलएफएस को एजुकेशन बिजनेस बेचने की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएलएंडएफएस को एजुकेशन बिजनेस बेचने की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया की देखरेख कर रहे पूर्व जस्टिस डीके जैन ने दी है। हालांकि जस्टिस जैन ने कहा है कि कंपनी को अभी एनसीएलटी की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद एनक्लैट और एनसीएलटी के निर्देशानुसार बोली की राशि को एस्क्रो अकाउंट में जमा करानी होगी।

▶ **रिजॉल्यूशन प्रक्रिया की देखरेख कर रहे पूर्व जस्टिस डीके जैन ने दी मंजूरी**

आइएलएंडएफएस का एजुकेशन बिजनेस स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड नाम से चलता है, जिसे कैरियर प्वाइंट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (सीपीपीपीएल) के हाथों बेचने का प्रस्ताव रखा गया है। कंपनी के कर्जदाता इसके लिए पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। इस सौदे के बाद कर्ज संकट से जूझ रही आइएलएंडएफएस को करीब 600 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। इससे पहले कंपनी के एजुकेशन बिजनेस के लिए सीपीपीपीएल ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। ई-वोटिंग के जरिये कंपनी के करीब 78 परसेंट कर्जदाताओं ने सीपीपीपीएल की बोली को मंजूरी दी थी। इस सौदे में सीपीपीपीएल पर एसआइएल के डेट की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा इक्विटी के लिए कुछ भुगतान भी किया जाएगा। गौरतलब है कि कर्ज भुगतान करने में असमर्थ रहने के कारण आइएलएंडएफएस इस समय रिजॉल्यूशन प्रक्रिया से गुजर रही है।

प्रतीकात्मक

पाक का दावा : भारत सीमा पर तैनात कर रहा मिसाइलें, करेगा हमला

- डरे हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को 7वीं बार लिखी चिट्ठी
- कुरैशी का दावा, भारत कश्मीर से ध्यान भटकाने को मिसाइल दागेगा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सातवीं बार चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि भारत ने सीमा पर विभिन्न प्रकार के मिसाइल तैनात किए हैं और वह कश्मीर की 'गंभीर स्थिति' से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है।

बता दें कि इसका बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि सीमा पर स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है और सेना उससे निपटने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भारतीय सेना प्रमुख के इस बयान से डर गया है और सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। 12 दिसंबर को सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम अपनी 7वीं चिट्ठी में कुरैशी ने कहा कि भारत गुप्त अभियान के तहत उस पर हमला कर सकता है। भारतीय कार्रवाई से दक्षिण एशिया में पहले से चल रहे तनाव और बढ़ेंगे। पाक

शाह महमूद कुरैशी। फाइल

विदेश कार्यालय की तरफ से बुधवार को जारी बयान के मुताबिक, कुरैशी ने अपनी चिट्ठी में दावा किया कि भारत ने विभिन्न रेंज व क्षमता वाले टेस्टिंग मिसाइल को तैनात किया है। इससे पहले कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को विगत एक, छह, तेरह अगस्त और 26 सितंबर के अलावा 16 व 31 अक्टूबर को भी चिट्ठियां लिखी थीं।

हाल के महीनों में कुरैशी ने अपनी चिट्ठियों के जरिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से कश्मीर की स्थिति पर बात की। कुरैशी ने इसके साथ ही यूएनएमओजीआइपी को क्षेत्र में मजबूत करने की अपनी अपील को दोहराया। उधर, भारत ने यह बार-बार कहा है कि यूनाइनटेड नेशंस मिलेट्री ऑब्जरवर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान (यूएनएमओजीआइपी) जिसकी स्थापना 1949 में हुई है, उसने अपनी सार्थकता खो दी है और शिमला समझौते के बाद अप्रासंगिक हो गई है।

इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जनरल रावत के बयान को घरेलू मुद्दों से विश्व का ध्यान हटाने का हटाने की नाकाम कोशिश बताया। पाकिस्तान सेना ने उल्टे भारत पर आरोप लगाया है कि नियंत्रण रेखा पर लगातार दो दिन से गोलाबारी हो रही है। इसमें पाकिस्तान के दो नागरिक घायल हुए हैं।

ट्रंप के रिजॉर्ट में अवैध रूप से दाखिल चीनी महिला गिरफ्तार

वाशिंगटन, एपी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट मार-ए-लागो क्लब में अवैध रूप से दाखिल होने पर एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया गया है। इस साल इस तरह की यह दूसरी घटना है। मार-ए-लागो क्लब फ्लोरिडा राज्य के पाम बीच पर स्थित है। इससे पहले गत मार्च में यूजिंग झांग (33) नामक चीनी महिला को रिजॉर्ट में अवैध रूप से दाखिल होने पर पकड़ा गया था। सितंबर में उसे इसके लिए एक माह की सजा भी सुनाई गई थी।

पाम बीच पुलिस के अनुसार, निजी क्लब के सुरक्षाकर्मियों ने बुधवार को जिंग लू (56) नामक महिला को रोका और उसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह दोबारा परिसर में घुस गई और फोटो लेने लगी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। लू के वीजा की जांच करने पर पता चला कि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप और उनका परिवार रिजॉर्ट में मौजूद नहीं था। संभावना जताई जा रही है कि सप्ताहांत के दौरान ट्रंप मार-ए-लागो पहुंचेंगे और वहीं छुट्टियां बिताएंगे।

हांगकांग के आंदोलनकारियों की अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अपील

- काले कपड़ों में एक हजार लोगों ने मिशनों के सामने जुलूस निकाल ज्ञापन दिया
- प्रदर्शनकारियों ने कहा-यहां जो रहा है वह स्थानीय मसला नहीं है

हांगकांग, रायटर : हांगकांग के लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने विदेशी सरकारों से समर्थन की गुजारिश की है। इसके लिए उन्होंने गुरुवार को कई देशों के राजनयिक मिशनों के बाहर मार्च किया और अमेरिका का अनुसरण करते हुए मानवाधिकार कानून बनाकर चीन पर दबाव डालने की अपील की।

अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कानून बनाकर हांगकांग का विशेष व्यापारिक सहयोगी का दर्जा बनाए रखने के लिए वहां मानवाधिकारों के पालन के संबंध में हर साल विदेश मंत्रालय का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। काले कपड़े पहने और फेस मास्क लगाए करीब एक हजार आंदोलनकारियों ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जापान और कनाडा के वाणिज्य दूतावासों के आगे से मार्च करते हुए वहां अपनी मांग से संबंधित पत्र दिए। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के मिशनों में वहां नियुक्त उच्च राजनयिक अधिकारी बाहर आए और उन्होंने आंदोलनकारियों से उनके ज्ञापन लिए।

हांगकांग में गुरुवार को विदेशी दूतावासों की ओर मार्च निकालते प्रदर्शनकारी। रायटर

इन अधिकारियों ने आंदोलनकारियों की मांग के समर्थन स्वरूप उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। मार्च में शामिल सुकी चान ने कहा, हांगकांग में जो हो रहा है वह यहां का स्थानीय मसला नहीं है। यह मानवाधिकारों और लोकतंत्र से जुड़ा आंदोलन है। विदेशी सरकारों को समझना चाहिए किस तरह से इस महानगर में अधिकारों का दमन हो रहा है। हम आंदोलन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन चाहते हैं। आंदोलन की गति बरकरार रहे, इसके लिए यह समर्थन जरूरी है। उल्लेखनीय है कि हांगकांग में छह महीने से ज्यादा समय से लोकतंत्र की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है।

महाभियोग के पक्ष में भारतवंशी सांसदों ने दिया मत

प्रथम पृष्ठ से आगे

भारतीय मूल के सभी चारों डेमोक्रेटिक सांसदों राजा कृष्णमूर्ति, एमी बेरा, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल ने महाभियोग के पक्ष में मतदान किया। मतदान के बाद कृष्णमूर्ति ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है।'

सीनेट में राह आसान नहीं : 100 सदस्यीय सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में है। विश्लेषकों का कहना है कि इस सदन में महाभियोग गिर सकता है क्योंकि दो तिहाई बहुमत से महाभियोग पारित होने पर ही ट्रंप को पद से हटाया जा सकता है। इस सदन में रिपब्लिकन के 53 और डेमाक्रेटिक पार्टी के 45 सदस्य हैं।

अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मंजूरी देती स्पीकर नैंसी पेलोसी। रायटर

जजों ने फैसले में लिखा, चौक पर तीन दिन टांगा जाए परवेज मुशर्रफ का शव

देशद्रोह मामला ▸ पाक के पूर्व सैन्य शासक को विशेष अदालत ने सुनाई है मौत की सजा

कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश, भगोड़े दोषी को पकड़कर सजा पर करें अमल

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में मौत की सजा सुनाने वाले जजों ने 167 पेज के अपने फैसले में लिखा है कि अगर सजा दिए जाने से पहले ही मुशर्रफ की मौत हो जाती है तो उनके शव को यहां लाया जाए और इस्लामाबाद के डी-चौक पर तीन दिन तक फंदे से लटकाकर रखा जाए। मुशर्रफ को यह सजा 2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल थोपने, संविधान को निलंबित रखने और जजों को हिरासत में रखने के मामले में सुनाई गई है। वह 2016 से दुबई में रह रहे हैं।

पाकिस्तान टुडे अखबार ने इस फैसले को विस्तार से प्रकाशित किया है। उसमें लिखा है, 'हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश देते हैं कि वे भगोड़े दोषी को पकड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि कानून के तहत सजा पर अमल किया जाए। अगर वह मृत पाए जाते हैं तो उनका शव लाकर इस्लामाबाद के डी-चौक पर तीन दिन लटकाया जाए।' जजों ने यह भी लिखा है कि तत्कालीन कोर कमांडर कमेटी के साथ ही सुरक्षा में तैनात रहने वाले दूसरे सभी वर्दीधारी अधिकारी भी दोषी के कृत्य में समान रूप से लिप्त थे। विशेष अदालत ने बीते मंगलवार को दो-एक के बहुमत से मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। वह मृत्युदंड पाने वाले पाकिस्तान के पहले पूर्व जनरल हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत ने सजा सुनाते समय कहा था कि वह अपना विस्तृत फैसला आगामी 48 घंटों में जारी करेगी।

दुबई के एक अस्पताल में उपचाराधीन पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने गुरुवार को वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। एएफपी

मुशर्रफ ने मौत की सजा को बताया व्यक्तिगत प्रतिशोध

इस्लामाबाद, एपी : पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने देशद्रोह मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को व्यक्तिगत प्रतिशोध करार दिया है। मुशर्रफ ने फिलहाल दुबई में शरण ले रखी है। उनकी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ओर से बुधवार को जारी एक वीडियो संदेश में पूर्व सैन्य शासक ने कहा, 'इस तरह के फैसले का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, जिसमें ना तो आरोपित और ना ही उसके वकील को अपने बचाव में कुछ कहने की इजाजत दी गई। मैं यही कहूंगा कि संविधान के तहत इस केस की सुनवाई की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई व्यक्तिगत प्रतिशोध के तहत की गई।' किसी का नाम लिए बगैर 76 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख ने कहा, 'जिन लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया, वे उच्च पदों पर आसीन हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।' बता दें कि मुशर्रफ 2016 से दुबई से नहीं लौटे हैं।

क्यूबा को 40 साल बाद मिलेगा पहला प्रधानमंत्री

- राष्ट्रपति कानेल इसी हफ्ते करेंगे पीएम के नाम का एलान
- पांच उपराष्ट्रपतियों या मंत्रियों में से किसी एक की बतौर पीएम हो सकती है नियुक्ति

हवाना, एएफपी : क्यूबा में 40 साल से ज्यादा समय बाद प्रधानमंत्री का पद बहाल होने जा रहा है। राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कानेल इसी हफ्ते प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम का एलान करेंगे। क्यूबा के नए संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर संसद की मुहर जरूरी है। इसके लिए शुक्रवार और शनिवार को संसद सत्र बुलाया गया है।

नए प्रधानमंत्री के नाम पर पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकृति भी लेनी होगी। यह हालांकि अभी साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री पद पर किसकी नियुक्ति होगी। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति कानेल अपने पांच उपराष्ट्रपतियों या मंत्रियों में से किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर सकते हैं।

फिदेल कास्त्रो थे अंतिम पीएम : क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो ने 1976 में राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया था। साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरोधी रहे कास्त्रो ने क्यूबा में शोषण के खिलाफ लड़कर साल 1959 में कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित की थी। वह तब से 1976 तक देश के प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2008 तक राष्ट्रपति रहने के बाद उन्होंने यह पद अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंप दिया था।

मिगेल डियाज-कानेल। फाइल

प्रधानमंत्री के लिए ये हैं मानक : गत अप्रैल में अपनाए गए नए संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए कई मानक तय किए गए हैं। इस पद के उम्मीदवार के लिए 605 सदस्यीय नेशनल असेंबली का सदस्य होना आवश्यक है। जन्म से क्यूबा का नागरिक होने के साथ ही उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि साल 2013 में मिगेल डियाज-कानेल क्यूबा के उप राष्ट्रपति बने थे। इन्हें फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो का दाहिना हाथ माना जाता है।

डॉक्टरों और नर्सों को ब्रिटेन देगा फास्ट ट्रैक वीजा

- महारानी ने अभिभाषण में बताई सरकार की प्राथमिकता
- योजना का भारतीय डॉक्टरों और नर्सों को हो सकता है बड़ा फायदा

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में गुरुवार को सरकार ने उस योजना को अंतिम रूप दे दिया जिसमें दुनिया भर से डॉक्टरों और नर्सों को फास्ट ट्रैक वीजा देकर बुलाया जाएगा। यह योजना जल्द ही लागू कर दी जाएगी। सरकारी नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) में डॉक्टरों और नर्सों की कमी के चलते यह योजना बनाई गई है। इस योजना का बड़ा फायदा भारतीय डॉक्टरों और नर्सों को होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस वीजा को एनएचएस वीजा का नाम दिया है। इसकी चर्चा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने की थी। गुरुवार को संसद में महारानी के अभिभाषण में भी इस योजना का जिक्र किया गया। इस अभिभाषण में महारानी सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करती हैं। इससे पुष्टि हो गई कि जॉनसन सरकार आने वाले कुछ हफ्तों में इस नई वीजा योजना को लागू करने जा रही है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कहा कि सरकार के इस कदम से नेशनल हेल्थ सर्विस को ताकत मिलेगी। नए डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा सहयोगी ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाएंगे।

जॉनसन सरकार अपने पूर्व कार्यकाल और 12 दिसंबर से पूर्व चुनाव प्रचार में दक्ष पेशेवरों को प्राथमिकता के आधार पर वीजा देने की घोषणा कर चुकी है। वह दुनिया के सबसे अच्छे पेशेवरों को ब्रिटेन बुलाना चाहती है। इस सिलसिले में कई कदम भी उठाए गए हैं। माना जा रहा है कि ब्रेक्जिट प्रक्रिया को जारी रखते हुए सरकार अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए आव्रजन नीति में बदलाव करेगी। यह सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

बोरिस जॉनसन। एएफपी

राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटिश राजनीति में रूसी दखल से किया इन्कार

- कहा, वह देशहित में काम करते हैं, कौन क्या कहता है परवाह नहीं
- ब्रिटिश पीएम की प्रशंसा की, कहा-लोगों में ब्रेक्जिट को लेकर बेहतर समझ विकसित

मॉस्को, रायटर : ब्रिटेन की राजनीति में रूसी दखल की चर्चाओं को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खारिज किया है। उलटे उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने ब्रेक्जिट को लेकर जनता के साथ बेहतर समझ विकसित की है जो उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं कर पाए। ब्रिटेन में रह रहे पूर्व रूसी जासूस और उसकी बेटी पर रासायनिक हमले के बाद पिछले साल रूस और ब्रिटेन के संबंध बहुत बिगड़ गए थे।

हाल ही में प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा था कि ब्रिटिश राजनीति में रूसी हस्तक्षेप की संसदीय जांच समिति की 50 पेज की रिपोर्ट उन्हें मिल गई है। समय आने पर सरकार उसे सार्वजनिक करेगी। पुतिन वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले भी उनका कार्यालय इस तरह के हस्तक्षेप से इन्कार करता रहा है। पुतिन ने कहा, कई देशों में ऐसी चर्चा वह अक्सर सुनते रहे हैं। लेकिन अगर कोई रूस के अंदरूनी हालात के बारे में अंदाजा लगाए तो क्या इसे हस्तक्षेप माना जाएगा। आप रूस के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, बदले में वह भी वैसा ही करेगा। अगर आप इसे हस्तक्षेप मानते हैं तो मानते रहिए। लेकिन वास्तव में हम ऐसा कुछ नहीं करते।

बीबीसी रिपोर्टर के यह कहने पर कि जॉनसन उनकी (पुतिन की) तुलना हैरी पॉटर की फिल्म के डॉबी से करते हैं। जवाब में पुतिन ने कहा, वह इन बातों की परवाह नहीं करते। जो काम रूस के हित में होते हैं, वे उन्हें करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कौन उनके विषय में क्या कहता है, इसकी वह परवाह नहीं करते। पुतिन ने उम्मीद जताई कि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन रूस के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाना चाहेगा।

अमेरिका में बाल श्रम मामले में फंसी एपल और गूगल

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : एपल, अल्फाबेट (गूगल की पैरेंट कंपनी), डेल, माइक्रोसाफ्ट और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को नामजद करते हुए अमेरिका में एक मामला दर्ज कराया गया है। यह मामला कांगो में कोबाल्ट के खनन में बच्चों से काम लेने से संबंधित है।

वाशिंगटन के जिला अदालत में इसी सप्ताह अंतरराष्ट्रीय अधिकार एडवोकेट्स ने 14 अज्ञात पीड़ितों की ओर से यह मामला दायर कराया है। पीड़ितों में कोबाल्ट खनन के दौरान सुरंग या दीवार ढहने से मारे गए बच्चों के अभिभावक या ऐसी दुर्घटना में घायल या दिव्यांग हो गए बच्चे शामिल हैं। कांगो में दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट भंडार है। खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले बच्चों को रोजाना एक या दो डॉलर मजदूरी दी जाती है।

बता दें कि बाल मजदूरी पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। बच्चों को इससे बचाने के लिए सरकारों के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में भी बाल मजदूरी के मामले प्रकाश में आना बेहद चिंता की बात है।

आग से ऑस्ट्रेलिया में आफत

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जंगलों में लगी आग की वजह से सात दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। सिडनी के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के कई इलाके आग की चपेट में हैं। गुरुवार को तामूर शहर के निकट गोल्ड ह्यूम हाईवे के किनारे लगी आग पर काबू करने की कोशिश में जुटे ग्रामीण अग्निशमन सेवा (आरएफएस) के कर्मी। यहां घरों को आग से भारी नुकसान होने की सूचना है। रायटर

मॉस्कोवासी अचरज में, 133 साल में दिसंबर इस बार सबसे गर्म

चिंताजनक

18 दिसंबर को छह डिग्री रहा तापमान, सामान्य तौर पर होता है -6.2 डिग्री सेल्सियस, अनुमान है कि यह बेमौसमी गर्मी अटलांटिक महासागर की ओर से आई है

मॉस्को, रायटर : मॉस्कोवासी अचरज में हैं कि इस साल सर्दियां कहां चली गईं। दिसंबर में हर साल रूस की राजधानी बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन इस साल दिसंबर का महीना यहां 133 साल में सबसे गर्म है।

एक पेंशनभोगी लुदमिला बिरयुकोवा ने कहा, 'यह हमारी सर्दियां नहीं है। यह कहीं और से आई है।' मॉस्को में हर साल इन दिनों जब बर्फ की चादर बिछी होती है और इमारतों से बर्फ की लड़ियां लटक रही होती हैं तो इस साल 18 दिसंबर को तापमान छह डिग्री सेल्सियस रहा। फॉबोस मौसम केंद्र की एलेना वोसोल्यूक ने बताया कि पिछली बार दिसंबर महीने में मॉस्को इतना गर्म 18 दिसंबर, 1886 को था जब तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। रूसी मौसम अनुसंधान केंद्र के मुताबिक, सामान्य तौर पर 18 दिसंबर को तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस होता है।

मॉस्को में यह बेमौसम गर्मी अटलांटिक महासागर की ओर से आई है और इस बार नए साल की छुट्टियों में बर्फबारी का नहीं बल्कि बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

मौसम में आए इस बदलाव से लोग ही नहीं बल्कि पेड़-पौधे भी अचरज में हैं। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के औषधि उपवन में स्नोड्रॉप और रोडोडेंड्रन के पौधों को भी वसंत आगमन का भ्रम हो गया है। उपवन के प्रधान माली एंटन डुबिन्युक ने बताया, 'पौधे भी इससे (गर्म मौसम से) धोखा खा गए हैं और उन्होंने मान लिया है कि वसंत आ चुका है। जब सर्दियां आएंगी तो यह फूल झड़ जाएंगे। लिहाजा स्पष्ट है कि वसंत में ये फूल नहीं खिलेंगे।' उपवन में टहलते हुए उन्होंने बताया, 'मैं यहीं जन्मा हूं और पूरी जिंदगी यहीं बिताई है। हम वास्तविक सर्दियों के अभ्यस्त हैं।'

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मौसम की बदलती प्रवृत्ति ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण देखने को मिल रही है। यदि वास्तव में ऐसा है तो हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन : सिडनी में गुरुवार को हजारों जलवायु कार्यकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के सिडनी स्थित आधिकारिक आवास के सामने मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और प्रधानमंत्री से छुट्टियां रद करने की मांग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों प्रदूषण की हालात बेहद चिंताजनक हो गई है। एएफपी

अमेरिका में भारतवंशी सिख टैक्सी चालक पर हमला

- पीड़ित की बेटी ने कहा, वेशभूषा के कारण की गई बुरी तरह पिटाई
- एक पखवाड़े से भी कम समय में दूसरी बार सिख टैक्सी चालक पर हमला

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतवंशी सिख टैक्सी चालक पर कबाब सेंकने वाले लोहे के सरिये से घातक हमला किया गया। यह हमला उस समय हुआ जब वह काम खत्म करने के बाद अपने घर के सामने कैब पार्क कर रहे थे। उनकी बेटी ने वेशभूषा के कारण हमला किए जाने का आरोप लगाया है। एक पखवाड़े के भीतर यह दूसरी वारदात है, जब किसी सिख पर हमला किया गया है।

एसएफगेट डॉट कॉम के अनुसार, बलजीत सिंह सिद्धू (57) उबर कैब चालक हैं। वह रविवार को काम खत्म करने के बाद कैलिफोर्निया के रिचमंड स्थित अपने घर के बाहर कैब पार्क कर रहे थे। तभी उनकी कैब के पास आकर एक व्यक्ति ने लाइटर मांगा। सिद्धू के मना करने पर वह चला गया। केटीवीयू टीवी चैनल को सिद्धू ने बताया, 'दोबारा लौटने पर उसने मुझसे कहा कि उसके पास पांच डॉलर हैं और वह टैक्सी से कहीं जाना चाहता है। मुझे यह बात संदिग्ध लगी और मैंने कहा कि शिफ्ट खत्म हो चुकी है। यह सुनकर वह चला गया और थोड़ी ही देर में लौटकर लोहे के सरिये से सिर पर हमला कर दिया।' उसने सिद्धू को कैब से निकालकर उनका गला दबाने की कोशिश भी की। सिद्धू की बेटी गगनजोत ने कहा, 'उनकी पगड़ी उतरी हुई थी और पूरा चेहरा खून से लथपथ था। यह काफी भयावह था।' गगनजोत ने कहा कि उसके पिता पर सिर्फ उनकी वेशभूषा के कारण हमला किया गया। उल्लेखनीय है कि पांच दिसंबर को वाशिंगटन में भी भारतवंशी सिख टैक्सी चालक पर हमला किया गया था।

सभी खिलाड़ियों के लिए जरूरी है कि वे चयन प्रक्रिया से गुजरें। यही एक सही प्रक्रिया है।
— कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता

गुवाहाटी में खेलो इंडिया की तैयारियों की विवेचना

नई दिल्ली, आइएएनएस : खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे सत्र में हिस्सा लेने वाले सभी राज्यों के शेफ द मिशन प्री टूर्नामेंट बैठक के लिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। शेफ द मिशन असम की राजधानी में स्थानीय आयोजन समिति द्वारा स्थापित मूलभूत संरचनाओं का आकलन कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे सत्र का आयोजन गुवाहाटी में 10 से 22 जनवरी, 2020 के बीच होना है। इन खेलों में 20 से अधिक स्पर्धाओं में खिलाड़ी शिरकत करेंगे।

KHELO INDIA

कैपिटल्स–आरसीबी में टक्कर, कमिंस को ले उड़ी केकेआर

आइपीएल नीलामी में इविन लुइस, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा और यूसुफ पठान जैसे क्रिकेटरों को नहीं मिले खरीदार, युवाओं पर रही टीमों की विशेष नजर

खेल संवाददाता, कोलकाता: आइपीएल के 2020 सत्र की नीलामी के हीरो रहे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस को खरीदने के लिए पहले दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर के बीच टक्कर चली लेकिन कोलकाता ने एंट्री मारी और उन्हें 15.5 करोड़ में अपने नाम कर लिया। कमिंस ने अब तक आइपीएल के 16 मैचों में 17 विकेट चटकाए हैं। वह इससे पहले भी कोलकाता टीम का हिस्सा रहे हैं और दिल्ली और मुंबई की टीमों में भी शामिल रहे हैं।

मैक्सवेल की घर वापसी: नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ही ग्लेन मैक्सवेल रहे, जिसे किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा। मैक्सवेल की घर वापसी हुई है। मैक्सवेल को लेकर दिल्ली और पंजाब में काफी देर तक बोली चली, हालांकि पंजाब की जेब भारी होने के कारण आखिरकार वह मैक्सवेल को खरीदने में सफल रही। मैक्सवेल मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों से क्रिकेट से दूर थे और उन्होंने हाल ही में वापसी की है। वह अब तक 69 आइपीएल मैचों में 1,397 रन बना चुके हैं जिनमें छह अर्धशतक शामिल हैं।

मॉरिस भी रहे महंगे खिलाड़ी: ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड व वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का भी बोलबाला रहा। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस तीसरे स्थान पर रहे, जिसे बेंगलूर ने 10 करोड़ में खरीदा, वहीं कैरेबियाई तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल ने चौथा स्थान हासिल किया, जिसे पंजाब ने 8.50 करोड़ में अपने नाम किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन कूल्टर नाइल को मुंबई ने 8 करोड़, भारत दौरे पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिमरोन हेटमायर को दिल्ली ने 7.75 करोड़, आइपीएल में 150 विकेट चटका चुके अनुभवी स्पिनर पीयूष चावला को चेन्नई ने 6.75 करोड़ और इंग्लैंड को पिछला 50 ओवर का विश्व कप जिताने वाले कप्तान इयान मोर्गन को कोलकाता ने 5.25 करोड़ में खरीदा।

आठ टीमों ने इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव

क्रिस लिन (मुंबई, 2 करोड़), इयोन मोर्गन (कोलकाता, 5.25 करोड़), रॉबिन उथप्पा (राजस्थान, 3 करोड़), जेसन रॉय (दिल्ली, 1.5 करोड़), आरोन फिंच (बेंगलूर, 4.4 करोड़), ग्लेन मैक्सवेल (पंजाब, 10.75 करोड़), क्रिस वोक्स (दिल्ली, 1.5 करोड़), पैट कमिंस (कोलकाता, 15.50 करोड़), सैम कुर्रन (चेन्नई, 5.50 करोड़), क्रिस मॉरिस (बेंगलूर, 10 करोड़), एलेक्स कैरी (दिल्ली, 2.4 करोड़), जयदेव उनादकट (राजस्थान, 3 करोड़), नाथन कूल्टर (मुंबई, 8 करोड़), शेल्डन कॉटरेल (पंजाब, 8.5 करोड़), पीयूष (चेन्नई, 6.5 करोड़), राहुल त्रिपाठी (कोलकाता, 60 लाख), विराट सिंह (हैदराबाद, 1.9 करोड़), प्रियम गर्ग (हैदराबाद, 1.9 करोड़), दीपक हुड्डा (पंजाब, 50 लाख), वरुण चक्रवर्ती (कोलकाता, 4 करोड़), यशस्वी जायसवाल (राजस्थान, 2.40 करोड़), अनुज रावत (राजस्थान, 80 लाख), आकाश सिंह (राजस्थान, 20 लाख), कार्तिक त्यागी (राजस्थान, 1.30 करोड़), इशान पोरेल (पंजाब, 20 लाख), एम सिद्धार्थ (कोलकाता, 20 लाख), रवि बिश्नोई (पंजाब, 2 करोड़), शिमरोन हेटमायर (दिल्ली, 7.75 करोड़), डेविड मिलर (राजस्थान, 75 लाख), सौरभ तिवारी (मुंबई, 50 लाख), मिशेल मार्श (हैदराबाद, 2 करोड़), जेम्स नीशाम (पंजाब, 50 लाख), जोश हेजलवुड (चेन्नई, 2 करोड़), बी. संदीप (हैदराबाद, 20 लाख), क्रिस ग्रीन (कोलकाता, 20 लाख), जोश फिलिप (बेंगलूर, 20 लाख), टॉम बैंटन (कोलकाता, 1 करोड़), फैबियान एलेन (हैदराबाद, 50 लाख), क्रिस जॉर्डन (पंजाब, 3 करोड़), केन रिचर्डसन (बेंगलूर, 4 करोड़), ओशाने थॉमस (राजस्थान, 50 लाख), प्रवीण तांबे (कोलकाता, 20 लाख), तरजिंदर सिंह ढिल्लन (पंजाब, 20 लाख), अनिरुद्ध जोशी (राजस्थान, 20 लाख), बलवंत सिंह (मुंबई, 20 लाख), संजय यादव (हैदराबाद, 20 लाख), मोहित शर्मा (दिल्ली, 50 लाख), पवन देशपांडे (बेंगलूर, 20 लाख), प्रभसिमरन सिंह (पंजाब, 55 लाख), तुषार देशपांडे (दिल्ली, 20 लाख), आर साई किशोर (चेन्नई, 20 लाख), मार्कस स्टोइनिस (दिल्ली, 2 करोड़), डेल स्टेन (बेंगलूर, 2 करोड़), एंड्रयू टाई (राजस्थान, 1 करोड़)

62 खिलाड़ी बिके। इनमें 33 भारतीय व 29 विदेशी हैं। इसमें 1.4 अरब 30 लाख रुपये खर्च हुए। राजस्थान ने 11, कोलकाता और पंजाब ने नौ-नौ, दिल्ली और आरसीबी ने आठ-आठ, हैदराबाद ने सात, मुंबई ने छह और चेन्नई ने चार खिलाड़ी खरीदे। कुल 332 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई गई

ये नहीं बिक पाए

हनुमा विहारी, पुजारा, यूसुफ पठान, ग्रैंडहोम, स्टुअर्ट बिन्नी, हेनरिक क्लासेन, मुश्फिकुर रहीम, नमन ओझा, कुशल परेरा, शाई होप, टिम साउथी, ईश सोढ़ी, जांपा, हेडन वाल्श, जहीर खान, मनजोत कालरा, रोहन कदम, हरप्रीत सिंह, डेनियल सैम्स, शाह रुख खान, देवधर, केएस भरत, अंकुश बैंस, विष्णु विनोद, खेजरोलिया, रिले मेरेडिथ, मिथुन सुदेशन, नूर अहमद, केसी करियप्पा, इविन लुइस, मनोज तिवारी, कोलिन इंग्राम, मार्टिन गुप्टिल, कार्लोस ब्रेथवेट, एंदिले फेलुक्वायो, कोलिन मुनरो, ऋषि धवन, बेन कटिंग, एनरिक नोर्त्जे, बरिंदर सरां, मार्क वुड, अल्जारी जोसेफ, मुस्तफिजुर रहमान, एडम मिल्ने, आयुष बदोनी, प्रवीण दुबे।

कभी गोलगप्पे बेचने वाले यशस्वी बने करोड़पति

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: मुंबई के 17 साल के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कभी अपना गुजारा करने के लिए गोलगप्पे बेचते थे, लेकिन गुरुवार का दिन उनके लिए बड़ी खुशी लेकर आया। राजस्थान रॉयल्स ने आइपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी में उनके लिए 2.40 करोड़ रुपये की बोली लगाई। जायसवाल जब उत्तर प्रदेश के भदोही से मुंबई आए थे तब उनकी उम्र महज 11 साल थी और उन्हें टेंट में रहना पड़ता था। यहीं से उन्होंने क्रिकेटर बनने के सपने को साकार किया। जायसवाल दक्षिण अफ्रीका में जनवरी-फरवरी में खेले जाने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने नीलामी में टीम के कप्तान प्रियम गर्ग (1.90 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद) को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'मैं काफी खुश हूं। मेरे लिए यह सीखने का काफी अच्छा मौका होगा। मेरे लिए अपना नाम बनाने का मंच है।' यशस्वी इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में 154 गेंद में 17 चौके और 12 छक्के से सजी 203 रन की पारी खेलकर लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे। उन्होंने सत्र में तीन शतक की मदद से 564 रन बनाए।

युवा तुर्क भी चमके

कोलकाता: दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के कप्तान प्रियम गर्ग को हैदराबाद ने 1.90 करोड़ में खरीदा। हैदराबाद ने विराट सिंह के रूप में झारखंड के युवा बल्लेबाज को भी इतनी ही रकम में अपने नाम किया। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी को 1.30 करोड़ में राजस्थान ने खरीदा।

पैट कमिंस
सत्र 2020
ऑस्ट्रेलिया
15.5 करोड़

अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों को भी मिली अच्छी कीमत

कोलकाता: नामचीन विदेशी क्रिकेटरों के बीच अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों को भी अच्छी-खासी कीमत मिल गई। कोलकाता से मुक्त किए गए स्पिनर पीयूष चावला को चेन्नई ने उनके भारी अनुभव को देखते हुए 6.75 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदा, वहीं कोलकाता में उनके साथी रहे रॉबिन उथप्पा को भी राजस्थान ने तीन करोड़ रुपये में खरीदा। तमिलनाडु के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को कोलकाता ने चार करोड़ में खरीदा। वरुण को पिछली नीलामी में पंजाब ने 8.4 करोड़ में अपने नाम किया था। पिछले साल सबसे ज्यादा 8.4 करोड़ में बिके जयदेव उनादकट को तीन करोड़ से संतोष करना पड़ा। राजस्थान ने ही उनादकट को फिर से खरीदा।

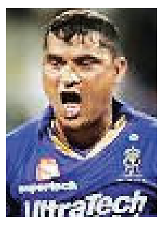
प्रवीण तांबे • ट्विटर

आइपीएल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी को कोलकाता ने खरीदा

कोलकाता: कोलकाता नाइटराइडर्स ने आइपीएल के सबसे उम्रदराज सक्रिय खिलाड़ी प्रवीण तांबे पर भरोसा जताते हुए उन्हें 20 लाख रुपये में खरीदा है। 48 वर्षीय इस लेग स्पिनर ने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अब तक 33 मैच खेलकर 28 विकेट लिए हैं। तांबे ने 41 वर्ष की उम्र में 2013 में आइपीएल में पदार्पण किया था। 8 अक्टूबर, 1971 को मुंबई में जन्मे तांबे ने 2014 में इसी कोलकाता टीम के खिलाफ हैट्रिक लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। तांबे टी-10 लीग में भी शिरकत कर चुके हैं और इस फॉर्मेट में एक पारी में पांच विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं।

2018 में 11.5 करोड़ और 2019 में 8.4 करोड़ रुपये में राजस्थान ने जयदेव उनादकट को खरीदा था। इस बार भी उन्हें राजस्थान ने तीन करोड़ रुपये देकर खरीदा

48 वर्ष 72 दिन की उम्र में बिकने वाले आइपीएल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने प्रवीण तांबे। 20 लाख में केकेआर ने खरीदा

01 मैच इस घरेलू सत्र में रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने तमिलनाडु के लिए खेला है जिसमें उन्होंने तीन ओवर में बिना किसी विकेट के 35 रन लुटाए। इसके बावजूद केकेआर ने उन्हें चार करोड़ में खरीदा

प्रत्येक सत्र के सबसे महंगे खिलाड़ी (रकम रुपयों में)

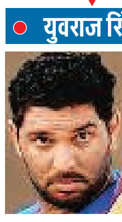

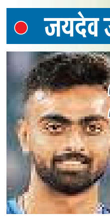

खिलाड़ी	सत्र	देश	रकम
महेंद्र सिंह धौनी	2008	भारत	06 करोड़
केविन पीटरसन	2009	इंग्लैंड	7.35 करोड़
शेन बांड	2010	न्यूजीलैंड	5.33 करोड़
गौतम गंभीर	2011	भारत	11 करोड़
रवींद्र जडेजा	2012	भारत	9.72 करोड़
ग्लेन मैक्सवेल	2013	ऑस्ट्रेलिया	5.3 करोड़
युवराज सिंह	2014 / 2015	भारत	14 करोड़ / 16 करोड़
शेन वॉटसन	2016	ऑस्ट्रेलिया	9.5 करोड़
बेन स्टोक्स	2017 / 2018	इंग्लैंड	14.5 करोड़ / 12.5 करोड़
जयदेव उनादकट	2019	भारत	8.4 करोड़

कोच ब्रेंडन मैकुलम ने की पैट कमिंस की तारीफ

कोलकाता, प्रेट्र: कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने पैट कमिंस को मौजूदा 'आइपीएल नीलामी में शामिल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' करार देते हुए गुरुवार को कहा कि उनकी फ्रेंचाइजी को इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज के लिए 15.50 करोड़ रुपये खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है।

मैकुलम ने कहा, 'मुझे लगता है कि वह इस नीलामी में शामिल सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एक क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने प्रगति की है। वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के उप कप्तान हैं, जो उनकी प्रगति की कहानी को बयां करता है। विश्वस्तरीय खिलाड़ी को टीम में शामिल करना शानदार है।' कमिंस आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज गेंदबाज हैं और उनके नाम 77 टी-20 मैचों में 90 विकेट हैं।

कार्तिक रहेंगे केकेआर के कप्तान : कमिंस के साथ केकेआर ने इंग्लैंड के विश्व विजेता कप्तान इयोन मोर्गन के लिए 5.25 करोड़ रुपये की सर्वाधिक बोली लगाई। मैकुलम से जब पूछा गया कि क्या 2020 सत्र में वह टीम की बागडोर संभालेंगे तो उन्होंने साफ किया कि दिनेश कार्तिक टीम के कप्तान बने रहेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर दिनेश कार्तिक हमारे कप्तान हैं। हम चाहते थे कि उनके आसपास अनुभवी और अच्छा नेतृत्वकर्ता हो। मोर्गन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक हैं।'

राहुल होंगे किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान: भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब ने आइपीएल के 2020 सत्र के लिए कप्तान नियुक्त किया है। किंग्स इलेवन के सह मालिक नेस वाडिया ने कहा, 'हम आगामी सत्र के लिए राहुल को कप्तान नियुक्त करके खुश हैं। उन्हें पिछले साल कुछ मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब उन्होंने शानदार वापसी की। उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है।' राहुल को किंग्स इलेवन ने 2018 के सत्र में 11 करोड़ रुपये में खरीदा था। अश्विन को रिलीज करने के बाद राहुल का पंजाब का कप्तान बनना तय था।

आइपीएल डायरी

चावला के धौनी से अच्छे संबंध : फ्लेमिंग

कोलकाता: सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि पीयूष चावला को काफी सोच-विचार कर टीम में शामिल किया गया है। चेपक के धीमे विकेट पर हमारी टीम स्पिनरों पर काफी निर्भर करती है। पीयूष उम्दा लेग स्पिनर हैं। आइपीएल में 150 विकेट लेने वाले चावला को चेन्नई ने 6.75 करोड़ रुपये की भारी कीमत में खरीदा है। उन्होंने कहा कि हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के चावला से अच्छे संबंध हैं। फ्लेमिंग ने सैम कुर्रन की खरीद को भी अच्छा चयन करार दिया। उन्होंने कहा कि कई अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन हमारे पास ज्यादा रुपये नहीं थे।

14 साल के नूर का नहीं हो पाया आइपीएल में पदार्पण

कोलकाता: अफगानिस्तान के 14 साल के चाइनामैन गेंदबाज नूर अहमद का आइपीएल में पदार्पण नहीं हो पाया। नीलामी के दौरान किसी भी फ्रेंचाइजी ने नूर पर बोली नहीं लगाई। कयास लगाए जा रहे थे कि इस प्रतिभाशाली स्पिन गेंदबाज पर सभी टीमों की नजर है और हमवतन राशिद खान की तरह नूर को भी सभी खरीदना चाहेंगी। महज 30 लाख रुपये का आधार मूल्य होने के कारण भी नूर को होड़ मचने का अंदाजा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी ओर भारतीय युवा तुर्क प्रियम गर्ग और यशस्वी जायसवाल पर अच्छे दांव लगे। नूर ने अब तक सात टी-20 मुकाबलों में आठ विकेट लिए हैं।

मैं फिर से आइपीएल के लिए तैयार : मैक्सवेल

नई दिल्ली, जासं: मैक्सवेल ने ट्विटर पर अपने वीडियो संदेश में कहा, 'किंग्स इलेवन के साथ कई शानदार यादें जुड़ी हैं और मैं अगले साल कुछ और यादों को जोड़ने का इंतजार कर रहा हूं। वहां मैं कई लोगों को जानता हूं, यह शानदार फ्रेंचाइजी है। मोहाली जाकर दर्शकों का मनोरंजन करने का इंतजार कर रहा हूं।'' मैक्सवेल जब पिछली बार टीम से जुड़े थे तो उन्हें प्यार से 'ग्लेनप्रीत सिंह' कहा जाता था। किंग्स इलेवन पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश मेनन ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे मध्यक्रम मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हम उन्हें टीम में शामिल करना चाहते थे। हमारे लिए मध्यक्रम में थोड़ी चिंताएं थी और यह परेशानी पहले भी रही है। वह टीम के बारे में अच्छे से जानते हैं। नीलामी में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दबदबे के बीच हमवतन क्रिस लिन ठंडे रहे। उन्हें वह कीमत नहीं मिल पाई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मुंबई को वह आसानी से आधार मूल्य पर मिल गए।

चोटिल चाहर बाहर, नवदीप टीम में

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे नहीं खेल पाएंगे दीपक, पीठ के निचले हिस्से में है दर्द की शिकायत

कटक, प्रेट्र: भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर गुरुवार को पीठ की चोट की वजह से भारत और वेस्टइंडीज के बीच मौजूदा वनडे सीरीज से बाहर हो गए। अब वह दोनों देशों के बीच सीरीज के तीसरे व निर्णायक मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और अंतिम वनडे मैच रविवार को यहां खेला जाएगा।

बीसीसीआइ के मुताबिक, 'दीपक को बुधवार को विशाखापत्तनम में हुए दूसरे वनडे मैच के बाद पीठ के निचले हिस्से में हल्का दर्द महसूस हुआ था। बीसीसीआइ की मेडिकल टीम ने उनका परीक्षण किया और इस तेज गेंदबाज को सलाह दी है कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ समय आराम की जरूरत है। इसलिए वह अंतिम वनडे मैच से बाहर रहेंगे।' चाहर हाल ही में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे। मूल रूप से आगरा के रहने वाले चाहर ने हैदराबाद के खिलाफ 10 रन पर आठ विकेट लेकर अपने रणजी करियर का शानदार पदार्पण किया था, लेकिन वह आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ सिर्फ दो सत्र बिताने के बाद भारत के लिए खेलने के दावेदारों में शामिल हुए। सैनी ने इस साल की शुरुआत में फ्लोरिडा और त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी-20 मैचों की सीरीज के दौरान भारत के लिए अपने करियर का शानदार आगाज किया था। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 17 रन पर तीन विकेट झटके थे, जिसमें उन्होंने अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया।

कोहली इतने नाटकीय क्यों हैं, उन्हीं से पूछें : पोलार्ड

विशाखापत्तनम: वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज में भारतीय कप्तान विराट कोहली काफी नाटकीय (एनिमेटेड) नजर आ रहे हैं और विरोधी कप्तान कीरोन पोलार्ड को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। टी-20 सीरीज के दौरान कोहली ने कैरेबियाई गेंदबाज केसरिक विलियम्स के हस्ताक्षर करने के अंदाज को दोहराया था। इसके बाद चेन्नई में पहले वनडे में मैदानी अंपायर शॉन जॉर्ज ने रवींद्र जडेजा के रन आउट का फैसला तीसरे अंपायर को सौंपा तो भी वह भड़क गए थे। पोलार्ड ने दूसरे वनडे में मिली हार के बाद कोहली के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'आपको उनसे ही पूछना होगा कि वह इतने नाटकीय क्यों थे। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा। जहां तक दूसरे वनडे की बात हैं तो हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन लगातार विकेट गिरने से दबाव में आ गए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हमसे यह गलती हो रही है।

रणजी में दिल्ली के बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली, आइएएनएस : आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया। पहली पारी में 215 रनों का स्कोर बनाने वाली दिल्ली रणजी ट्रॉफी मुकाबले के तीसरे दिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने अपनी दूसरी पारी में 28 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर मात्र 89 रन ही बनाए थे। इससे पहले आंध्र की पहली पारी 368 रनों के विशाल स्कोर पर खत्म हुई थी। आंध्र ने रिकी भुई के 144 रनों की शानदार पारी और चिपुरापल्ली स्टीफन (4/47) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत दिल्ली को काफी हद तक शिकंजे में कस लिया है।

तीसरे दिन आंध्र के गेंदबाजों के आगे दिल्ली के बल्लेबाज बेबस नजर आए। आंध्र के बायें हाथ के तेज गेंदबाज स्टीफन ने दिल्ली के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। स्टीफन ने दिल्ली के कुणाल चंदेला को 19, हितेन दयाल को 13, जोंटी सिद्धू को नौ और कुंवर बिधुड़ी को मात्र दो रनों पर आउट किया। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दिल्ली की ओर से ललित यादव 23 रन और विकास मिश्रा सात रन बना कर क्रीज पर जमे हुए थे। आंध्र अभी भी 64 रनों की बढ़त बनाए हुए है।

उत्तराखंड के सामने मैच बचाने की चुनौती : नईदुनिया, रायपुर : अमनदीप खरे (192 रन, 359 गेंद) भले ही दोहरा शतक जड़ने से चूक गए, लेकिन अजय मंडल (241* रन, 301 गेंद) ने दोहरा शतक जड़ा।

फुटबॉल बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड के बीच खेला गया विवादस्पद मुकाबला, रीयल मैड्रिड का आरोप, उन्हें नहीं दी गई दो पेनाल्टी, मेसी ने किया निराश

विरोध के बीच 17 साल बाद एल क्लासिको में नहीं हुआ गोल

बार्सिलोना, रायटर: विरोध प्रदर्शन के बीच बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड के बीच यहां कैंप नाउ में खेला गया एल क्लासिको मुकाबला गोलरहित (0-0) ड्रॉ पर खत्म हुआ। 17 साल बाद ऐसा हुआ जब एल क्लासिको में कोई गोल नहीं हुआ। यह मुकाबला विवादों से घिरा रहा। रीयल का आरोप है कि उन्हें दो बार पेनाल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन रेफरी ने ऐसा नहीं किया। स्टेडियम से बाहर स्पेन से कैटलोनिया की आजादी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और अंदर मैच चल रहा था। इस ड्रॉ के बाद बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड की टीम के अंक तालिका में एकसमान 36-36 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के आधार पर मेजबान टीम शीर्ष पर और मैनेजर जिनेदिन जिदान की टीम दूसरे स्थान है। बार्सिलोना ने 17 मैचों में 11 जीते हैं जबकि तीन मुकाबले ड्रॉ खेले हैं व तीन में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मैड्रिड ने भी इतने मैच खेले जिसमें उसे 10 में जीत मिली जबकि छह में ड्रॉ और एक में हार झेलनी पड़ी।

मौके का फायदा नहीं उठाया: मैच में दोनों टीमों को गोल करने के मौके मिले, लेकिन दोनों ही इसे गोल में नहीं बदल पाए। मेहमान टीम के स्टार स्ट्राइकर गेरेथ बेल ने गोल किया, लेकिन उसे ऑफ साइड करार दे दिया गया। जिदान की टीम शुरू से ही आक्रामक अंदाज में खेल रहे थी और उनके खिलाड़ियों ने 12 बार मेजबान टीम के गोल पोस्ट पर लक्ष्य साधा। बार्सिलोना के मैनेजर इर्नेस्टो वाल्वेर्डे के पास उसके दिग्गज स्ट्राइकर लियोन मेसी ही प्रेरणा के रूप में थे, लेकिन उन्होंने निराश किया और एक भी गोल नहीं कर पाए। जिदान व रामोस की रणनीति के आगे वह गोल नहीं कर पाए। 31वें मिनट में रामोस ने उन्हें ब्लॉक करके गोल करने से रोक दिया। मैड्रिड के लुका मॉड्रिक मेसी को रोकने के लिए उनकी टी-शर्ट पकड़ने लगे।

पेनाल्टी पर नाराजगी: पेनाल्टी नहीं मिलने से मैड्रिड के खिलाड़ी निराश दिखे। रीयल मैड्रिड के राफेल वराने पर बार्सिलोना के लेंगलेट ने 17वें मिनट में उनके दायें पैर पर अपने बायें पैर से हिट किया। इसके दो मिनट बाद ही रीयल मैड्रिड को कॉर्नर मिला और कॉर्नर से गेंद पेनाल्टी एरिया के पास गई और वहां भी मेजबान टीम के इवान रेकेटिक ने वराने की टी-शर्ट को खींचकर उन्हें गिरा दिया। इस पर ना तो रेफरी एलेजेंडरो जोस हर्नांडिज ने प्रतिक्रिया दिखाई और ना ही वार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दूसरे हाफ में मेसी के पास गोल करने का मौका आया। जोर्डी अल्बा के पास पर मेसी गेंद पर नियंत्रण नहीं कर पाए और टीम ने गोल करने का मौका गंवा दिया।

43 एल क्लासिको मैच सर्जियो रामोस ने खेले हैं। वह रीयल मैड्रिड की तरफ से सबसे ज्यादा एल क्लासिको मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बन गए

गेंद पर अपनी पकड़ी बनाने की कोशिश करते बार्सिलोना के लियोन मेसी (बायें) और रीयल मैड्रिड के लुका मॉड्रिक • एएफपी

प्रदर्शन का मैच पर असर नहीं

बार्सिलोना: एल क्लासिको मैच के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वे लोग कैटोलिना की आजादी की मांग रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। स्टेडियम के अंदर भी कुछ लोगों ने आजादी की मांग को लेकर हाथों में झंडे ले रखे थे। हालांकि इन चीजों का मैच पर कोई असर नहीं पड़ा और मैच तय समय पर शुरू और खत्म हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मैच को देर से शुरू करने या मैच में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। दोनों टीमें सुरक्षित स्टेडियम पहुंचीं और भारी सुरक्षा के साथ मैच के बाद वापस लौट गईं। कुछ लोगों ने मैच के दौरान पिच पर खाली हिस्सों में पीले रंग की 'बीच बॉल' फेंकी थीं। इससे पहले यह मुकाबला अक्टूबर में होना था, लेकिन प्रदर्शन के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था।

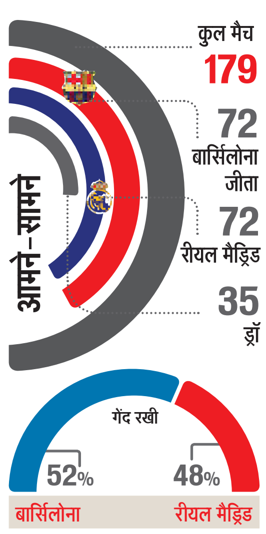

बार्सिलोना		रीयल मैड्रिड
19	फ्री किक	06
03	यलो कार्ड	05
02	कॉर्नर किक	06
01	ऑफ साइड	02
04	गोलकीपर बचाव	02
587	कुल पास	516

हमारी टीम बार्सिलोना के खिलाफ मजबूत थी। हमने गोल करने के कई मौके बनाए थे। हमने पहले हाफ में पेनाल्टी को लेकर अपील की और साफ दिख रहा था कि हमें पेनाल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं दी गई। वार तकनीक इसमें मदद कर सकती थी लेकिन इसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया।
सर्जियो रामोस, कप्तान, रीयल मैड्रिड

यह मैच हर चीज, दोनों टीमों और फुटबॉल के लिए अच्छा रहा है। हम सभी इस नतीजे से खुश हो सकते हैं। हमारी टीम ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया।
जिनेदिन जिदान, मैनेजर, रीयल मैड्रिड

मेरी टीम इस प्रदर्शन से प्रभावित नहीं हुई। हमने रीयल मैड्रिड के खिलाफ अच्छा मैच खेला। मैंने प्रदर्शनकारियों को कई 'बीच बॉल' मैदान की पिच पर फेंकते हुए देखा। लोगों ने विरोध किया, लेकिन ज्यादा नहीं।
ईर्नेस्टो वाल्वेर्डे, मैनेजर, बार्सिलोना

केएससीए सचिव के घर पर छापेमारी

नई दिल्ली, जेएनएन: कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल) के मैच फिक्सिंग मामले से संबंध होने की वजह से बेंगलुरु शहर की अपराध शाखा (सिटी क्राइम ब्रांच या सीसीबी) ने गुरुवार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के सचिव संतोष मेनन के घर पर छापेमारी की है। यह जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी। इससे पहले सीसीबी ने कोर्ट से इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सर्च वारंट ले लिया था।

इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु पुलिस की सीसीबी टीम ने मैच फिक्सिंग मामले में संबंध के चलते कर्नाटक की रणजी टीम के पूर्व खिलाड़ी एवं बेल्गावी पैंथर्स टीम के पूर्व कोच सुधींद्र शिंदे के घर की तलाशी ली थी। शिंदे कर्नाटक की अंडर-19 टीम के कोच और रायचूर क्षेत्र से केएससीए की प्रबंध समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शिंदे ने टीम के मालिक अली असफाक थारा के साथ मिलकर केपीएल में कुछ मैच फिक्स किए थे। शिंदे पहले बीजापुर बुल्स से भी जुड़े थे। पुलिस ने इससे पहले बेल्गावी पैंथर्स टीम के मालिक अली असफाक थारा को भी गिरफ्तार किया था। उसने दुबई के सट्टेबाज के साथ कथित तौर पर दांव लगाए थे और खिलाड़ियों के साथ संपर्क में थे। शिंदे और थारा के अलावा सीसीबी ने अब तक भावेश बाफना (पैंथर्स ड्रमर), बेंगलुरु ब्लास्टर्स के खिलाड़ी निशांत सिंह शेखावत, एम विश्वनाथ, गेंदबाजी कोच वीनू प्रसाद, पूर्व रणजी खिलाड़ी व बेल्लारी टस्कर्स के कप्तान सीएम गौतम, स्पिनर अबरार काजी और सट्टेबाज संयम गुलाटी को भी गिरफ्तार किया था।

यूएस ओपन के सेमीफाइनल में मुदित, किया पदक पक्का

नई दिल्ली : भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी ने टेक्सास के फोर्ट वर्थ कन्वेंशन सेंटर में जारी यूएस ओपन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ मुदित ने अपने लिए पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन (आइटीटीएफ) सीनियर पदक सुरक्षित कर लिया है। कनाडा के मार्को के साथ खेल रहे मुदित ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के तियान ये और शी झीगाओ को 4-1 से हराया।

मैं अपनी फिल्म साइना को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे पूरी उम्मीद है परिणीति ने इसमें अच्छा काम किया होगा।
– साइना नेहवाल, भारतीय शटलर

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल से जीता जुवेंटस

फुटबॉल डायरी ▶ सीरी-ए में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने जुवेंटस के गोलकीपर बुफोन

सैंपडोरियो को दी जुवेंटस ने 2-1 से शिकस्त

मिलान, एपी : क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार हेडर से किए गोल की मदद से जुवेंटस ने इटली की फुटबॉल लीग सीरी-ए में सैंपडोरिया को 2-1 से शिकस्त दी। गत विजेता जुवेंटस ने इस जीत के साथ तालिका में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। जुवेंटस के गोलकीपर 41 वर्षीय जियानलुइगी बुफोन ने पाओलो माल्दिनी के सीरी-ए में सर्वाधिक 647 मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मैच के तीनों गोल पहले हाफ में हुए। पाउलो डायबाला ने 19वें मिनट में गोल करके जुवेंटस का मैच में खाता खोला। लेकिन इसके 16 मिनट बाद ही गियानलुका कैपरारी ने गोल कर सैंपडोरिया की मैच में वापसी करा दी। इस दौरान 45वें मिनट में रोनाल्डो का गोल विजयी साबित हुआ। एलेक्स सैंड्रो ने गेंद को विपक्षी टीम के गोल पोस्ट की ओर भेजा और वहां रोनाल्डो ने उछलकर अपने हेडर से गेंद को उसकी सही दिशा दिखाकर टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी। मैच के बाद रोनाल्डो ने कहा कि यह गोल अच्छा था, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरी मदद से टीम तीन अंक हासिल करने में सफल रही। महत्वपूर्ण चीज है कि जुवेंटस ने जीत हासिल की। मैं चाहता हूं कि टीम यह ट्रॉफी फिर से हासिल करें। 34 वर्षीय रोनाल्डो पिछले महीने गोल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वह पिछले पांच मैचों में छह गोल कर चुके हैं।

स स स

बेल्जियम चुनी गई साल की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम

ज्यूरिख, एएफपी : फुटबॉल की विश्व संस्था फीफा ने बेल्जियम को लगातार दूसरी बार साल की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है। बेल्जियम इस समय फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर मौजूद है। विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राजील तीसरे नंबर पर हैं। शीर्ष तीन स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन शीर्ष पांच में बदलाव देखने को मिला है। इंग्लैंड एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है जबकि उरुग्वे दो पायदान ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर आ गया। बेल्जियम 2015 और 2018 साल की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीत चुकी है। बेल्जियम के अलावा एशियाई चैंपियन कतर को मूवर ऑफ द ईयर-2019 के पुरस्कार के लिए चुना गया। कतर ने दिसंबर 2018 की फीफा रैंकिंग के बाद से 25 मैचों में 138 अंक हासिल किए हैं। कतर ने इन 25 मैचों में 16 जीते हैं जबकि दो ड्रॉ और सात मैच हारे हैं। टीम इस साल की शुरुआत में एशियन कप के फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर एशियाई चैंपियन बनी थी। कतर ने अपनी रैंकिंग में 38 स्थानों का सुधार किया है और वह इस समय 55वें पायदान पर है।

भारत को फिर नुकसान : फीफा की जारी साल की आखिरी रैंकिंग में 108वें नंबर पर बनी हुई है। भारतीय टीम हालांकि पूरे वर्ष में 11 पायदान नीचे खिसकी। भारत के 1187 अंक हैं और वह एशियाई देशों में 19वें स्थान पर हैं।

मोंटेरी को हराकर क्लब विश्व कप फाइनल में पहुंचा लिवरपूल

दोहा, आइएएनएस : रोबटरे फीर्मिनो के इंजुरी टाइम में किए गए गोल की मदद से लिवरवूल ने मोंटेरी को 2-1 से हराकर क्लब विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में शनिवार को खलीफा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में लिवरपूल का सामना कोवा लिबर्टाडोरेकी विजेता फ्लेमेंगो से होगा। लिवरपूल ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में 11वें मिनट में नेबी कीता के गोल के दम पर 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि फ्लेमोंगो ने 14वें मिनट में ही रोजेलियो फ्यूनेस मोरी के गोल के सहारे 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। दूसरे हाफ तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थी।

शतक के जश्न के अंदाज पर ट्विटर पर छाए केएल राहुल

विशाखापत्तनम : केएल राहुल के वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अपने करियर का तीसरा वनडे शतक जड़ने के बाद का जश्न का अंदाज ट्विटर पर छा गया है। राहुल ने शतक जड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपनी अंगुलियों को कानों के ऊपर रख लिया था।

उनके एक प्रशंसक ने उनकी उस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'गलती हो गई भगवान। फिर कभी कॉफी विद करन में नहीं जाऊंगा।' एक अन्य प्रशंसक ने दो फोटो पोस्ट कीं। एक में राहुल कानों पर अंगुलियां रखे नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे में वह सेल्यूट करते दिख रहे हैं। उनके इस प्रशंसक ने साथ ही लिखा, 'जब मां डांटती हैं, जब पिता डांटते हैं।' एक अन्य यूजर ने राहुल की यह फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, 'जब रिश्तेदार ज्ञान देना शुरू करते हैं।'

एक प्रशंसक ने लिखा, 'मुझे माफ कर दो भगवान, अब के बाद से सिर्फ चाय पीऊंगा।' एक यूजर ने प्रतिक्रिया दी, 'राहुल, जब उन्हें करन जौहर ने कॉफी विद करन के एपिसोड के लिए आमंत्रित किया।' एक अन्य ने लिखा, 'परीक्षा के दौरान टॉपर्स।' ऐसे ही कुछ मजेदार कमेंट लोगों ने इस तस्वीर पर किए।

शतक के बाद जश्न मनाते राहुल। फाइल फोटो

रिकॉर्ड 62 करोड़ 59 लाख रुपये में बिका 127 साल पुराना ओलंपिक का घोषणापत्र

टोक्यो ओलंपिक डायरी

न्यूयॉर्क, रायटर : ओलंपिक का मूल घोषणापत्र नीलामी में बिकने वाला खेल का सबसे महंगा घोषणापत्र रहा। बुधवार को यहां हुई नीलामी में इसे 8.8 मिलियन डॉलर (62 करोड़ 59 लाख रुपये) में खरीदा गया। इसके सात करोड़ रुपये में बिकने की उम्मीद थी, लेकिन 12 मिनट तक चली बोली में यह रकम बढ़ती चली गई। इसको लेकर तीन अंतरराष्ट्रीय खरीदारो में होड़ दिखी।

यह 127 साल पुराना आधुनिक ओलंपिक खेलों का घोषणापत्र है। नीलामीकर्ता सोथबे के अनुसार, ओलंपिक के मूल घोषणापत्र के लिए बोली की गई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पिएरे डि काउबेर्टिन द्वारा 1892 में हस्ताक्षरित इस दस्तावेज में पुरातन यूनानी खेलों को नया रूप देने और एथलीटों के लिए मानक तय किए गए थे। सोथबे के प्रमुख रिचर्ड ऑस्टिन ने कहा कि ओलंपिक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देश एक-दूसरे के खिलाफ स्पर्धा करते हैं, लेकिन यह युद्ध नहीं होता। मूल घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने के चार साल बाद एथेंस (यूनान) में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पदार्पण हुआ था। इससे पहले बेब रूथ द्वारा पहनी न्यूयॉर्क की यानकीज जर्सी खेल का सबसे महंगा बिकने वाला सामान था। जिसे जून में 5.64 मिलियन डॉलर (39 करोड़ रुपये) में खरीदा गया था।

भूकंप को लेकर भी तैयार है टोक्यो

टोक्यो, एपी : टोक्यो ओलंपिक आयोजनकर्ता और सरकार हर चीज के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसमें भूकंप को लेकर भी सतर्कता है। ओलंपिक गेम्स अगले वर्ष टोक्यो में आयोजित होने हैं। एरिके वेन्यू पर जिम्नास्टिक की स्पर्धा होंगी। गुरुवार को इस जगह पर आपदा से बचने के लिए ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें 100 फायर फाइटर्स, पुलिस और जापान सेल्फ डिफेंस के लोगों ने भाग लिया। जापान में कई बार भूकंप आए हैं और वह इसके लिए बेहद सतर्क है।

खिलाड़ियों को रूसी झंडे के नीचे खेलने दिया जाए : पुतिन

मास्को : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस के एथलीटों को देश के झंडे के अंतर्गत खेलने देना चाहिए। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानि वाडा ने रूस पर चार वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद रूस किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। पुतिन ने कहा कि अगर वाडा को हमारी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, हमारी टीम से कोई समस्या नहीं हुई तो हमारे एथलीट अपने झंडे के नीचे जरूर खेलेंगे। किसी भी तरह की सजा व्यक्तिगत होनी चाहिए।

श्रीलंका ने पाकिस्तान को 191 रन पर समेटा

कराची, एएफपी : श्रीलंका ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर नेशनल स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को मेजबान पाकिस्तान को उसकी पहली पारी में 191 रन पर समेट दिया। श्रीलंका ने इसके जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक तीन विकेट पर 64 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम अभी पाकिस्तान के स्कोर से 127 रन पीछे है।

पहले दिन का खेल खत्म होने तक एंजेलो मैथ्यूज आठ और लसिथ एंबुलडेनिया तीन रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके अलावा ओशादा फर्नाडो ने चार, कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 25 और कुशल मेंडिस ने 13 रनों का योगदान दिया। पाकिस्तान की ओर से मुहम्मद अब्बास ने दो और शाहीन अफरीदी ने एक विकेट हासिल किया। इससे पहले, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती चली गई। इसके कारण वह 191 रन तक ही पहुंच पाई। मेजबान टीम के लिए असद शफीक ने 63, बाबर आजम ने 60 और आबिद अली ने 38 रनों की पारी खेली।

पाकिस्तानी बल्लेबाज हैरिस सोहेल के खिलाफ अपील करते श्रीलंका के विकेटकीपर निरोशन डिकवेला। एएफपी

विविध

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ एक साल से कर रहे थे ठगी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- क्रेडिट कार्ड का ऑफर देकर ओटीपी लेकर करते थे ठगी, गाजियाबाद से संचालित कर रहे थे गिरोह
- सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपितों को किया गिरफ्तार, आरोपितों के कब्जे से 50 सिम कार्ड बरामद

सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपित लोगों को फोन पर क्रेडिट कार्ड का ऑफर देने के बहाने ठगी करते थे। आरोपित ऑफर के बहाने से लोगों से ओटीपी लेकर उनका क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैक कर रुपये ओला मनी व पेटीएम मेंट्रांसफर कर लेते थे। ठगी का धंधा गाजियाबाद के सेवा नगर मोहल्ले से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 17 मोबाइल, 50 सिम कार्ड, एक लैपटॉप व 11 हजार रुपये बरामद किए है। पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश किया। वहां से पांचों को जेल भेज दिया गया है।

एसपी देहात रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़ित अभिषेक गौर ने सूरजपुर कोतवाली में ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी दौरान ठगों ने पीड़ित को फिर से फोन कर ओटीपी नहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह दीखित की टीम ने ठग गिरोह के मास्टरमाइंड अजय निवासी कविनगर गाजियाबाद को गुरुवार सुबह सूरजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अजय की निशानदेही पर गाजियाबाद सिहानी गेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला सेवा नगर स्थित एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से रोहित यादव, अभय सिंह, इरशाद और किशोर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित गाजियाबाद से फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। मौके से पुलिस ने 50 सिम कार्ड सहित कई अन्य सामान बरामद किया।

अजय है गिरोह का मास्टरमाइंड

पुलिस ने बताया कि अजय गिरोह का मास्टरमाइंड है और वह 12वीं तक पढ़ा है। सभी आरोपित बीते एक साल से लोगों को फोन कर ऑफर देने के बहाने ठगी का धंधा संचालित कर रहे थे।

लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर हत्या की धमकी देने का आरोप

संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)

लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का नाम एक और नए विवाद से जुड़ गया है। गुरुवार को नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा ने पूर्व चेयरमैन और अपने पति मनोज धामा की हत्या की साजिश रचने का आरोप विधायक नंदकिशोर पर लगाया है। रंजीता ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चेयरमैन ने विधायक के दो कथित ऑडियो भी वायरल किए, जिनमें वह गाली-गलौज करते हुए गोली मारने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर आरोपों को सिरे से नकारते हुए ऑडियो से छेड़छाड़ की बात कह रहे हैं।

रंजीता ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के बाद गुर्जर ने उनके पति को फर्जी मामलों में फंसाकर परेशान किया है। साथ ही पालिका के विकास कार्यों में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। रंजीता ने कहा कि कुछ समय पूर्व एक लोकार्पण कार्यक्रम में भी विधायक ने उनके साथ अपने समर्थकों से अभद्रता कराई। साथ ही उनके खिलाफ तीन फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। रंजीता धामा ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी व अपने पति की सुरक्षा की मांग के साथ विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की है।

उधर, गुर्जर का कहना है कि वह मनोज धामा का सम्मान करते हैं। वायरल ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है। ऑडियो में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन को पत्र लिखा था, जिसमें करोड़ों का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में पूर्व चेयरमैन को जेल जाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की शिकायत उन्हें नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।

अब दो जनवरी को होगी गुर्जर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई

जासं, गाजियाबाद : लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर दर्ज हुए मारपीट के मामले में उनकी ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन कचहरी में वकीलों की हड़ताल के कारण अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अब अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए दो जनवरी की तारीख नियत की है।

बता दें कि लोनी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष सिंह ने विधायक पर अपने दफ्तर में बुलाकर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया था। इस मामले में विधायक के समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन विधायक की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है।

ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक के अधिवक्ता परविंदर नागर ने एडीजे-1 में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई होनी थी।

यमुना एक्सप्रेस वे पर 63 किलो अफीम पकड़ी, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- तस्करों के कब्जे से 25 लाख रुपये नकद बरामद, हरियाणा व पंजाब के फार्म हाउस और होटल में सप्लाई होनी थी अफीम
- कार की स्टपनी में छिपाकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी अफीम
- झारखंड से ऑन आर्डर मंगाई जाती है नशे की सामग्री

झारखंड से उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए हरियाणा व पंजाब के फार्म हाउस और होटलों में सप्लाई होने के लिए जा रही 63 किलोग्राम अफीम बीटा दो कोतवाली पुलिस ने पकड़ी है। मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य भाग निकले। तस्करों के कब्जे से 25 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। खास बात है कि कार की स्टेपनी में छिपाकर अफीम लाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों तस्करों को कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि बीटा दो कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय को झारखंड से अफीम यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते लाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कोतवाली प्रभारी टीम सहित एक्सप्रेस वे के आस-पास सक्रिय हो गए। देर रात जीरो प्वाइंट के समीप से डस्टर कार सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से 63 किलोग्राम अफीम, एक डस्टर कार व 25 लाख रुपये नकद बरामद किया गया है। आरोपितों की पहचान अरुण निवासी झारखंड व सतीश निवासी कुरुक्षेत्र हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला है कि झारखंड में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। वहीं से सड़क मार्ग से तस्करी कर अफीम को हरियाणा व पंजाब लाया जाता है।

पांच साल से कर रहे थे तस्करी : कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित अरुण तस्कर है जबकि सतीश कारोबारी है। अरुण पिछले पांच साल से अफीम तस्करी का अवैध धंधा कर रहा है। सतीश के हरियाणा में फार्म हाउस है। उन्हीं में अफीम विदेशी मेहमानों को सप्लाई की जाती है। इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी।

पचास हजार का मिला इनाम : आइजी मेरठ रेंज आलोक सिंह ने बीटा दो कोतवाली की टीम को पचास हजार का इनाम दिया है। पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते होने वाली तस्करी के रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर नशे के कारोबार पर बड़ी चोट की है।

कॉलेजों में भी सप्लाई होने की आशंका

पुलिस का दावा है कि अफीम की सप्लाई दिल्ली-एनसीआर के कॉलेजों में भी की जाती है। पुड़िया बनाकर तस्कर छात्रों तक नशे का सामान पहुंचाते हैं। पुलिस नेटवर्क के हर हिस्से की जांच कर रही है।

नेताजी के अनुयायी थे गुमनामी बाबा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश
- नेताजी के रूप में प्रचारित होने पर बदल लिया था मकान
- उत्तर प्रदेश की पिछले सरकार ने गठित किया था आयोग

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में प्रचारित और चर्चित गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी की शिनाख्त करने में जस्टिस विष्णु सहाय आयोग नाकाम रहा है। अलबत्ता उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने दोनों के बीच कई समानताएं पाई हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे। हालांकि जिस समय यह बात प्रसारित होने लगी थी कि वह सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने तत्काल अपना मकान बदल लिया था।

फैजाबाद के राम भवन में रहने वाले गुमनामी बाबा की असलियत का पता लगाने के लिए गठित किए गए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दोनों सदनों में पेश की गई। रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि गुमनामी बाबा बंगाली थे और बंगला, अंग्रेजी व हिंदी भाषाओं के जानकार थे। वह एक असाधारण मेधावी व्यक्ति थे। राम भवन के जिस भाग में वह निवास करते थे, उसमें बड़ी संख्या में मिलीं बंगला, अंग्रेजी और हिंदी की किताबें इसकी गवाही देती हैं। उन्हें युद्ध, राजनीतिक और सामयिक विषयों की गहन जानकारी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वर के समान उनकी आवाज में भी प्राधिकार का भाव था। उनमें प्रचंड आत्मबल और आत्मसंयम था, जिसने उन्हें जीवन के अंतिम 10 वर्षों में अयोध्या और फैजाबाद में पर्दे के पीछे रहने के योग्य बनाया था। जो लोग पर्दे के पीछे से उनसे बात करते थे, वे उनसे सम्मोहित हो जाते थे। वह पूजा और ध्यान में पर्याप्त समय व्यतीत करते थे। संगीत, सिगार और भोजन के प्रेमी भी थे। भारत में शासन की स्थिति से उनका मोहभंग था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो अपनी पहचान जाहिर होने के बजाय मृत्यु को पसंद करते हैं।

गौरतलब है कि गुमनामी बाबा का देहावसान 16 सितंबर 1985 को हुआ था। उनकी पहचान का पता लगाने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर अखिलेश सरकार ने 28 जून 2016 को जस्टिस विष्णु सहाय आयोग गठित किया था। आयोग ने 19 सितंबर 2017 को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। कैबिनेट ने बीती जुलाई में आयोग की रिपोर्ट को विधानमंडल में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

देश की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती के आरोपित रूसी पारदी की मौत

नईदुनिया, गुना

- तीन साल पहले गैंग ने लूटे थे पौने छह करोड़ रुपये
- दो साल से मध्य प्रदेश की गुना जेल में बंद था

देश की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती के आरोपित रूसी पारदी की गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह दो साल से मध्य प्रदेश की गुना जेल में बंद था। गुना जेल से मिली जानकारी के अनुसार रूसी पारदी पुत्र पेमड़ा पारदी (35) 12 दिसंबर 2017 से गुना जेल में बंद था। गुरुवार तड़के करीब तीन बजकर 35 मिनट पर उसे दिल का दौरा पड़ा। डॉ. अनिल राजपूत ने प्राथमिक उपचार कर 3.45 बजे उसे एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

2016 में विशेष बोगी की छत में छेद कर लूटे थे करोड़ों : रूसी पारदी के खिलाफ पुलिस पर हमले सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेन डकैती से वह ज्यादा चर्चा में आया था। रूसी की गैंग ने आठ अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सलेम स्टेशन से चेन्नई के एगमोर स्टेशन जा रही कड़ी सुरक्षा वाली ट्रेन की विशेष बोगी की छत में छेद कर 5.78 करोड़ रुपये लूटे थे। इस वारदात के तीन माह बाद आठ नवंबर को नोटबंदी हुई, तो दो करोड़ रुपये के नोट जला दिए थे। शेष राशि का गैंग के सदस्यों ने बंटवारा कर संपत्ति खरीद ली थी।

तमिलनाडु की सीबी-सीआइडी की टीम ने मप्र पुलिस की मदद से इस वारदात का पर्दाफाश किया था। उस समय सीबी-सीआइडी ने प्रेस वार्ता में इसे देश की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती करार दिया था। हालांकि, रूसी यह पर्दाफाश होने के पहले से ही अन्य अपराध में जेल में बंद था।

मौसम विशेष

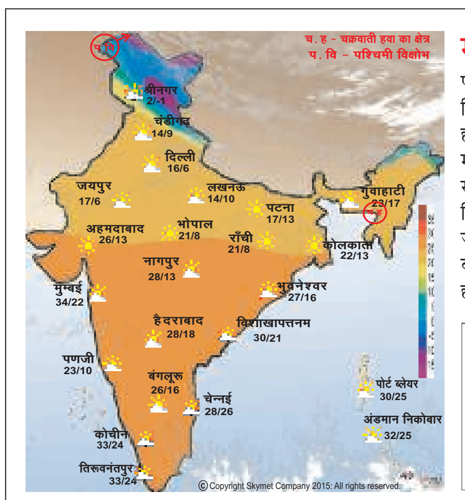

पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं के साथ ठंडी सुबह में मध्यम कोहरा व कुहासा छाया रहेगा। आंशिक बादलों के साथ धूप खिली रहेगी। दिन शीतल रहेगा। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बादल छाये रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व बर्फबारी संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/22/व	अहमदाबाद	30/16/व
कोलकाता	23/13/आंबा	बड़ौदा	31/14/आंबा
चेन्नई	31/24/व	नागपुर	28/13/व
हैदराबाद	28/18/आंबा	इन्दौर	29/14/आंबा
बंगलूरू	26/15/आंबा	राँची	28/16/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/25/आंबा	पटना	27/14/आंबा
गुवाहाटी	23/15/आंबा	जमशेदपुर	30/17/आंबा
गंगटोक	07/-4/आंबा	पुणे	31/21/आंबा

दुनिया में पहली बार बनी परमाणु बिजली

1951 में आज ही अमेरिका के इडाहो में बने एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पहली बार बिजली का उत्पादन हुआ। इस बिजली से 200 वाट के चार बल्ब जलाए गए। 1964 में इसे बंद करके संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया।

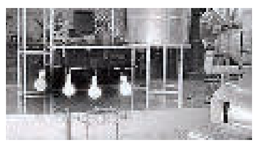

मिसौरी में लगाया गया अविवाहितों पर कर

1820 में आज ही अमेरिका के मिसौरी में अविवाहित पुरुषों पर कर नीति लागू की गई। इसके मुताबिक 21 से 50 साल की उम्र के अविवाहित लोगों को सालाना एक डॉलर टैक्स देना होता था। टैक्स की राशि को तीन डॉलर बढ़ाने के एक साल बाद ही 1922 में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को खत्म कर दिया।

वसुधैव कुटुंबकम को मजबूती देता है अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस

दुनिया में शांति, स्थायित्व और सामाजिक व आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए देशों व लोगों के बीच एकता का होना जरूरी है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने मानव एकता को 21वीं सदी के मौलिक मूल्यों में शामिल किया और 2005 में आज के दिन को अंतरराष्ट्रीय मानव दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जो लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं, उन्हें ऐसे लोगों का मददगार बनना चाहिए जो पीड़ित हैं और एक सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व एकता कोष की भी स्थापना की, जिससे गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास की दिशा में काम किया जा सके।

कमाई और लोकप्रियता में विराट ने सलमान खान को पछाड़ा

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कमाई और लोकप्रियता के मामले में बॉलीवुड सितारे सलमान खान को पछाड़ दिया है। फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से भारत की 100 हस्तियों की सूची में इस बार विराट कोहली पहले नंबर पर हैं। सूची में पिछले तीन साल से सलमान खान का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। विराट इस सूची को टॉप करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सूची को पेशे व विज्ञापनों से हुई कमाई और उनकी लोकप्रियता के आधार पर तैयार किया जाता है। 2019 की सूची पहली अक्टूबर, 2018 से 30 सितंबर, 2019 के बीच हुई कमाई व प्रसिद्धि के आकलन के आधार पर तैयार की गई है।

फोर्ब्स की सूची
- तीन साल से टॉप पर चल रहे सलमान तीसरे नंबर पर पहुंचे
- दूसरे नंबर पर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने बनाई जगह

विराट कोहली। प्रेट्र

अक्षय कुमार। ट्विटर

सलमान खान। फाइल

फोर्ब्स ने 252.72 करोड़ रुपये की कमाई के साथ विराट को सबसे ऊपर जगह दी है। दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार हैं, जिनकी कमाई 293.25 करोड़ रुपये रही। ज्यादा कमाई के बावजूद लोकप्रियता के मामले में विराट से कमतर रह जाने के कारण अक्षय दूसरे स्थान पर रहे। 229.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ सलमान खान इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अमिताभ बच्चन और एमएस धौनी क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। इनकी कमाई इस अवधि में क्रमशः 239.25 करोड़ रुपये और 135.93 करोड़ रुपये रही। छठे और सातवें स्थान पर क्रमशः शाह रुख खान (124.38 करोड़ रुपये) और रणवीर सिंह (118.2 करोड़ रुपये) का नाम है। टॉप 10 में दो महिलाएं हैं। इसमें 59.21 करोड़ रुपये की कमाई के साथ आलिया आठवें और 48 करोड़ रुपये के साथ दीपिका पादुकोण 10वें स्थान पर हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 76.96 करोड़ रुपये की कमाई के साथ नौवें स्थान पर हैं।

टॉलीवुड की बढ़ी कमाई : दक्षिण भारतीय सिने उद्योग यानी टॉलीवुड के सितारों की कमाई बढ़ रही है। सूची में 13 टॉलीवुड सितारों ने जगह बनाई है। 2018 की सूची के 15 टॉलीवुड सितारों के मुकाबले गिनती कम हुई है, लेकिन कुल कमाई बढ़ी है। पिछली बार 15 टॉलीवुड सितारों की कमाई सूची की सभी हस्तियों की कुल कमाई के 11.26 फीसद के बराबर रही थी। इस बार 13 टॉलीवुड सितारों की कमाई सूची में शुमार लोगों की कुल कमाई के 12.57 फीसद के बराबर है।

झलक रही लैंगिक विषमता : सूची से विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक विषमता की तस्वीर भी दिख रही है। 100 हस्तियों की इस सूची में कुल 30 महिलाएं हैं। फोर्ब्स इंडिया के एडिटर ब्रायन कार्वाल्हो ने कहा कि फिल्म जगत हो या कोई खेल, हर जगह महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है। क्रिकेट में टॉप पुरुष खिलाड़ी और टॉप महिला खिलाड़ी के साथ होने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट में 6.5 करोड़ रुपये का अंतर होता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इस बार सूची में महिलाओं की संख्या 2018 की तुलना में ज्यादा है। 2018 में मात्र 17 महिलाओं को सूची में जगह मिल पाई थी।

इधर-उधर की

सांता को लिखी भावुक चिट्ठी

लंदन, एजेंसी : क्रिसमस के मौके पर हर कोई सांताक्लाज से अपनी मुराद पूरी कर लेना चाहता है, लेकिन यहां की नौ साल की एक लड़की ने सांता को एक पत्र लिखा जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो रहा है। नौ साल की एमिलिया बर्गियो से उनके माता-पिता ने अपनी विश लिस्ट तैयार करने को कहा। उन लोगों को अनुमान था कि उनकी बेटी दर्जनों की संख्या में उपहार की मांग कर देगी। लेकिन बिटिया की सूची देखकर वे दंग रह गए। एमिलिया ने सांता को लिखी चिट्ठी में कहा कि उनके पास सबकुछ है। इसके लिए उसने सांता को धन्यवाद दिया। काफी देर मैंने सोचा कि क्रिसमस पर आपसे क्या मांगू, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छे मित्र और परिवार है। हालांकि एक-दो चीज है जिन्हें मैं लेना चाहूंगी। अगर आपको समय मिले तो मुझे रोलर स्केट्स और इवी सीरीज की किताबें बतौर उपहार दे दीजिएगा। एमिलिया के इस पत्र को उनके पिता ने फेसबुक पर डाल दिया जो वायरल हो चुका है। भावुक कर देने वाली प्रतिक्रियाओं की बाढ़ लगी है।

शोध अनुसंधान

काम के घंटे ज्यादा होने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा

ऑफिस में ज्यादा समय बिताना हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। चिंता की बात यह है कि ऐसे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी ऐसी समस्या का खतरा रहता है, जिसका पता सामान्य मेडिकल जांच में चलना मुश्किल होता है। हालिया शोध में यह बात सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हफ्ते में 35 घंटे काम करने वालों की तुलना में हर हफ्ते 49 घंटे या इससे ज्यादा काम करने वालों में मास्क्ड हाइपरटेंशन का खतरा 70 प्रतिशत और सस्टेंड हाइपरटेंशन का खतरा 66 प्रतिशत तक ज्यादा रहता है। मास्क्ड हाइपरटेंशन की स्थिति में सामान्य मेडिकल जांच से ब्लड प्रेशर में तेजी का पता नहीं चल पाता है। वहीं सस्टेंड हाइपरटेंशन में हमेशा रीडिंग लेने पर ब्लड प्रेशर ज्यादा दिखता है। यह खतरा महिलाओं और पुरुषों दोनों में समान रूप से देखा गया। हाई ब्लड प्रेशर के दोनों ही प्रकार दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। - आइएएनएस

बैठे रहने से नहीं ज्यादा खाने से मोटापे का खतरा

बच्चों के बढ़ते वजन से परेशान हैं तो उनके खानपान पर नजर रखना शुरू कर दीजिए। हमेशा यह सोचना सही नहीं कि बाहर खेलने-कूदने और सक्रिय रहने से उसका मोटापा नियंत्रित हो जाएगा। हालिया शोध में यह बात सामने आई है। वैज्ञानिकों ने कहा कि आमतौर पर माना जाता है कि आलस करने और ऊर्जा की खपत कम रहने से बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। यह पूरी तरह सही नहीं है। अगर बच्चा आलसी नहीं है और बाहर खेलता-कूदता है, तब भी उसका खानपान उसे मोटापे का शिकार बना सकता है। शोध में पाया गया कि सक्रिय रहने वाले और बैठे रहने वाले बच्चों की ऊर्जा खपत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। ऐसे में बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए उनके खानपान को सही रखना ज्यादा महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। - आइएएनएस

पहली बार घटे तंबाकू सेवन करने वाले

बड़ी जीत ▶ विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दिखी सुनहरी तस्वीर, छह करोड़ लोगों ने की तौबा

रंग ला रहे सरकारों के प्रयास सुरक्षित हो रहा लोगों का जीवन

लंदन, रायटर : धूमपान को लेकर दुनिया भर के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहली बार धूमपान करने वाले और तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले पुरुषों की संख्या में लगातार होती वृद्धि पर काबू पाया गया है। गुरुवार को जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में महामारी बनती इस समस्या के लिए तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या में कमी अहम पड़ाव है। दुनिया में धूमपान करने वालों की संख्या में यह बदलाव सरकारों के उन प्रयासों का नतीजा है जिसके तहत वे जीवन बचा रही हैं, स्वास्थ्य को सुरक्षित रख रही हैं और तंबाकू को पराजित कर रही हैं।

कम हुए सेवन करने वाले : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2000 की तुलना में दुनिया में तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2018 में छह करोड़ कम रही। 2000 में दुनिया भर में 1.397 अरब लोग तंबाकू का सेवन करते थे। 18 साल बाद यानी अब यह संख्या कम होकर 1.337 अरब हो गई है।

खतरनाक असर : फेफड़े का कैंसर, सांस संबंधी अन्य दिक्कतें, स्ट्रोक और हृदय संबंधी रोगों के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार। मुंह, गला और अन्य तरह के कैंसर का कारक।

तेज गिरावट का अनुमान : रिपोर्ट के अनुसार आगे भी धूमपान करने वाले पुरुषों की संख्या में तेज गिरावट का अनुमान है। 2020 तक इनकी (पुरुष और महिलाएं) संख्या में 2018 के मुकाबले एक करोड़ की कमी आ सकती है। 2025 तक इस संख्या में 2.7 करोड़ की और कमी दिख सकती है।

भारतीय महिलाओं में धुंआरहित तंबाकू खात्मे की ओर : रिपोर्ट के अनुसार कभी करीब हर भारतीय महिला धुंआरहित तंबाकू का सेवन करती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं तक ही सीमित होती जा रही है। युवा इससे दूरी बना रहे हैं। लगता है कि ये प्रथा खात्मे की ओर है।

रिपोर्ट में शामिल तंबाकू के प्रकार : विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट में सिगरेट, पाइप, सिगार, वाटरपाइप, धुंआरहित तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी और चुरट, गर्म करके इस्तेमाल किए जाने वाले तंबाकू उत्पादों को आधार बनाया गया।

80 लाख दुनिया में हर साल तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतें

70 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष इस्तेमाल से होने वाली मौतें

12 लाख उन लोगों की मौतें जो धूमपान नहीं करते, लेकिन किसी धूमपान करने वाले से प्रभावित होते हैं

4 दुनिया में तंबाकू का सेवन करने वाले हर पांच में से पुरुषों की संख्या

"कम संख्या में लोगों का तंबाकू सेवन करना वैश्विक रूप से जन स्वास्थ्य को लेकर बड़ी उपलब्धि सरीखा है" – **विनायक प्रसाद, तंबाकू नियंत्रण इकाई के प्रमुख, डब्ल्यूएचओ**

60% दुनिया के कुल देशों में उनकी हिस्सेदारी जहां 2010 के बाद तंबाकू के सेवन में दिखी कमी

महिलाओं ने बाजी मारी

धूमपान करने वाली महिलाओं की संख्या में कमी साल 2000 में ही दिख गई थी। इस साल इनकी संख्या में 34.60 करोड़ कमी दिखी जो 2018 में 24.4 करोड़ रही। इसी दौरान तंबाकू का सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या में चार करोड़ (1.05 अरब से बढ़कर 1.093 अरब) का इजाफा दिखा।

धीमा जहर है धूमपान, शरीर को कर देता है खोखला

धूमपान का सेवन कई गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। इससे होने वाले कई रोग लंबे समय बाद शरीर में अपना असर दिखाना शरू करते हैं और तब कई रोगियों के बचने की संभावना भी कम हो जाती है। धूमपान से होने वाली बीमारियां धीमा जहर होती हैं और शरीर को रोगी बना देती हैं।

फेफड़ों से संबंधित रोग : क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एंफीसेमा ऐसी बीमारियां हैं जो कभी ठीक नहीं होती। इनकी वजह से सांस लेना भी दूभर हो जाता है।

कोरोनरी हार्ट डिसीज : धूमपान करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही उच्च रक्तचाप की समस्या भी हो जाती है। जो लोग धूमपान करते हैं उनमें अन्य के मुकाबले दिल के दौरे का जोखिम तीन गुना अधिक होता है।

मस्तिष्क का दौरा : एक अनुमान के मुताबिक मस्तिष्क के दौरे से मरने वालों में 11 फीसद मरीज धूमपान करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में दिमागी दौरा पड़ने की आशंका दूसरों के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक रहती है।

फेफड़े का कैंसर : पूरे विश्व में कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे बड़ा आंकड़ा फेफड़े के कैंसर का है। इसमें 80 फीसद मौतें धूमपान की वजह से होती हैं।

डायबिटीज का खतरा कम कर सकती है कॉफी

- स्वीडन के शोधकर्ताओं का दावा- फिल्टर कॉफी से मिलता है लाभ
- जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ अध्ययन

लंदन, आइएएनएस : कॉफी पीने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि फिल्टर कॉफी से डायबिटीज टाइप 2 के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिल्टर काफी से मतलब है कि कॉफी को पानी या दूध में डालकर न उबाला जाए, बल्कि पहले कॉफी को कप में डालकर उसके ऊपर गर्म दूध या पानी डाला जाए।

यह अध्ययन इंटरनल मेडिसिन नामक स्वास्थ्य पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि फिल्टर कॉफी पीने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वीडन की चलमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और उमिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्ष फिल्टर कॉफी के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही ये परिणाम कॉफी के प्रकारों के प्रभावों का आकलन करने में भी मदद करते हैं। उमिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इल अध्ययन के शोधकर्ता रिकॉर्ड लैंडबर्ग ने कहा, 'हमने शरीर में विशिष्ट अणुओं की पहचान की है, जो कॉफी के विभिन्न प्रकारों के सेवन का संकेत देते हैं। हमारे रक्त में ये अणु बायोमार्कर के रूप में मौजूद होते हैं। सामान्यतः इनका उपयोग टाइप 2 मधुमेह यानी डाइबिटीज के जोखिम की गणना के समय विश्लेषण के लिए किया जाता है।' उन्होंने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज के संबंध में हमारे परिणाम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शरीर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और डायबिटीज को विकसित होने से रोक देता है। लैंडबर्ग ने कहा, 'यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि केवल फिल्टर कॉफी ही डायबिटीज टाइप 2 के स्तर को बढ़ने से रोक पाती है, न कि उबली हुई कॉफी।' शोधकर्ताओं ने कहा, 'जो लोग दिन में दो से तीन कप फिल्टर कॉफी का सेवन करते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम अन्य के मुकाबले 60 फीसद तक कम हो जाता है।'

प्रतीकात्मक

अफ्रीका में भी छाया क्रिसमस का खुमार

दक्षिण अफ्रीका के डरबन में उसाका मरीन वर्ल्ड में स्थित देश के सबसे बड़े समुद्री थीम पार्क में एक शो के दौरान सांता क्लाज की पोशाक में रे मछली को भोजन खिलाता गोताखोर। साउथ अफ्रीकन मरीन बायोलॉजिकल रिसर्च वर्ल्ड के थीम पार्क में 200 से अधिक समुद्री जीव-जंतु और मछलियां पाई जाती हैं। क्रिसमस और अन्य छुट्टियों के मौके पर यहां स्थानीय और विदेश के एक लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। इसमें जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण का काम किया जाता है। एएफपी

प्रथम विश्वयुद्ध की पनडुब्बी मिली

मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया सुर राज्य के सांता मार्गरिटा द्वीप के समुद्र में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डूबी पनडुब्बी का पता लगा है। इसकी खोज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री (आइएनएएच) ने की है। अमेरिकी नौसेना इस पनडुब्बी का इस्तेमाल प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अटलांटिक महासागर में पैट्रोलिंग के करती थी। रायटर

स्क्रीन शॉट

असली घटनाओं से प्रेरित है कबीर खान की 'द फॉरगॉटन आर्मी'

'काबुल एक्सप्रेस', 'एक था टाइगर' और 'बजरंगी भाईजान' जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले कबीर खान अब वेब सीरीज 'द फॉरगॉटन आर्मी : आजादी के लिए' लेकर आ रहे हैं। अगले साल 24 जनवरी से अमेजन पर प्रसारित होने वाली इस सीरीज में पांच एपिसोड होंगे। शो में आजाद हिंद फौज के गठन और उसके कार्यकलापों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कहानी को सैनिकों की नजर से दिखाने की कोशिश की गई है। उसमें कई ऐसी जानकारियां भी होगी, जिससे वर्तमान पीढ़ी अनभिज्ञ है। कबीर खान ने अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर के तौर पर की थी। उन्होंने अपने निर्देशन का आगाज इसी नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म (द फॉरगॉटन आर्मी) से किया था, जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज पर आधारित थी। उनके मुताबिक, 'द फॉरगॉटन आर्मी : आजादी के लिए' एक ऐसी कहानी है, जिसने मुझे फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान मैं कई स्वतंत्रता सेनानियों से मिला था। अब उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। उस समय मैं खुद काफी युवा था। उस डॉक्यूमेंट्री ने काफी लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन उसका सीमित वर्ग था। मुझे एहसास हुआ कि सिनेमा बहुत सशक्त माध्यम है। बहरहाल, इस कड़ी में बनाई गई कहानियां वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित हैं, जो दशकों पहले घटित हुई थीं।' शो में सनी कौशल और शार्वरी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद अप्रैल में कबीर खान निर्देशित फिल्म '83 आएगी। रणवीर सिंह अभिनीत वह फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप जीतने पर आधारित है।

फिल्म दबंग 3 के गाने से हटाए गए विवादित सीन

सलमान खान अभिनीत फिल्म 'दबंग 3' के गाने हुड़ हुड़ दबंग... से विवादित सीन हटा लिए गए हैं। फिल्म के इस गाने में साधू-संतों के नाचने का विरोध किया गया था। शुक्रवार को फिल्म रिलीज होने से दो दिन पहले बुधवार की रात फिल्मनिर्माता कंपनी की तरफ से गाने से कुछ दृश्यों को हटाने की जानकारी दी गई। प्रोडक्शन हाउस की ओर से सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में कहा गया कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने स्वेच्छा से हुड़ हुड़ दबंग... से कुछ दृश्य हटा लिए हैं। पिछले महीने में साधू-संतों को बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नचाने को लेकर विरोध जताया गया था। एक संस्था ने सेंसर बोर्ड को 'दबंग 3' को प्रतिबंधित करने के लिए पत्र लिखा था। गाने के विरोध में सोशल मीडिया पर भी 'बॉयकाट दबंग 3' मुहिम चलाई गई थी। 'दबंग' सीरीज की तीसरी फ्रेंचाइजी से फिल्ममेकर महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर अपने अभिनय सफर की शुरुआत कर रही हैं। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा रज्जो की भूमिका में नजर आएंगी।

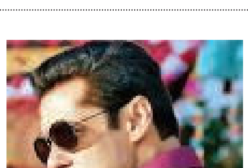

मैं पुरानी फिल्मों वाली बेचारी बहन नहीं बनी हूं : अंजना

हिंदी सिनेमा ऐसी जगह है, जहां हमेशा दिखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन से गायब होते ही दर्शक और इंडस्ट्री दोनों उस सितारे को भूल जाते हैं। अभिनेत्री अंजना सुखानी इस मामले में काफी लकी रही हैं। वर्ष 2017 में फिल्म 'कॉफी विद डी' करने के बाद अंजना निजी कारणों की वजह से सिनेमा से दूर रही हैं। अब वह फिल्म 'गुड न्यूज' से वापसी कर रही हैं। अंजना का मानना है कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें दो साल बाद भी बड़े बैनर से वापसी करने का मौका मिला है। वह कहती हैं कि काम को लेकर जो आक्रामकता मुझमें पहले नहीं थी, वह अब है। 'गुड न्यूज' में अंजना अक्षय कुमार की बहन बनी हैं। वह बताती हैं कि मेरा किरदार पुरानी फिल्मों की तरह बेचारी बहन का नहीं है, जो मदद के लिए अपने भाई का कंधा ढूंढ़ती है। यहां बड़ा भाई अपनी बहन से सलाह ले रहा है। मेरा किरदार एक सशक्त बहन का है, जो वकील है और आइवीएफ को लेकर हुए मसले को सुलझाने में अपने भाई और भाभी की मदद करती है। अपने जीवन की सबसे बड़ी गुड न्यूज का जिक्र करते हुए अंजना बताती हैं कि यह फिल्म मिलना उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। फिल्मों में वापसी के बाद अंजना जल्द ही अपना सिंगल भी ला सकती हैं। उन्होंने बताया कि दो साल का वक्त उन्होंने अपने अभिनय और गायकी को निखारने में भी लगाया है।

'बागी 3' में दिशा का डांस नंबर

'बागी 2' में टाइगर श्रॉफ के साथ लीड भूमिका निभाने के बाद दिशा पटानी 'बागी 3' में भी नजर आने वाली हैं। लेकिन इस बार वह फिल्म में फीमेल लीड नहीं हैं। वह सिर्फ एक डांस नंबर करेंगी। जल्द ही इस डांस की शूटिंग शुरू होगी। एक खबर के अनुसार, दिशा 'बागी 3' में एक स्पेशल गाने में अपना डांस नंबर देंगी। इस डांस नंबर में उनके साथ टाइगर श्रॉफ भी होंगे, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। रिपोर्ट की मानें तो दिशा का यह डांस नंबर फिल्म के अहम दृश्यों में से एक है। इस गाने के बाद ही फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी। पिछले डांस नंबर की तरह यह भी फिल्म के नैरेटिव का हिस्सा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही टाइगर और श्रद्धा कपूर सर्बिया में फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पूरी कर वापस लौटे हैं। दिशा आखिरी बार 'भारत' में सलमान खान के साथ नजर आईं थी। अब उनकी आने वाली फिल्मों में 'मलंग', 'केटीना' और 'राधे' शामिल हैं।

अध्ययन

ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने किया दावा कहा- ऐसा करने से खाली बैठे रहने वालों के मुकाबले 31 फीसद कम हो जाता है मृत्यु का जोखिम

लंबा जीवन चाहिए तो घूमें आर्ट गैलरी और म्यूजियम

लंदन, प्रेट्र : बदलती जीवनशैली का सबसे ज्यादा असर हमारी आयु पर भी पड़ता है क्योंकि इसके कारण हम गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कई बार इतने घातक रोग शरीर को जकड़ लेते हैं कि व्यक्ति की असमय मौत तक हो जाती है। इसलिए हर दिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में लोगों की जीवनशैली काफी अनियमित है, जिसका असर एक उम्र के बाद उनके शरीर में देखने को मिलता है।

जीवनशैली से संबंधित परेशानियों से बचने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया सुझाव दिया है। उनका कहना है कि यदि आप शारीरिक व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते और लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हर दिन किसी म्यूजियम, थियेटर, कंसर्ट और आर्ट गैलरी का एक चक्कर जरूर लगाकर आएं। ऐसा करने से न सिर्फ आप खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे बल्कि गतिहीनों के मुकाबले शारीरिक रूप से भी स्फूर्त रहेंगे। ब्रिटेन में युवाओं पर किए गए अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है।

बीएमजे जर्नल में प्रकाशित हुए इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने लोगों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में सुधार के लिए कलात्मक गतिविधियों के प्रभावों का आकलन किया, साथ ही यह समझने का प्रयास किया कि इससे किसी व्यक्ति को क्या-क्या लाभ मिल सकता है।

प्रतीकात्मक

शोधकर्ताओं ने बताया कि पिछले अध्ययनों में पाया गया है कि कलात्मक गतिविधियों के साथ व्यस्त करने से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है यानी अवसाद, चिंता, डिमेंशिया और अस्थिरता की समस्याएं ठीक हो सकती हैं। इस अध्ययन के लिए ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने कलात्मक गतिविधियों में व्यस्तता और मृत्यु दर की विभिन्न आवृत्तियों के बीच संबंधों का पता लगाया।

कम होगा मृत्यु का जोखिम : इस अध्ययन के परिणाम ब्रिटेन में 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6,000 से अधिक वयस्कों के आंकड़ों पर आधारित हैं, जो इंग्लिश लॉगिट्यूडिनल स्टडी ऑफ एजिंग (ईएलएसए) में भाग ले रहे थे। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग नियमित तौर पर थियेटर, कंसर्ट, ओपेरा, म्यूजियम, ऑर्ट गैलरी और एग्जीबिशन में भाग लेने जाते थे। वे अन्य के मुकाबले लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों में गतिहीनों के मुकाबले मृत्यु का खतरा 31 फीसद कम होता है।

गतिहीनता से रोगी हो जाता है शरीर : शोधकर्ताओं ने कहा कि बैठे रहने से न केवल हमारा समय नष्ट होता है बल्कि हम कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा गतिशील रहना चाहिए। यदि आप शारीरिक गतिविधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते तो थियेटर, कंसर्ट, ओपेरा, म्यूजियम और आर्ट गैलरी के चक्कर लगाने से भी स्वस्थ रह सकते हैं।